लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.81
Parliament Library

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)

Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]

[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)

(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, शुक्रवार, 30 जून, 1967/9 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 29–Friday, June 30, 1967/Asadha 9, 1889 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference ..	3855

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
841 ढांचा निर्माण उद्योग	Structural Fabrication Industry	3856-3859
842 मैसर्स ए. एच. ह्वीलर एण्ड कम्पनी	M/s. A. H. Wheeler and Co	3859-3861
843 अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	3862-3864
844 अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा इस्पात की ट्यूबों का आयात	Import of Steel Tubes by Amin chand Pyare Lal Group	3864-3865
857 गैर-सरकारी सार्थों के साथ इस्पात के सौदों की जांच के लिये 'सरकार आयोग'	'Sarkar Commission' to enquire into Steel deals with Private Firms	3865-3868
845 साइकिल के टायरों और ट्यूबों की कमी	Shortage of Cycle Tyres and Tubes ...	3868-3870
846 उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity in Industry	3870-3872
अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
20 पांचवां इस्पात कारखाना परियोजना	Fifth Steel Plant Project	3872-3875

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERE TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या/S. Q. Nos.

847 डिब्बों में बन्द किये गये खाद्य-पदार्थों और फलों का निर्यात	Export of Tinned Food and Fruit ...	3875-3876

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता. प्र. संख्या/S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
848	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries in the Public Sector	3876
849	कलकत्ता – दिल्ली रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Calcutta-Delhi Railway Line	3877
850	व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों द्वारा भी खाद्य ऋण	Food Loan to India by Member Countries of GATT	3877
851	अमरीका से आयात	Imports from U. S. A.	3877–3878
852	इस्पात बाजार में मंदी	Slump in Steel Market	3878
853	नामपत्र (लेबल) बनाने की मशीनों का आयात	Import of Lable Making Machinery ...	3878–3879
854	उड़ीसा खनन निगम को ऋण	Loans to Orissa Mining Corporation ...	3879–3 ,80
855	चौथी पंचवर्षीय योजना में खनन नीति	Mining Policy during Fourth Plan ...	3880
856	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	3880–3881
858	अव्यवस्थित कपड़ा मिलों सम्बन्धी निगम	Corporation for Sick Textile Mills ...	2881–3882
859	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of H. E. C. Ranch ..	3882
860	बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd. Bangalore ...	3882–3883
861	काजू का निर्यात	Export of Cashew-nuts	3883
862	लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले भारतीय रेलों के अधिकारी	Officers of Indian Railways Attached to Indian High Commission in London ...	3883–3884
863	चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Czechoslovakia ...	3884–3885

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

सा प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
864	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में छपाई की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machine in H. M. T.	3885
865	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में रोलिंग मिल रोल्स का निर्माण	Manufacture of Rolling Mills Rolls in H. E. C., Ranchi	3885–3886
866	नकली रेशम के कपड़ों के निर्यात सम्बन्धी नीति	Export Policy of Art Silk Fabrics ...	3886
867	छोटी (नैरो गेज) रेलवे लाइनों को हटाना	Dismanting of Narrow Gauge Railway Lines	3887
868	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में औजार और कलम–छोड़ हड़ताल	Tool–cum–Pendown Strike in H. E. C. Ranchi	3887–3888
870	कारों की मांग में वृद्धि	Increase in Demand for Cars	3888–3889
अता. प्र. संख्या / U. S. Q.Nos.			
4116	हनुमानगढ़ और हिन्दूमलकोट के बीच बड़ी रेलवे लाइन	B. G. Line between Hanumangarh and Hindumalkot	3889
4117	चुरु और नोहर के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Churu and Nohar ...	3889
4118	त्रिपुरा में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in Tripura ... –	3889–3890
4119	पूर्व रेलवे में फायरमेंनों की पदोवनति	Reversion of Firemen on the Eastern Railway	3890-3891
4120	गोआ में जहाज बनाने के गैर-सरकारी छोटे कारखाने	Small Private Shipyards in Goa	3891
4121	मनीपुर को लोहे की नालीदार चादरों का नियतन	Allotment of C. I. Sheets to Manipur	3891–3892
4122	सरकोणम में स्टेनलैस स्टील का कारखाना	Stainless Steel Project at Sarkonam ...	3892

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

अता. प्र. संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
4123	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	Hindustan Motors Ltd.	3892
4124	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने	Public Sector Steel Project	3892–3893
4125	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की पत्र पत्रिकाएं	Periodicals of Hindustan Steel Ltd. ...	3893–3894
4126	आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import Licences – ..	3894–3895
4127	मशीनों का निर्यात	Export of Machinery	3895
4128	गोआ में खनन कार्यों के लिये लाइसेंस	Licence for Mining in Goa	3895–3896
4129	गोआ में छर्रे बनाने का कारखाना	Pelletisation Plant in Goa ...	3896–3897
4130	गोआ के छोटे खान मालिक	Small Mine Owners of Goa ...	3897–3898
4131	रेलवे विभाग में मशीनीकरण की व्यवस्था	Introduction of Mechanisation on the Railway	3898
4132	पूर्व रेलवे में संगणक लगाना	Introduction of Computers on the Eastern Railway	3898–3899
4133	रेलवे में अनिवार्य सेवा निवृत्ति	Compulsory Retirement on Railways ...	3899
4134	भड़ौच और दहेज के बीच नैरो गेज सैक्शन बन्द किया जाना	Closure of N. G. Section between Broach and Dahej	3899
4135	रेलवे भोजन–यान	Dining Cars	3900
4136	महिला कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Women Employees	3900–3901
4138	बस्तर में खनिजों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Bastar	3901
4139	रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Raipur to Jagdalpur ...	3901

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

4140	इस्पात का मूल्य	Price of Steel	3901-3902
4141	रेलवे भोजन–यान	Dining Cars	3903
4142	बरमों का आयात	Import of Drilling Rigs	3903
4143	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का निर्यात	Export of H. M. T. Watches	3903-3904
4144	तुर्की में भारतीय इस्पात का मूल्य	Prices of Indian Steel in Turkey ...	3904
4145	बटनों का निर्यात	Export of Buttons	3104
4146	दिल्ली से विशाखापत्तनम् को सीधी गाड़ी	Through Train from Delhi to Vishakhapatnam	3904-3905
4147	छोटे उद्योगों के लिये मशीनें और सांचे	Machinery and Dyes for Small Scale Industries	3905
4148	अहमदाबाद और कलोल के बीच मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के चलने का समय	Running Times of Mail/Express Trains between Ahmedabad and Kalol ...	3905-3906
4149	पाटन और भिलाड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Patan and Bhilad Stations	3906
4150	यवतमाल-एलिचपुर नैरो गेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज में बदलना	Conversion of Yeotmal-Ellichpur N. G. Line into B. G.	3906
4151	महाराष्ट्र में हथकरघों से कपड़े का उत्पादन	Production of Handloom Cloth in Maharashtra	3907
4152	रेलवे कुली	Railway Porters	3907
4135	मैसर्स नानक चन्द शादीराम	M/s, Nanak Chand Shadi Ram	3907-3908
4154	पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे में डीजल तेल की खपत	Consumption of Diesel Oil on E. and S. E. Railways	3908
4155	बिस्कुट उद्योग के लिये आयात किये जाने वाले सामान का अंश	Import content of the Biscut Industry ...	3908-3909

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

4156	नये हाती रेलवे यार्ड के समीप सघर्ष (स्यालदह सैक्शन)	Clash near new Hati Railway Yard (Sealdah Section) ...	3909
4157	ट्रकों का निर्यात	Export of Trucks	3909-3910
4158	झांसी और करारी स्टेशनों के बीच जीप–रेलगाड़ी टक्कर	Jeep–Train Collision between Jhansi and Karari Stations	3910
4159	तिस्वा रेलवे स्टेशन पर डाका	Robbery on Tissua Railway Station ...	3910
4160	लोंग काली मिर्च तथा मेवों का आयात	Import of Cloves, Black Pepper and Dry Fruits	3911
4161	निर्यात संवर्द्धन परिषदें	Export Promotion Councils	3911–3912
4162	रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था करना	Manning of Level Crossings ...	3912
4163	मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग	Coal Industry in Madhya Pradesh ...	3912–3913
4164	त्रुटिपूर्ण रेल की पटरियां	Defective Rails	3913
4165	लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences	3913–3914
4166	ओखला और बादली औद्योगिक बस्तियां	Okhla and Badli Industrial Estates ..	3914
4167	गांवों में उद्योगों की स्थापना	Rural Industrialisation	3914–3915
4168	भारतीय बन्दरगाहों से पुनर्निर्यात	Re–exports from Indian ports	3915
4169	गोआ के बन्दरगाहों से निर्यात	Exports from the Port of Goa	3916
4170	आशय-पत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent	3916
4171	औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences	3916

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4172	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य	Prices of Export Commodities	3916–3917
4173	कांगड़ा और मंडी में चाय बागान	Tea Plantations in Kangra and Mandi ...	3917
4174	आयातित मोटर गाड़ियां	Imported Vehicles ...	3917
4175	रेलवे मंत्रालय में मित–व्ययिता	Economy in the Ministry of Railway ...	3918
4176	धोतियों का कपड़ा बनाना	Production Length of Dhoties	3918–3919
4177	प्रबन्ध अभिकरण	Managing Agencies	3919
4178	दक्षिण–पूर्व रेलवे में मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance on S. E. Railway ...	3919
4179	कपड़े का निर्यात	Export of Textiles	3919–3920
4180	हथकरघा कपड़े का निर्यात	Export of Handloom Cloth	3920
4181	उड़ीसा और राजस्थान की कोयले की आवश्य–कता	Coal Requirements of Orissa and Rajasthan	3920–3921
4182	उड़ीसा में औद्योगिक कारखाने	Industrial Units in Orissa	3921
4183	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H. E. C., Ranchi	3921–3922
4184	रांची स्थित हैवी इंजी–नियरिंग कारपोरेशन	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	3922
4185	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H. E. C. Ranchi	3222–3924
4186	साईकिल का निर्यात	Export of Cycles	3924
4187	रेलवे जोनों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Railway Zones	3924–3925
4188	बीकानेर डिवीजन में लालगढ़ अस्पताल	Lalgarh Hospital in Bikaner Division ..	3925

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4189	तेल्लीचेरी मैसूर रेलवे लाइन	Tellicherry Mysore Railway Line ...	3925
4190	केरल में नारियल जटा उद्योग	Coir Industry in Kerala	3926–3927
4191	गाड़ियों का देरी से चलना	Late Running of Trains ...	3927
4192	भटनी जंक्शन पर प्लेट–फार्म	Platforms on Bhatni Junction	3928
4193	तुर्तीपार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म	Platform at Turtipar Raillway Station ...	3928
4194	अरकोणम इंजीनियरिंग वर्कशाप के परिसर में कंक्रीट की वर्कशाप	Workshop at Arkonam Engineering Workshop Premises	3929
4195	अरकोणम इंजीनियरी वर्कशाप	Arkonam Engineering Workshop	3929
4196	नेवेली लिग्नाइट निगम	Neiveli Lignite Corporation	3929–3930
4197	बिड़ला ब्रदर्स को औद्यो–गिक लाइसेंस दिया जाना	Industrial Licences to Birla Brothers ...	3930
4198	वन्य पशुओं का निर्यात	Exports of Wild Animals ..	3930–3931
4199	ईस्ट इन्डिया जूट एन्ड हेसियन एक्सचेंन्ज	East India Jute and Hessian Exchange ...	3931
4200	गैर-सरकारी व्यक्तियों को रेलवे विश्राम अतिथि गृहों का नियतन	Allotment of Railway Rest/Guest Houses to Non-Officials	3931–3932
4201	संयुक्त संयंत्र समिति	Joint Plant Committee	3932
4202	ओलावाक्कोट क्रियासोट कारखाना	Olavakkot Creosote Plant	3932–3933
4203	रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारी	Employees of Rourkela Steel Plant ...	3933
4204	भारत एल्यूमिनियम कम्पनी	Bharat Aluminium Company	3933–3934

4205	निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports ...	3934
4206	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Orissa ..	3935-3937
4207	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in Orissa	3937-3938
4208	उड़ीसा में औद्योगिक कारखाने	Industrial Units in Orissa ...	3938
4209	उड़ीसा के लिये कोयले के डिब्बों का नियतन	Allotment of Coal Wagons to Orissa	3938-3939
4210	उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग का विकास	Development of Handicraft Industry in Orissa	3939
4211	मैसर्स हिन्दुस्तान व्हीकल्स लिमिटेड, पटना	M/s. Hindustan Vehicles Ltd., Patna	3939-3940
4212	मैसर्स डालमिया एण्ड जैन को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences to Messrs. Dalmia & Jain	3940
4213	इटावा से भिन्ड तक रेलवे लाइन	Railway line from Etawa to Bhind	3940
4214	उत्तर रेलवे के सवारी डिब्बों के परिचारक (कोच अटेंडेन्ट)	Coach Attendants of Northern Railway	3940-3941
4215	पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अधिक ली गई राशि को लौटाने के मामले	Cases involving Refund of overcharges by N. E. Railway	3941
4216	पूर्व रेलवे मे रेलवे पासों का दुरुपयोग	Misuse of Railway passes on Eastern Railway	3941-3942
4217	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals, Ltd.	3942
4218	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद	Bharat Heavy Electricals Ltd., Hyderabad ...	3943
4219	चाय का निर्यात	Export of Tea ...	3943-3944

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4220	खुर्दा रोड जंकशन पर महिला यात्री-मार्ग दर्शक	Lady Passenger Guide at Khurda Road Junction	3944
4221	मोटरकारों के साथ दिये जाने वाले औजारों का मूल्य	Price of Tools given with Motor Cars ..	3944
4222	कारों का निर्माण	Production of Cars	3944-3945
4223	बिहार में सीमेंट का वितरण	Distribution of Cement in Bihar	3945-3946
4224	पायदानों पर यात्रा	Travelling on Foot-Boards	3946
4225	37-अप तथा 38-डाउन रेलागड़ियां	37 UP and 38 Dn. Trains	3947
4226	बहादुरगढ़ और नई दिल्ली के बीच 1 डी. एस. बी. गाड़ी	1 DSB Train between Bahadur Garh and New Delhi	3947
4227	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले की सप्लाई	Supply of Coal by N. C. D. C.	3948
4228	बालाघाट तथा जबलपुर जिलों में तांम्बे के खनिज भण्डार	Copper Deposits in Balaghat and Jabalpur Districts	3948
4229	कीटनाशक दवाई छिड़कने की मशीन	Insecticide Spraying Machine ...	3949
4230	बिड़ला सार्य-समूह	Birla Group of Firms ...	3949-3950
4231	बसर तथा मंचेरियल के बीच रैलवे लाइन	Rail Link between Basar and Mancherial ...	3950
4232	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries Units in M. P. ..	3950-3951
4233	रुई का मूल्य	Price of Cotton ...	3951
4234	जयनगर अर खजौली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt Station between Jaynagar and Khajauli Station	3952

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4235	कामरेंडी के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment near Kamaradi	3952
4236	निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर माल डिब्बों का नियतन	Allotment of Wagons at Nizamabad Railway Station	3952–3953
4237	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	3953
4238	दुर्घटनाओं के बाद रेल गाड़ियों के ड्राइवरों को बहाल किया जाना	Reinstatement of Railway Drivers after Accidents	3953–3954
4239	खेलकूद के सामान का आयात	Import of Sports Goods	3954
4240	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को आवंटित इस्पात का कोटा	Steel Quota allotted to Hindustan Motors Ltd.	3954–3955
4241	रेलवे लाइनों के निकट की मिट्टी खोदना	Diggings near Railway Lines ...	3955
4242	मध्य प्रदेश की गोटीटोरिया–मोहपानी कोयला खानें	Gotitoria-Mohapani Coal Mines, M. P. ..	3955–3956
4243	रेलवे की जोनल तथा डिवीजनल सलाहकार परिषदें	Zonal and Divisional Advisory Councils of Railways	3956
4244	हस्तशिल्प तथा हथकरघा माल निर्यात निगम	Handicrafts and Handlooms Exports Corporation ...	3956–3957
4245	कम्पनियों के सन्तुलन-पत्र	Balance Sheets of Companies	3957
4246	ईदगाह, आगरा से चलने वाली गाड़ियां	Trains originating from Idgah, Agra	3957–3958
4247	आउट एजेंसियां	Out Agencies ...	3958
4248	खेल-कूद के सामान का निर्यात	Export of Sports Goods	3958–3959

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4249	रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद	Gem and Jewellery Export Promotion Council	3959–3960
4250	निवारी स्टेशन पर प्लेटफार्म	Platform at Nivari Station	3960
4251	निवारी स्टेशन	Nivari Station ..	3960
4252	आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता	Assam Compensatory Allowance	3960–3961
4253	कानपुर में उपरि पुल	Overbridge at Kanpur	3961–3962
4254	इस्पात के उत्पादन में बहुतायत	Glut in Production of Steel	3962–3963
4255	सरकार द्वारा कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Textile Mills ...	3963
4256	तांबे तथा जस्ते का उत्पादन	Production of Copper and Zinc	3963–3965
4257	गोमांस का निर्यात	Export of Beef ..	3965–3966
4258	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	3966
4259	विदेशी फर्मों को रायल्टी	Royalty to Foreign Firms ...	3966–3967
4260	पन्ना की हीरे की खानें	Panna Diamond Mines ...	3967–3968
4261	भिलाई में नेहरु संस्कृति भवन (नेहरु हाउस आंन कल्चर)	Nehru House on Culture, Bhilai	3968
4262	भारती मिल्स, पांडिचेरी	Bharti Mills, Pandicherry	3968–3969
4263	भारती मिल्स, पांडिचेरो	Bharti Mills, Pandicherry	3969
4264	पहाड़ा स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Pahara Station	3969–3970
4265	गोआ में रेल के माल–डिब्बों की उपलब्धता	Availability of Railway Wagons in Goa	3970
4266	रेलगाड़ियों से रेलवे उपकरणों की चोरी	Theft of Railway Equipment from Train ..	3970–3971

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4267	मैसूर राज्य के धारवार जिले में पैदा होने वाली कपास	Cotton Grown in Dharwar District, Mysore	3971-3972
4268	मैसूर में कपास परिवहन जांच – पड़ताल चौकियां	Cotton Transport Check–Post in Mysore ..	3972
4269	बस्तर में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in Bastar	3972
4270	दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of Milk Powder	3972-3973
4271	औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry of I. D. and C. A.	3973
4273	रेलवे मंत्रालय में हिन्दी कार्य	Hindi Work in Railway Ministry ...	3973-3974
4274	रेलवे में गन्ने की चोरी	Pilferage of Sugarcane on Railways ..	3974
4275	उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में माल बेचने का ठेका	Vending Contract on Lucknow Division of Northern Railway	3974-3975
4276	लखनऊ डिवीजन में भोजन व्यवस्था के बारे में शिकायतें	Complaints against Serving of Meals in Lucknow Division	3975
4277	मुजफ्फरपुर में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशिक्षण स्कूल	N. E. Railway Training School, Muzaffarpur	3975
4279	बांदा में रेलवे लोको वर्कशाप	Railway Loco Workshop, Banda ..	3976
4280	कालोल स्टेशन के निकट माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Kalol Station ...	3976
4281	सन्तालपुर के निकट माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train near Santalpur	3976-3977

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4282	बरौनी और कटिहार के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of M. G. Line between Barauni and Katihar into B. G.	3977
4283	सूडान को मसालों का निर्यात	Export of Spices to Sudan ...	3977
4284	आयात किये गये ट्रैक्टरों का मूल्य	Prices of Imported Tractors ...	3977–3978
4285	हिमाचल प्रदेश को निर्यात की गई लोहे की नालीदार चादर	C. I. Sheets allotted to Himachal Pradesh ...	3978
4286	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्यात	Exports by Hindustan Steel Limited ...	3978–3979
4287	मैसूर में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Mysore ..	3979
4288	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ...	3979
4289	मैसूर में तुमकुर जिले में नये उद्योगों की स्थापना	Establishment of New Industries at Tumkur District in Mysore	3979–3980
4290	पूर्व रेलवे की लोको परिचालक वर्ग की समिति	Loco Running Staff Committee, E. Rly. ...	3980
4291	नकली रेशमी धागे की कीमत	Price of Art Silk Yarn ...	3980–3981
4292	नकली रेशम उद्योग	Art Silk Industry ...	3981–3982
4293	तालों का निर्यात	Export of Locks	3982–3983
4295	औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली	Industrial Licensing ...	3983
4296	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियाँ	Industrial Estates in U. P. ...	3983
4297	बेलाडिला में कच्चे लोहे का कारखाना तथा पैल्लेटाइजेशन प्लांट	Pig Iron Plant and Pelletization Plant at Bailadila	3984

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS – Contd.

4298	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public Sector Projects in Madhya Pradesh..	3984–3985
4299	रेलवे द्वारा ऐल्यूमिना फेरिक का आयात	Import of Alumina Ferric by Railways ...	3985
4300	नइ कारों के बारे में बुकिंग	Booking in respect of New Cars	3985–3986
4301	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant ...	3986
4302	रानीपर स्टेशन पर टक्कर	Collision at Ranipur Station ...	3986-3987
4303	इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering products	3987
4304	भारतीय इस्पात का निर्यात	Export of Indian Steel	3987–3988
4305	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	Empansion of Durgabur Steel plant	3988
4306	कपड़ा मिलों द्वारा रुई का स्टाक जमा करना	Hoarding of cotton stocks by Textile Mills	3988–3989
4307	सवारी कारों का निर्माण	Manufacture of Passenger Cars ...	3989
4308	रेलवे विद्युतीकरण के कलकत्ता डिविजन के कर्मचारी	Employees of Railway Electrification, Calcutta Division ...	3989
4309	देहरादून के निकट फास्फेट के भण्डारों का पाया जाना	Phosphate Deposits near Dehradun	3990
4310	भिलाई तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात कारखाने	Bhilai and other public Sector Steel plants ...	3990–3991
4311	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Cars ...	3991–3992
4312	मध्य प्रदेश में शक्ति–चालित करघे	Powerlooms in Madhya Pradesh	3992
4313	बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण की व्यवस्था	Reservation at Burhanpur Railway Station..	3992
4314	उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Implements	3992

4315 औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates	3992–3993
4316 आमों को बिहार से होकर ले जाना	Transportation of Mangoes throught Bihar	3993
4317 पानीपत वूलन एन्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, खरड़	Panipat Woolen and General Mills Co. Ltd., Kharar	3993–3994
4318 निर्यात व्यापार के लिए विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration for Export Business..	3994
अतारांकित प्रश्न संख्या 2802 के उत्तर में शुद्धि	Correction in answer to unstarred Question. No. 2802 (16.6.67)	3994-3995
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	3995–3998
भारत आ रहे अनाज के एक जहाज को संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा रोक लिये जाने और जुर्माने के तौर पर 27,000 टन अनाज उतारने के आदेश का समाचार	Roported detention of an India bound Ship by U.A. R. and order to unload the 27, 000 tons of foodgrains as fine ..	3995
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh ...	3995
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	3995
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	3998–4000
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill	4000
प्राक्कलन समिति	Estimates committee	4000
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report ...	4000
मंहगाई भत्ता आयोग की रिपोर्ट के बारे में	Re. D. A. Commission's Report	4000–4001
अनुदानों की मांगे	Demands for Grants.	4001–4012
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce	4001–4012
श्री सोमानी	Shri N. K. Somani ...	4001
श्री फ. गो. सेन	Shri P. G. Sen	4003
श्री सेक्वीरा	Shri Segueira ..	4005
श्री रा. की. अमीन	Shri R. K. Amin	4006

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	4006
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Mambers' Bills and Resolutions	4013
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	4013
खाद्यान्नों की वसूली की योजना के बारे में संकल्प–(जारी)	Resolution Re. Scheme for Procurement of Foodgrains (contd.)	4013–4019
श्री भगवान दास	Shri Bhagwaen Das	4013
श्री रंगा	Shri Ranga	4014
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	4015
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes ..	4016
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	4017
तिब्बत के बारे में संकल्प	Resolution Re. Tibet	4019
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel ...	4019
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	4020
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. patodia	4020
श्री जे. के. चौधरी	Shri J. K. Chowdhury	4021
श्री जार्ज फार्नेन्डीज	Shri George Fernandes	4023
श्री गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	4024
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair ...	4025
श्री म. ला. सोंधी	Shri M. L. Sondhi	4026
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	4026

लोक सभा वाद-विवाद का सारांश

अनुदित संस्करण

शुक्रवार 30 जून, 1967 । 9 आषाढ़ , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
3888	प्रश्न संख्या `770 ` के स्थान पर `870 `पढ़िये ।
3940	ऊपर से चौथी पंक्ति में ` Shri Ahmed ' के स्थान पर Shri F.A. Ahmed ' पढ़िये ।
3991	प्रश्न संख्या `3311 ` के स्थान पर `4311 `पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 30 जून, 1967/9 आषाढ़, 1889 (शक)
Friday June 30, 1967/9 *Asadha*, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री गोपी नाथ सिंह के दुखद निधन का समाचार देना है, जिनका देहान्त 29 जून, 1967 को लखनऊ में 75 वर्ष की आयु में हो गया।

श्री गोपी नाथ वर्ष 1950-52 में अन्तरिम संसद के सदस्य थे।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को सवेदना सदेश भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

सभा अपना खेद व्यक्त करने के लिये कुछ समय के लिये खड़ी हो जाये।

इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Structural Fabrication Industry

\+
***841. Shri Rabi Ray :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Joshi :
Shri Madhu Limiye :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to a survey made by the Indian Engineering Association, half of the capacity of structural fabrication industry is not being utilized;

(b) whether Government propose to establish a number of such big factories in the public sector with foreign collaboration; and

(c) the steps being taken in the matter in order to make use of the full capacity of the private sector ?

The Dupty Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh) : (a) In August, 1966, the Indian Engineering Association in their report on the spare capacity in the Structural Fabrication Industry, had stated that no major orders had been placed on this industry during the preceding year and that most of the units in the industry were working to 60% of their capacity. However, according to the Government's assessment, the spare capacity relates primarily to units fabricating light structurals, and the capacity available for manufacture of medium and heavy structurals is relatively better utilised.

(b) Structurals fabrication unit with a capacity of 25,000 tons/annum for heavy structurals is being established at Naini, in U. P., as a joint enterprise of the Government of India and Messrs Voest of Austria. In addition, a Structural Fabrication shop is being set up with a capacity of approximately 30,500 tonnes per year as an integral part of the Bokaro Steel Plant, with Soviet essistance.

(c) All the concerned authorities responsible for the implementation of approved projects in the Public Sector have been advised to place firm orders for their requirements of structurals with the different units in the industry expeditiously. Detailed information relating to their requirements is collected and passed on to the Panel for Structural Fabricating Industry so as to enable the industry to tender for and undertake the necessary preparatory work.

The question of export of structurals has also been examined. The Panel for Structural Fabricating Industry has been advised to approach the Council to sponsor a team under its auspices, to conduct a market survey of foreign markets which have not been studied so far. This is being considered by the Panel.

A Scheme has been evolved by the Joint Plant Committee for re-imbursing the difference between domestic and international prices of steel and pig iron to fabricators of engineering goods for export.

A suggestion for the establishment of an Indian Consortium which could offer package deals abroad, and more particularly offer comprehensive consultancy services and

undertake the supply of structurals and equipment, construct and commission projects in Asia and Africa on a turn key basis, is presently under consideration of the Panel.

Shri Rabi Ray : May I know the names of the persons responsible for non-utilisation of the 40 percent capacity in this industry and whether the persons held responsible for it would be punished ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : As indicated by the Association the units manufacturing heavy, light and medium structurals were working to 60 percent of their capacity. According to our information there is slight recession in the light structural industry and the heavy structural units have not been much affected. Our Public sector industries are underlying the need to start manufacturing of heavy and medium structurals within the country. Much needs to be done. We anticipate sizeable shortage towards the end of the fourth plan and we have undertaken manufacturing of heavy structurals in the Public Sector just to obviate import.

Shri Rabi Ray : Does the hon. Minister propose to chalk out a programme for lift irrigation in the upstream dry lands of the Ganges and the Jamuna by reconditioning the light structurals ?

Shri F. A. Ahmed : Although the light structural units undertake the manufacture of varied items, yet it is such an industry that cannot be modelled on regional basis or unitwise. Since most of the items have to be moved to distant places, regional imbulances are bound to occur. With a view to minimising the effects of recession in the light structural industry we have asked all our public sector undertakings to make a list of their anticipated requirements and pass on the same for placing indent.

Shri S. M. Joshi : May I know whether there is any idle capacity in the heavy structurals ?

Shri F. A. Ahmed : The idle capacity is mainly in the light structurals and in the heavy structurals it is only to a very limited extent. Even so, there is no cause for anxiety as we have already informed of our requirements to the industry for the Bokaro Steel Plant.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : निजी क्षेत्र की पूरी क्षमता को काम में लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैंने बताया यह उद्योग इस प्रकार का है कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि यह अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा। परन्तु यह सच है कि विशेष रूप से रेल माल डिब्बों की मांग कम होने के कारण मंदा रहा है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह अस्थायी मंदा है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को कम करने के लिये हमने विभिन्न कदम उठाये हैं। हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कहा है कि वे अगले कुछ वर्षों की अपनी आवश्यकता का अनुमान लगायें और उसकी सूचना उन लोगों को दे दी जाती

है। हम ढांचों को निर्यात करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिये हम राज सहायता देते हैं।

श्री हेम बरुआ : हमारे इंजीनियरी उद्योग में काफी क्षमता बेकार पड़ी है और दूसरी और बड़ी मात्रा में इंजीनियरी का सामान आयात करते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसकी जांच की जा रही है। इन तीनों प्रकार के एककों द्वारा जो सामान निर्मित किया जाता है उसे आयात नहीं करने दिया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन, क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस उद्योग में मंदा इसलिये नहीं है कि हमने हलके ढांचों के आयात की अनुमति दे रखी है, अपितु, इसलिये कि आर्थिक मंदा है और विभिन्न जगहों से क्रयादेश नहीं आ रहे हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know the value of the orders placed by various Government Departments on the public sector units after the issuing of the circular for estimating requirements and placing orders ?

Shri F. A. Ahmed : A conference was held with all the relevant ministries and thereafter a committee was constituted and it was decided that all the Public Sector Undertakings would notify their requirements to the committee. Then the committee would ask the industries to contact the public undertakings and meet their requirements.

श्री नन्द कुमार सोमानी : भारी ढांचा उद्योग में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए, उनको लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योग में बदलना आसान होगा। ऐसी हालत में सरकार की क्या नीति है क्योंकि इससे निजी क्षेत्र के सैकड़ों एककों को हानि पहुँचेगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने बताया कि सरकार की इच्छा यह है कि कारखानों को पूरी क्षमता पर चलाने के लिये जहा तक संभव हो गैर सरकारी क्षेत्र की सहायता की जाये। इंजीनियरी संस्थान द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में कहा गया है कि छोटे बड़े सब कारखाने समूचे तौर पर अपनी 60 प्रतिशत क्षमता पर काम करते रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य को पता है कि कुछ कारखानों ने पिछले वर्ष उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक माल निर्मित किया जबकि कुछ अन्य कारखानों ने काफी कम माल निर्मित किया। उद्योग ऐसे स्वरुप का है कि इसमें एककवार वर्गीकरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जहां तक बड़े ढांचों का सम्बन्ध है, मेरे सामने जो कठिनाइयां रखी गई हैं वे ये हैं कि उन ढांचों की जितनी मांग है हम उससे कम माल दे रहें हैं और चतुर्थ योजना के अन्त पर सरकारी क्षेत्र में तीन या चार नई परियजोनाओं के चालू होने पर भी इन ढांचों की कमी रहेगी। जहां तक हल्के ढांचों का सम्बन्ध है, यह सच है कि उस प्रयोजन के लिये क्षमता बेकार रही है। यह जानने के लिये कि हम किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं हम निरन्तर रूप से उनके प्रतिनिधियों से मिलते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक प्रश्न में समूची नीति के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे, तो सारा दिन उसी में लग जायेगा। अगला प्रश्न।

M/s. A. H. Wheeler & Co.

+

***842 Shri K. N. Tiwary ;**
Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend again he contract awarded to M/s. A. H. Wheeler & Co; and

(b) if so, the reasons therefor ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) मेसर्स ए० एच० व्हीलर एन्ड कम्पनी के साथ पहले जो करार हुआ था, उसमें यह व्यवस्था थी कि यदि उनका काम संतोषजनक हो, तो उनके ठेके की अवधि स्वतः बढ़ा दी जायेगी। तदनुसार 1.1.67 से उनके ठेके की अवधि बढ़ा दी गई है।

Shri K. N. Tiwary : For what period this has been renewed ?

श्री परिमल घोष : ठेके का 9 वर्ष के लिये, 1.1.1967 से 31.12.1975 तक के लिये नवीकरण किया गया था।

Shri K. N. Tiwary : Why this contract has been renewed when there had been a elamorous demand in this House to terminate the contract and other parties were interested in this contracted ?

श्री परिमल घोष : यह सच है कि 1960 तक व्हीलर एन्ड कम्पनी की दुकानों का एक बड़ी संख्या में जमाव होता रहा। 1960 में मामले का पुनर्विलोकन किया गया और जमाव को तोड़ने के लिये यह फैसला किया गया कि केवल 5 वर्ष के लिये ठेके का नवीकरण किया जायेगा। तत्पश्चात व्हीलर एन्ड कम्पनी ने अभ्यावेदन दे दिया कि नवीकरण का ठेका न होने के कारण कुछ अनिश्चितता रही है। तब मामले का पुनर्विलोकन किया गया था और विधि मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि ठेका पांच वर्ष के लिये दिया जायेगा और यदि कम्पनी चाहे तो अगले वर्षों के लिये उसका नवीकरण करा सकती है। पहले 5 वर्ष समाप्त होने पर जब नवीकरण का प्रश्न आया तो नवीकरण को समाप्त करने का फैसला किया गया था। परन्तु उसके बाद अभ्यावेदन दिया गया और मामला पुनः विधि मंत्रालय को सौंप दिया गया था। विधि मंत्रालय ने फैसला किया कि रेलवे नवीकरण खण्ड का एकपक्षीयक्षम रूप से संशोधन करने के लिये सक्षम नहीं है। अतः रेलवे ने फर्म से बातचीत करना आरम्भ की और यह निर्णय किया गया कि नवीकरण शब्दों को हटा दिया जायेगा और ठेके की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा कर 9 वर्ष कर दी जायेगी। उसके परिणामस्वरूप 1.1.1967 से 31.12.1975 तक 9 वर्षों के लिये ठेके का नवीकरण किया गया है।

श्री अब्राहम : क्या सरकार खुले बाजार से टेन्डर मंगाने के प्रश्न पर विचार करेगी; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : यह स्वामिस्व के भुगतान के आधार पर किया जाता है। अतः टैन्डर का कोई प्रश्न नहीं है। कुल बिक्री पर निर्धारित स्वामित्व के आधार पर मामला तय किया जाता है।

Shri Baswant : It is not proper to give monoply for the whole of India. Why is the Railway Ministry afraid of awarding contracts to the local co-operative societies ?

श्री परिमल घोष : मामले पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है कि निश्चित अवधि की समाप्ति से पूर्व नवीकरण नहीं हो सकता। अतः मामले पर इस समय पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि एक सो गुलाब के ठेके का, जिन्हें विभाजन के बाद ठेका दिया गया था, नवीकरण किया गया है ?

श्री परिमल घोष : जी, हां।

Shri Achal Singh : On what terms this contract given ?

श्री परिमल घोष : निबन्धन और शर्तें ये हैं कि 9 वर्ष तक वे सफल बिक्री पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत का स्वामित्व देंगे।

डा० रानेन सेन : कुछ वर्ष द्वारा भारत सरकार ने एक आदेश द्वारा व्हीलर एन्ड कम्पनी की दुकानों में रूस के सभी प्रकाशनों का बेचा जाना वर्जित कर दिया था। बाद में इस आदेश को रद्द किया गया था। परन्तु अभी तक ये दुकानें रूसी साहित्य नहीं देती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूस के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं, क्या सरकार ने उनको रूसी साहित्य सप्लाई करने के लिये कहना उचित समझा है ?

श्री परिमल घोष : यह मामला हमारी जानकारी में नहीं आया है। यदि यह सच है तो इसकी जांच की जायेगी।

श्री तिरूमल राव : माननीय मंत्री को यह बताते हुए प्रसन्नता हुई थी कि 1960 में नवीनकरण करते समय समझौते में एक खंड यह भी जोड़ दिया गया था कि इसको 1965 से पांच वर्ष आगे तक के लिये बढ़ा दिया गया था। क्या ऐसा संविदा करने से पहले, जिसमें से वे संविदे की शर्तें पूरी न होने पर भी, उससे निकल नहीं सकते, उन्होंने विधि विभाग की सलाह ली थी ?

श्री परिमल घोष : जी हां ऐसा किया गया था।

श्री वि० ना० शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स व्हीलर एण्ड कं० ने अपने स्टाल किसी और पार्टी को किराये पर दे दिये हैं ?

श्री परिमल घोष : कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वे अपने बुक स्टाल अपने एजेन्टों को किराये पर दे रहे हैं। मामला विधि मंत्रालय को सौंप दिया गया है। विधि मंत्रालय की यह राय है कि जब भी कोई व्यक्ति एक एजेन्ट की नियुक्ति करता है तो संविदे के अनुसार इसमें मालिक के अधिकारों का हस्तान्तरण शामिल नहीं होता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब उन्होंने उसे आगे किराये पर दिया तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री परिमल घोष : उन्होंने आगे किराये पर नहीं दी। उन्होंने एक एजेन्ट की नियुक्ति की और एजेन्ट की नियुक्ति का अभिप्राय निश्चित रूप से अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं हो जाता।

श्री हेम बरूग्रा : चूंकि मैसर्स विहिलर एण्ड क० केवल उन्हीं पुस्तकों को स्टाल में लगाने में विशिष्ट है जिन्हें 'शिलिंग शोकर' कहा जाता है और उन पुस्तकों को नहीं जो पढने योग्य हैं। इसके साथ साथ हमें यह विदित है कि उनके विशेष क्षेत्रों में स्थित स्टालों में उसी भाषा या उसी विशेष क्षेत्र की पुस्तकें वहां प्रदर्शित या चुनी नहीं गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि मैसर्स व्हीलर एण्ड कं० ने पुस्तकों के चुनने में कुछ धर्मपरायणता का परिचय नहीं दिया है और प्रान्तीय भाषाओं के पुस्तकों का भी चयन किया है।

श्री परिमल घोष : जहां तक हमारी जानकारी है वे सब प्रकार की पुस्तकें बेच रहे हैं जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें भी शामिल हैं।

श्री हेम बरूग्रा : वे नहीं हैं।

श्री परिमल घोष : यदि माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक है तो हम इस सम्बन्ध में जांच करेंगे।

श्री हेम बरूग्रा : जब भी मैं कभी रेलवे स्टेशन पर जाता हूं तो मैं व्हीलर एण्ड कं० के स्टाल की पुस्तकों का अवश्य ही निरीक्षण करता हूं। मेरे विचार से उनका प्रदर्शन केवल कुछ ही प्रकार की पुस्तकों तक सीमित है जिसमें मुख्यतः कामुक साहित्य होता है।

श्री शशि रंजन : अभी माननीय सदस्य डा० सेन ने बताया था कि पहले रूसी साहित्य को अस्वीकार कर दिया गया था और अब उसे स्वीकार कर लिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत के साम्यवादी दल ने रेलवे स्टालों पर अपना ही साहित्य भेजा है और क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है ?

अखबारी कागज का आयात

+

*843. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी अखबारी कागज के आयात पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(ख) भारत में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1963–64 से 1966–67 (फरवरी 1967 तक) के दौरान कुल 693.41, 739.80, 618.11 और 976.70 लाख रुपये का विदेशी अखबारी कागज का आयात किया गया।

(ख) देश में एक मात्र स्थित अखबारी कागज मिल की उत्पादन क्षमता 30,000 टन से 75,000 टन प्रतिवर्ष की जा रही है और राजकीय क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने की सम्भावना का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गैर–सरकारी क्षेत्र में रुपया लगाने को प्रोत्साहन देने के लिये अखबारी कागज उद्योग को उद्योगों के लिये आवश्यक लाइसेंस उपबन्धों विकास विनियमन अधिनियम, 1951 से मुक्त कर दिया गया है, और इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी पार्टी लाइसेंस बिना अखबारी कागज का प्लान्ट स्थापित कर सकती है।

Shri George Fernandes : The production of the new print plant which is in the public sector comes to near about 30,000 tonnes per year. It has been said for near about seven years that efforts are being made to increase its production to the extent of 75,000 tonnes. It has also been said that there would have been the production of 75,000 tonnes of newsprint in the Nepha Mills by July this year. I want to know whether the promise of the Government to produce 75,000 tonnes of newsprint per year at the Nepha Mills would be fulfilled by the next month.

Shri Dinesh Singh : Yes please. Our promise is resulting into actual practical. The work of constructing the building would begin there in August this year. After that the machinery has to be installed there. We are of the view that some production would also be started by May, 1968. We hope that the production of newsprint would start there by the middleof 1969,

Shri George Fernandes : It means that the promise of the Goveroment to produce 75,000 tonnes of newsprint by July this year is out of question and the Government has become a total failure in that regard.

Government promised that during the Third Five Year Plan the production of the newsprint would be raised from 30,000 tonnes to 1,50,000 tonnes, but it is still 30,000 toones. it has been said that they are prepared to help the persons working in private sector. But the hon. Minister knows that out of the licences given to the persons in private

sector, none has utilised these licences. It is, therefore, clear that this work of newsprint is not possible in private sector.

Government spent foreign currency amounting to rupees ten crores every year on newsprint. Will it not try to save this foreign currency immediately by bringing the production of newsprint completely under public sector.

Shri Dinesh Singh : I have replied it is the very beginning.

Shri Kanwar Lal Gupta : There are embassies of several countries here. They import newsprint for periodicals from foreign and because they import more then their requirements, the remaining newsprint is being sold in black in the open market, I want to know whether the Government is aware of the quantities of the newsprints these embassies import for their own use during an year ? whether the Government have the control regarding its use, the quantity sold in black market and what happened to that money etc ?

Shri Dinesh Singh : We have no information that the newsprint has been sold in black by the embassies. If the hon. member will give some information in this regard. whether inside the House or outside the House, an investigation in this matter would be made.

श्री दामानी : नेपा की क्षमता में विलम्ब से बढ़ने का क्या कारण है ? क्या उत्पादन को बढ़ाने के लिये अपेक्षित कच्चे माल को प्राप्त करने में कोई कठिनाई है ?

श्री दिनेश सिंह : हमें आशा है कि अब कोई कठिनाई नहीं होगी । हम इसका विस्तार किस प्रकार कर रहे हैं मैंने उसका कार्यक्रम बताया है । पहले भी इस मामले पर हम ध्यान पूर्वक विचार कर चुके हैं । जैसा कि आपको विदित ही है कि हम अखबारी कागज का निर्माण करने के इच्छुक हैं, परन्तु पूरा कच्चा माल प्राप्त करने में हम सफल नहीं हुए हैं । इसकी सार्थकता के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन पूरे हो गये हैं । सभा को कागज निगम की स्थापना किये जाने के हमारे इरादे की जानकारी ही है वह अखबारी कागज का भी निर्माण करेगा ।

Shri Kameshwar Singh : Whether the hon. Minister would be pleased to state the time when import of newsprint would be stopped ?

Shri Dinesh Singh : It is not possible for me to give the specific date.

Shri Sita Ram Kesri : Whether the hon. Minister woul d be pleased to state the quantity of the newsprint we require at present, the quantity we import from outside, the quantity we produce here in the country and the quantity we are going to increase in our production ?

Shri Dinesh Singh : At present our requirement is 1,70 thousand tonnes. We are producing 30 thousand tonnes here and as I have already told that we are increasing it to 75 thousand tonnes. The remaining 100 thousand tonnes we import from outside and the need of 25 thousand is met by the white and other papers.

Shri Sarjoo Pandey : whether the hon. Minister is aware that several presses took more imported quota and sell it in black at high prices to small presses, If it is so, whether the Government have adopted some method to prevent it.

Shri Dinesh Singh : If the hon. member gives me some information in this regard, neassary investigation well be made in this regard.

श्री तन्नेटि विश्वनाथम : अखबारी कागज की इतनी अधिक कमी को देखते हुए क्या सरकार आन्ध्रप्रदेश के निजामाबाद जिले में बोधन स्थान पर राजकीय क्षेत्र में घ.स को कच्चे माल की तरह प्रयोग कर कोई कारखाना आरम्भ करने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में जो अध्ययन किया गया है वह आंध्र राज्य से सम्बन्धित नहीं है । चूंकि अब माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है तो मुझे आशा है कि निगम इस मामले की जांच करेगा इस ओर भी ध्यान देगा ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ देशों से द्विपक्षी अनुबन्ध करने का है जिनसे अखबारी कागज आयात किया जाता है ताकि विदेशी मुद्रा की बजत की जा सके ।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक मुझे स्मरण है अखबारी कागज के लिये विनिमय की व्यवस्था की गई है । परन्तु इस समय में उसका ब्यौरा नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 844 और 857 को इकट्ठा ले लिया जाये ।

अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा इस्पात की ट्यूबों का आयात

*844. **श्री स० मो० बनर्जी** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री मधु लिमये : **श्री जर्ज फरनेन्डीज** :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमींचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा लाइसेंस के बिना अथवा वैध लाइसेंस के बिना इस्पात की ट्यूबों के आयात के बारे में विधि मंत्रालय की राय के सम्बन्ध में 25 मार्च, 1967 के "पेट्रिऑट" समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का यह मत है कि माल आ जाने और सीमा-शुल्क विभाग द्वारा माल जब्त कर लिये जाने के बाद लाइसेंसों में परिवर्तन करना नैतिक/कानूनी रूप से उचित है;

(ग) यदि हां, तो क्या संशोधन करने को समूची प्रक्रिया में संशोधन करने के विचार से इस पर पुन विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) से (घ) "पेट्रिऑफ" में प्रकाशित 25 मार्च के समाचार में कुछ चादरों के आयात किये जाने का उल्लेख किया गया

है । इन तथ्यों का तारांकित प्रश्न संख्या 214 का लोक सभा में 10 नवम्बर को उत्तर देते समय उल्लेख किया गया था । तथ्य इस प्रकार है ।

मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल द्वारा आयात की गई वाणिज्यिक किस्म की उस आकार की काली सादी चादरें के तीन मद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, 1963 में देखे गये थे, जिनका लाइसेंस में जिक्र नहीं किया गया था । इन तीनों मामलों में मूल सीमा–शुल्क निवारण अनुमति पत्र दिये गये थे और उसके तुरन्त बाद ही इस्पात और लोहा नियंत्रक ने आयात की गई चादरों के आकार को उसमें शामिल करने के लिये संशोधन किये थे, परन्तु सम्बन्धित सीमा–शुल्क कलक्टरों ने यह निर्णय दिया था कि सीमा–शुल्क निवारण अनुमति पत्र गैर कानूनी था अतः समान को जब तक के लिये जब्त कर लिया जाये जब तक कि जुर्माना न अदा किया जाये और दो मामलों में अर्थ दण्ड दिया गया । अपील करने पर केन्द्रीय उत्पादन और सीमा–शुल्क बोर्ड ने इस्पात और लोहा नियंत्रक बोर्ड द्वारा दिये गये संशोधित अनुमति पत्रों को स्वीकार कर लिया, अर्थ दण्ड को क्षमा कर दिया गया और जब्त करने के आदेश वापिस ले लिये गये ।

हम इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले का निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या सीमा शुल्क निवारण अनुमति पत्रों सम्बन्धी प्रक्रिया में संशोधन किया जाना आवश्यक है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हम 30 जून, 1967 को प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्होंने वही उत्तर पढ़ दिया है जो उन्होंने तारांकित प्रश्न संख्या 214 का 15 नवम्बर, 1966 को पढ़ा था । मैं इससे उसे मिला सकता हूं । वह मेरे पास है । हम कुछ और जानकारी चाहते हैं ।

गैर-सरकारी सार्था के साथ इस्पात के सौदों की जांच के लिए सरकार आयोग

+
***857. श्री कामेश्वर सिंह : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार गैर सरकारी सार्था के साथ इस्पात के सौदों की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये सरकार आयोग ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि समिति को सम्बन्धित फाइलें नहीं दी जा रही है और बहुत सी महत्वपूर्ण फाइलें गायब है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा चन्ना रेड्डी) : (क) समिति का गठन 12 सितम्बर, 1966 को हुआ था और उसी तारीख से इसने कार्य आरम्भ कर दिया था ।

(ख) विभिन्न कार्यालय जैसे लोहा और इस्पात मंत्रालय लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड समय समय पर सम्बन्धित फाइलें समिति को देते रहते हैं ।

कुछ देरी अवश्य हुई है क्योंकि फाइलें कई वर्ष पहले की है । अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है कि समिति ने कोई फाइलें मांगी हो और उसके बारे में यह कहा गया हो कि फाइल नहीं मिल रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : तारांकित प्रश्न संख्या 214 तारीख 10 नवम्बर, 1966 और उसके पढ़ें गये उत्तर को देखने से मुझे पता लगा कि यह विशेष प्रश्न मेरे मित्र श्री मधु लिमये ने पूछा था । उन्होंने पूछा था कि क्या एस. पी. ई. ने इस उल्लंघन की जांच की थी । उत्तर था 'जी नहीं' । मैं यह जानना चाहूँगा कि शेडी व्यापार के सम्बन्ध विधि मंत्रालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि माननीय मंत्री इस मामले की आगे जांच के लिए इसे एस. पी. ई. को सौंपे क्योंकि इसमें केन्द्रीय मंत्री शामिल हैं ।

डा० चन्ना रेड्डी : जैसा कि सदन को विदित ही है कि इस मामले की जांच सरकार जांच समिति द्वारा की जा रही है अत: इस सम्बन्ध में और कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है । वास्तव में मेरी श्री मधु लिमये और अन्य माननीय सदस्यों से अनौपचारिक बार्ता हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार जांच समिति एस. पी. ई. को सौंपे गये सब मामलों का पता लगायेगी और शायद यह भी उन्हीं मामलों में से एक है जिन्हें हमें सरकार जांच समिति के विवेक पर छोड़ना चाहते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जांच समिति नियमों के अनुसार यदि भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री या वर्तमान केन्द्रीय मंत्री इसमें शामिल हों तो उनके साक्ष्य ले सकती है और क्या समिति को माननीय मंत्री से जिरह करने का अधिकार है । दूसरे क्या जब तक इस कम्पनी को कोटा नहीं दिया जायेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : जहां तक समिति के क्षेत्राधिकार और केन्द्रीय मंत्री के साक्ष्य देने का सम्बन्ध है, तो मेरे विचार से यदि वह इसे आवश्यक समझेगी तो इसमें कोई बाधा सामने नहीं आयेगी ।

जहां तक परमिट को देने का प्रश्न है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय को सौंपा गया है और निर्णय को कुछ काल के लिए स्थगन के आदेश जारी किये गये हैं ।

Shri George Fernandes : Under what rules the Collector of Customs has declared the issuing of custom clearance permit as illegal ? At the time of appeal some Ministers must have interfered and under what rules the Board have changed its previous decision ?

Dr. Chenna Reddy : There is no question of interference by any Minister. The Custom Collector thought that it would not be appropriate or correct to make amendment in the permit issued before, but when an appeal was made to the Revenue Board, it asked the advise of the Ministry of Law and the Min. of law gave the advise that the licence issuing authority has goot the right to amend it as well. Thus this has been done by the Revenue Board with the consultation of Law Ministry.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : प्राय: यह देखा जाता है कि मामले की जांच के दौरान फाइलें गुम हो जाती हैं या उनमें लिखित सामग्री की चोरी-छिपे बाहर ले आया जाता है । इस

सम्बन्ध में सरकार क्या सुरक्षात्मक उपाय कर रही है तथा ऐसी फाइलों से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस मामले से सम्बन्धित कोई भी फाइल गुम नहीं हुई है।

श्री रा० बरुआ : क्या लोहा तथा इस्पात नियंत्रक संशोधन जारी करके एक अवैध बात को वैध बना सकता है ? क्या यह बात तत्कालीन मंत्री को बताई गई थी ?

डा० चन्ना रेड्डी : जिस अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह लाइसेंस जारी कर सके, उसे यह अधिकार भी होता है कि वह उसमें संशोधन कर सके। इस प्रकार स्वयं संशोधन ही वैध हो जाता है। मंत्री महोदय के सामने इस प्रश्न का लाये जाने की आवश्यकता ही नहीं होती।

श्री सम्बन्धन : परमिट जारी करने वाला अधिकारी परमिट मे संशोधन माल के आयात से पहले कर सकता है। सीमा अधिकारियों द्वारा माल पकड़े जाने के बाद परमिट में संशोधन करने का उसे कोई अधिकार नहीं होता। फिर सम्बन्धित अधिकारी ने किस कानून के अधीन आयातित माल को वैध बनाने के उद्देश्य से परमिट में संशोधन किया है तथा विधि मंत्रालय ने किस आधार पर इस बात का समर्थन किया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : पहले तो बोर्ड द्वारा की गई व्याख्या का विधि मंत्रालय ने समर्थन किया और फिर यह भी देखना पड़ता है कि जो संशोधन किया गया है वह सदाशय से किया गया है या कदाशय से। यह बताया गया है कि लौहा तथा इस्पात नियंत्रक इस बात से संतुष्ट था कि इस मामले में संशोधन सदाशय से किया गया था और इस आधार पर राजस्व अधिकारी ने इसे शुरु से ही संशोधित मान लिया।

श्री सम्बन्धन : यदि माल लाइसेंस में नहीं होता, तो प्रायः जप्त कर लिया जाता है।

Shri D. N. Tiwary : Why is the Minister not prepared to take such steps against the M/s. Aminchand Pyarelal firm so that they cannot make a mess of the affairs and the House may also be satisfied with the actions taken.

Dr. Chenna Reddy : The matter has been referred to the Enquiry Committee and the enquiry is going on expeditiously.

Shri Kameshwar Singh : May I know whether the files or the documents required by the Enquiry Committee, have been made available to it or some related papers have been found missing ?

Dr. Chenna Reddy : The files being required by the Enquiry Committee are being supplied to it. No papers are found to be missing.

Shri Kameshwar Singh : Some files dealing with the heavy losses have been removed. Is it a fact ?

Dr. Chenna Reddy : Such matters have not come into the notice of the Ministry. If you have some knowledge of it, please send it to me. I will consider it.

श्री हेम बरुआ : अमींचन्द प्यारेलाल फर्म को काली सूची में रखने की सभा में कई बार मांग की जा चुकी है क्योंकि उसके व्यापार में बहुत गड़बड़ी पाई गई है। क्या सरकार ने उसके प्रति अपना रुख उदार बना लिया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : सरकार का रुख इस फर्म के प्रति उदार नहीं है। परन्तु जहां तक उसे काली सूची में रखने की बात है या उसके साथ व्यापार बन्द करने का प्रश्न है, उस फर्म ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से रोक आदेश ले लिया है।

साइकिल के टायरों और ट्यूबों की कमी

\+

***845. श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि साइकिलों के लोकप्रिय किस्म के टायरों और ट्यूबों की दिल्ली के बाजार में बहुत कमी है जबकि ये चोर बाजारी से बड़ी संख्या में मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में इन समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। साइकिलों के लोकप्रिय किस्म के टायरों और ट्यूबों की कमी के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) इस कमी का कारण यह है कि उपभोक्ता मैसर्स डनलप इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित गुडइयर, इंडिया सुपर तथा डनलप टायर और ट्यूबों को प्राथमिकता देते हैं। सरकार ने ऐसे अनेक कार्य किये हैं जिससे ऐसे टायर-ट्यूब वास्तविक उपभोक्ताओं को अधिकृत व्यापारियों तथा उपभोक्ता सहकारी भंडारों से कम्पनी द्वारा निर्धारित फुटकर भावों पर मिल सके। इस सम्बन्ध में जो कार्य किये गये हैं उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है जो सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी 855/67]**

Shri R. S. Vidyarthi : Since when the cycle tyres and tubes have been brought under the purview of the Essential Commodities Act and how many cases of this type have been registered ?

Shri F. A. Ahmed : There is no shortage of tyres and tubes on an average. But people prefer to purchase the tyres and tubes manufactured by M/s. Dunlop India Ltd., which produces only about 50 percent and this quantum is not sufficient for all. From this point of view there is a shortage. Now ten percent of the production is given to the cooperative societies for making them available to genuine consumers. Moreover Delhi Administration have decided to make tyres and tubes available on the basis of cycle and cycle-riksha licences.

Shri. R. S. Vidyarthi : May I know whether it is a fact that the tyres and tubes supplied by the manufactures to Delhi wholesale dealers or cooperative societies, are being

sent to U. P. or Madhya Pradesh; if so, the steps taken by the Government in the matter.

Shri F. A. Ahmed : It is wrong presumption. Such a complaint was received by the Government in 1966 and a meeting of cycle dealers was called, in which it was made clear that all the tyres and tubes supplied to them should be made available to Delhi people.

श्री मनुभाई पटेल : मुझे स्वयं को मोटर साइकिल की ट्यूब नहीं मिल रही है। मैं दुकान-दुकान घूमा परन्तु मुझे ट्यूब न मिली। क्या आप इस सम्बन्ध में भी गौर करेंगे कि मुझ जसे जरूरतमन्द लोगों को मोटर साइकिल ट्यूब मिल जाये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्रश्न का सम्बन्ध साइकिल टायर ट्यूबों से है और मोटर साइकिल की ट्यूबों से है।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is no shortage of tyres and tubes but they are available in the black market and the price in the black market is three times more than the fixed price. The reason for it is that cycle dealers give 4 tyres to consumers and the receipts for 15 tyres are made in the bogus names. These 15 tyres go into black market. Will you be kind enough to order an enquiry into it ?

Shri F. A. Ahmed : Some days back I held the discussions in this respect with Delhi Administration and they told me that there have been no complaints of this type since 1966. If there is any specific case, give me the details and the enquiry will be ordered into.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विभिन्न राज्यों को कितने-कितने टायर ट्यूब दिये जाते हैं। क्या सरकार को इस बारे में विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट मिलती है ? क्या सरकार को पता है कि उन राज्यों में टायर ट्यूब अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे पास इससे सम्बन्धित आंकड़े नहीं हैं। राज्यों को उनकी आवश्यकता तथा टायर-ट्यूबों की उपलब्धता के आधार पर टायर ट्यूबों का कोटा दिया जाता है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : वस्तुतः कठिनाई यह है कि उत्तर अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं, जो वास्तविकता से दूर होते हैं। चोर-बाजारी में जितने चाहे टायर ट्यूब मिल सकते है परन्तु निर्धारित मूल्य पर नहीं। क्या सरकार जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन इन्हे आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है और इनके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह प्रश्न दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में है। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी बाद में सभा पटल पर रखी जा सकती है।

Shri Ram Charan : The riksha-pullers in U.P. are experiencing the acute shortage of tyres and tubes and they have to purchase them at exorbitant prices of Rs. 30/- each. Will the Government see into it ?

Shri F. A. Ahmed : In respect of U. P. I have got no information. I will seek the required information from the State and place it on the Table.

Shri A. G. Sahgal : Is it a fact that the production of the tyres and tubes is less than the demand for them in the market ? Will the Government now try to increase 10 percent of the production for commercial supplies ?

Shri F. A. Ahmed : It is wrong to say that the production is less than the demand. In 1961, 110 lakhs tyres were produced and now their number is 190 lakhs. In 1965-66 four lakhs 46 thousand tyres were exported. The difficulty is this that people want a particular brand of tyres. We will consider the suggestion for increase in 10 percent.

उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता

+

***846. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री देवकीनन्दन पाटौदिया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संस्था ने हाल में उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां। व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने 1965 में भारत में उद्योगों की अप्रयुत्त क्षमता के बारे में सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण का प्रतिवेदन अक्तूबर 1966 में प्रकाशित हुआ था।

(ख) परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि औद्योगिक क्षमता का पूर्ण प्रयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। परिषद के अनुसार इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. कच्चे माल का अभाव ।

2. पुर्जों का अभाव ।

3. मशीनों का अभाव ।

4. श्रमिक सम्बन्धी झगड़े ।

मूल जानकारी कुछ फर्मों से अन्य तरीकों के साथ-साथ प्रश्नावली जारी करके एकत्र की गई थी। कुल 129 फर्मों ने उत्तर भेजा जिनमें से 103 ने कच्चे माल के अभाव, 53 ने पुर्जों

के अभाव, 50 ने मशीनों के अभाव, 87 ने विदेशी मुद्रा के अभाव के बारे में तथा 49 ने श्रमिकों सम्बन्धी झगड़ों के बारे में शिकायत की। पुर्जों और मशीनों के अभाव का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा का अभाव है।

(ग) सर्वेक्षण की भी अपनी सीमाएं थी। जैसा कि व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने स्वीकार किया है कि प्रश्नावली के बहुत ही कम उत्तर प्राप्त हुए हैं। 17 उद्योग-समूह जिसके अधीन 276 उद्योग आ जाते है, के 4,728 निर्माता एककों में से केवल 129 ने प्रश्नावली के उत्तर भेजे हैं। यद्यपि व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के निष्कर्षों को इसने बहुत हद तक प्रभावित किया है। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत में उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता अत्यधिक है। सरकार समय-समय पर ऐसे कदम उठाती रही है जिनसे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी तथा अनेक उद्योग अपनी वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग करेंगे। उनमें से कुछ निम्नलिखित है :

(1) आयात लाइसेंसों का उदारतापूर्वक दिया जाना, जिससे मुख्यतः प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा;

(2) कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण का उठाया जाना; और

(3) वर्तमान क्षमता के प्रयोग में विविधता लाने के लिये सीमा में रहते हुये उदारतापूर्वक अनुमति देना जिससे एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु बनाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर काफी बड़ा है। अतः आप इसे पटल पर रख सकते थे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि कुछ सरकारी उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक मशीनें मंगा ली गई है और जिनका उपयोग वे दो या तीन साल से पहले न कर सकेंगे? यदि हां, तो इस अप्रयुक्त क्षमता का सदुपयोग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसके लिये प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को अधिक आयात करने की अनुमति दी जा रही है तथा पुर्जे खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा दी जा रही है। कुछ उद्योगों से नियंत्रण उठाने का प्रश्न भी विचाराधीन है जिससे बाजार व्यवस्था ठीक हो जाये और उद्योग आगे पनप सके।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या सरकार को पता है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये गये लाइसेंस चोर-बाजारी में दुगने और तिगुने दामों पर बेचे जा रहे हैं। सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह स्थिति उस समय थी जबकि आयात लाइसेंसों पर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। जब से इन आयात लाइसेंसों को उदार बनाया गया है तब से अभाव

या चोर बाजारी के बारे में शिकायत नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य को किसी मामले का पता है तो उसका वे पूरा ब्यौरा दें जिसके बारे में छानबीन की जायेगी।

श्री अ० कु० गोपालन : क्या यह सच है कि कुछ उद्योग पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उन्हें लाइसेंस दिये गये हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि कुछ उद्योगों में क्षमता का उतना उपयोग नहीं किया जा रहा है जितना कि दूसरे उद्योगों में। परन्तु ये लाइसेंस उस समय दिये गये थे जिस समय यह अनुमान लगाना कठिन था कि आर्थिक मन्दी के कारण अप्रयुक्त क्षमता बढ़ेगी।

श्री हेम बरुआ : क्या आप उन लाइसेंसों को वापिस लेने को तैयार हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उद्योग स्थापित हो जाने के बाद उनसे लाइसेंस वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब भी उद्योग की उपयुक्त क्षमता बढ़ती है, उसे यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपने उत्पादन में विविधता लायें। वे ऐसा कर भी रहे हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है रांक फांसफेट के अभाव की वजह से सुपर-फास्फेट बनाने वाले कारखाने अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे है। क्या सरकार गैर सरकारी क्षेत्र में किसी को इसे मगाने का परमिट देने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कच्चे माल के अभाव को पूरा करने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

श्री रंगा : मंत्री महोदय से जो बातें पूछी गई है उनका उत्तर नहीं दिया है, बल्कि एक सामान्य उत्तर दे दिया है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहा तक इस प्रश्न विशेष का सम्बन्ध, यह सम्बन्धित मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये। कच्चे माल के अभाव को ध्यान में रखते हुए उर्वरक कारखानों को प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा दी जा रही है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

पांचवां इस्पात कारखाना परियोजना

+

अ.सू.प्र. *20. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री आ० ना० मुल्ला :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीति राज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवां इस्पात कारखाना परियोजना को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर में बताया गया है कि पांचवां इस्पात कारखाने को ताक पर नहीं रखा जायेगा। आन्ध्र प्रदेश के दावे को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की नीति यह है कि यह कारखाना आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किया जाये ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह मामला विचाराधीन है और यह चौथे इस्पात कारखाने के पूरा होने तथा देश की सामान्य अर्थव्यवस्था पर आधारित है

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने पांचवे इस्पात कारखाने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है। क्या यह स्थापित किया जायेगा या नहीं ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस बारे में निश्चित रुप से अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन पहले ही तैयार करा लिया है अथवा नया प्रतिवेदन तैयार करायेगी, जिसके आधार पर यह निर्णय किया जा सके कि पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करना है अथवा नहीं ? क्या उसके अनुरुप सरकार चौथी योजना में भी परिर्वतन करेगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : चौथी योजना में परिवर्तन का सम्बन्ध हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। आजकल हमें मन्दी का सामना करना पड़ रहा है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी पूरा व्यौरा तैयार कर लिया गया, जिन पर सरकार यथा समय ध्यान देगी।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : May I know the names of the places which are being considered for the fifth steel plant ?

Dr. Chenna Reddy : Different places inclulding those suggested by Anglo-American consortituim, will be considered at the proper time.

श्री सेझियान : वर्ष 1962 में तत्कालीन इस्पात मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ने यह आश्वासन दिया था वि पांचवां इस्पात कारखाना सलेम में शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। क्या सलेम इस्पात कारखाना चौथी योजना में सम्मिलित किया जायेगा ? क्या मद्रास सरकार ने भी इसके बारे में कोई प्रार्थना पत्र भेजा था, यदि हां तो उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : वह सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है तथा चौथी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इसे ठोस रूप दिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच है कि वित्त की कमी के कारण सरकार ने विद्यमान इस्पात कारखानों के विस्तार का कार्यक्रम छोड़ दिया है ? इस बात को ध्यान में रखते

हुए क्या यह सम्भव है कि पांचवां इस्पात कारखाना चौथी योजना काल में ही शुरू कर दिया जायेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : अभी इस बारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि चौथी योजना का स्वरूप और आकार सामान्य अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निश्चित किये जायेंगे ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : क्या यह सच है कि 1965 में मंत्री मंडल ने एक तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय किया था कि विशाखापतनम में पांचवां इस्पात कारखाना लगाया जायेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार का ध्यान मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार पांचवां इस्पात कारखाना मद्रास के सलेम में स्थापित करने के लिये सहमत नहीं होगी तो मद्रास में उसके विरोध में आन्दोलन शुरू हो जायेगा ? यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : समाचार पत्रों में छपी खबर के आंतरिक इसकी कोई औपचारिक जानकारी हमें नहीं है । अतः प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवे इस्पात कारखाने को विभिन्न राज्यों द्वारा दिये जाने के कारण ताक पर रखा है अथवा आर्थिक स्थिति के कारण ?

डा० चन्ना रेड्डी : देश की सामान्य स्थिति के कारण इतने बड़े इस्पात कारखाने को इस समय स्थापित करना सम्भव नहीं है ।

श्री रंगा : क्या सरकार को यह डर है कि यदि बोकारों इस्पात कारखाने का काम जारी न रखा गया तो रूसी प्रधान मंत्री भूख हड़ताल कर देगा और यदि विशाखापतनम में पांचवां इस्पात कारखाना न लगाया गया तो आन्ध्र प्रदेश का मुख्य मन्त्री सत्याग्रह कर देगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में दोनों देशों में समझौता सम्पन्न हो चुका है और प्रत्येक मामला अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है । अन्त भूख-हड़ताल या सत्याग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पें वेंकटासुब्बया : क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि तीन मुख्य स्थानों-विशाखापतनम, होस्पेट और सलेम-में छोटे कारखाने स्थापित किये जायेंगे जो बाद में बड़े कारखानों में परिणत हो जायेंगे ?

डा० चन्ना रेड्डी : फिलहाल कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी मांग और लक्ष्यों की स्थिति का पूर्ण अध्ययय किया जा रहा है ।

श्री अम्बाजागन : यदि कोई अन्य देश पांचवें इस्पात कारखाने में लगने वाली कुल विदेशी मुद्रा का खर्च वहन करने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या सरकार इस परियोजना पर पुनर्विचार करेगी और इसे स्वीकृति देगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : विदेशी सहयोग मात्र से ही हमारे सभी आर्थिक वायदे और आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं। इस समय हमारे देश की निर्माण क्षमता 69 प्रतिशत हैं। इससे आगे जो भी किया जायेगा वह हमारी निर्माण क्षमता से परे होगी।

श्री स० कुन्दू : पांचवें इस्पात कारखाने के लिए बनी समिति ने अपना प्रतिवेदन पारादीप बन्दरगाह बनने से पहले दिया था। अब चूंकि पारादीप बन्दरगाह चालू हो चुका है, जहां मेगनीज़ बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र होता जा रहा है, इसलिए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस क्षेत्र में पांचवां इस्पात करखाना या एक मझले दर्जे का इस्पात कारखाना स्थापित किया जाये ?

श्री चन्ना रेड्डी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बात पर भी विचार किया जायेगा ?

प्रश्नों क लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डिब्बों में बन्द किये गये खाद्य पदार्थों और फलों का निर्यात

***847. श्री शारदा नन्द** : **श्री भारत सिंह चौहान** :
श्री विश्वनाथ राय : **श्री रणजीत सिंह** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तैयार किये गये तथा डिब्बों में बन्द किये गये खाद्य पदार्थों और फलों की विदेशों में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ऐसे पदार्थों के निर्माताओं को प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। भारत में तैयार किये गये तथा डिब्बों में बन्द किए गए खाद्य पदार्थों एवं फलों की मांग लगातार बढ़ रही है।

(ख) और (ग) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:—

1. पंजीकृत निर्यातकों के लिए चालू आयात नीति के अन्तर्गत इन वस्तुओं के सम्बन्ध में जहाज पर निःशुल्क निर्यात मूल्य के दस प्रतिशत दर पर आयात प्रतिस्थापन का अधिकार है। पंजीकृत निर्यातक अथवा उनके नाम निर्देशित व्यक्ति इन आयात लाइसेंसों का प्रयोग निम्नलिखित वस्तुओं के आयात के लिए कर सकते हैं :—

(1) उन्हें मिले हुए किसी वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस में उल्लिखित मदें, यदि अप्रैल, 1967-मार्च, 1968 की अवधि के लिए आयात नीति के अनुसार उन मदों की अनुमति हो।

(2) अन्य मदें, यदि वे उन वस्तुओं के निर्माण के लिए अपेक्षित हों जिनका निर्माण लाइसेंसों के आवेदक करते हैं और पेकिंग का सामान।

2. उपरोक्त वस्तुओं पर नकद सहायता भी दी जा सकती है जो निर्यात के निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक होती है।

3. आयातित टिन प्लेटों पर 957·67 रु० प्रति टन शुल्क वापिस भी किया जाता है।

4. इसके अतिरिक्त चीनी से बनने वाले माल के निर्माताओं–निर्यातकों को डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ और फलों के निर्माण के लिए 'ग्रीन फार्म' आवंटन योजना के अन्तर्गत, चीनी का आवंटन भी किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग

***848. श्री यशपाल सिंह :**
श्री शशी रंजन :
डा० रानेन सेन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कुछ उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के कुछ उद्योग स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इस प्रयोजन के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केन्द्रीय (52 करोड़) और राज्य (30 करोड़) दोनों क्षेत्रों के लिए 82 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सीमेंट निगम के लिए 25 करोड़ रुपये और कागज निगम के लिए 41·5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Electrification of Calcutta-Delhi Railway Line

*849. Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :
Shri Arjun Singh Bhadoria
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in the electrification of the Calcutta-Delhi Railway line and the time by which this work will be completed;

(b) whether the electrification work is going on any other Railway lines also and if so, the names thereof; and

(c) whether a detailed report of all such works will be laid on the Table ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. LT–856/67]**

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों द्वारा भारत को खाद्य ऋण

*850. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित खाद्य ऋण के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) क्या भारत 'दी केनेडी राउण्ड' दल द्वारा औपचारिक करार का अन्तिम रूप दिए जाने की प्रत्याशा में इस व्यवस्था के अन्तर्गत अनाज खरीद सकता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अन्न सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंन्ध के सम्बन्ध के बातचीत को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । इसमें उन विकासशील देशों को जिन्हें, खाद्य सहायता की आवश्यकता है, इस प्रकार की सहायता देने का मामला भी समाविष्ट है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीका से आयात

*851. **श्री रमानी** :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल से अमरीका सरकार ने भारत द्वारा वाणिज्यक आधार पर अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों में खरीद करने पर विरोध प्रकट किया था;

(ख) यदि हां, तो यह विरोध किस आधार पर किया गया था; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात बाजार में मन्दी

***852. श्री ओंकार सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात बाज़ार में मन्दी आ जाने के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, 1966–67 में 15 करोड़ रुपये का घाटा दिखायेगा; और

(ख) यदि हां, तो हानि में चल रहे सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का 1966–67 का हिसाब-किताब अभी तैयार नही हुआ है और न उसका आडिट ही हुआ है परन्तु ऐसा अनुमान है कि कम्पनी को काफी घाटा रहेगा। इस घाटे के कारण अंशतः बाजार में मन्दी होना और अंशतः अन्य कारण जैसे भारी पूंजीगत खर्चो, परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों कच्चे माल और फालतू पुर्जों की कीमतों में वृद्धि, तथा श्रमिक अशान्ति आदि हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात कारखानों की कार्य पद्धति को फिर से सशक्त करने के लिए छः सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: —

(1) प्रबन्धकीय ढांचा

(2) प्रबन्धकीय नियन्त्रण

(3) तकनीकी सुधार

(4) लागत में कमी

(5) प्रोत्साहन योजनायें और

(6) बाजार में बिक्री।

नामपत्र (लेबल) बनाने की मशीनों का आयात

***853. श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अनेक पक्षों को नामपत्र (लेबल) बनाने की नवीनतम बढ़िया मशीनों का आयात करने की अनुमति दी है क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि में लेबल-उत्पादन कई सौ गुना बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार ने बाहर से नामपत्र बनाने की मशीनों का आयात करने के लिए इतने अधिक लोगों को अनुमति इसलिए दी थी कि सरकार नामपत्र बनाने की देशी मशीनों की तुलना में आयातित मशीनों को अच्छा समझती है ?

(ग) यदि हां, तो अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(च) पिछले पांच वर्षों में किये गये आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) लेबल कागज, परतदार कागज, प्लास्टिक की चादरों और धातु की चादरों में बनाये जाते हैं। बने हुए लेबल भी होते हैं जो 'लेबल करघों' पर बनाये जाते हैं। इनमें से कागज के लेबल बहुत प्रचलित हैं। मुद्रण तथा पैकेजिंग उद्योगों में काम आने वाले छपाई और कटाई के सामान्य उपकरण लेबल की छपाई के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें केवल नक्काशी के सहायक उपकरणों जैसे सन्तुलनकारी उपकरण की थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः गत पांच वर्षों में कागज से विभिन्न वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों द्वारा लेबल बनाने की कोई भी ऐसी मशीन बाहर से नहीं मंगाई गई है यद्यपि इस वर्षों में लेबलों की मांग काफी बढ़ी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा खनन निगम को ऋण

***854. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उडीसा खनन निगम को ऋण के रूप में कितनी राशि दी है;

(ख) क्या राज्य सरकार नें केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि वह इस खनन निगम को राज्य सरकार से अपने नियन्त्रण में ले ले;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारत सरकार को उड़ीसा सरकार द्वारा उठाये गये किसी ऐसे कदम की जानकारी है जिसका उद्देश्य उन खनन क्षेत्रों को, जो सरकार के खनन निगम के लिए खनिज निकालने के लिए सुरक्षित रखे गये थे, गैर-सरकारी खान-मालिकों को पट्टे पर देने का है;

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से पूछताछ की है; और

(च) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) भारत सरकार द्वारा निगम को ऋण के रूप में 3·425 करोड़ रुपये की कुल राशि दी गई है:—

(1) भारत सरकार द्वारा सीधे ऋण के रूप में मंजूर की गई राशि :

1965–66	1·85 करोड़ रुपये
1966–67	1·81 करोड़ रुपये
कुलः—	3·66 करोड़ रुपये

(2) राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में निगम को दी गई राशिः—

1966–67	0.765 करोड़ रुपये
समस्त राशिः—	3·831 करोड़ रुपये

(ख) नहीं महोदय ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) से (च) उड़ीसा सरकार से पता लगाया गया है कि कुछ क्षेत्र जो पहले उड़ीसा खनन निगम को दिये गये थे अब शायद निगम उन्हें छोड़ दे और इन क्षेत्रों को निजी पक्ष खुले रूप से पट्टे पर ले सकेंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में खनन नीति

*855. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला, सोना तथा लौह अयस्क सम्बन्धीं अधिकतर खनन उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) कोयला खनन उद्योग के स्वामी अधिकतर निजी-पक्ष हैं, परन्तु सोना खनन उद्योग पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में है। कच्चे लोहे का उत्पादन अधिकतर निजी पक्ष की खानों से होता है।

(ख) इन खनिजों से सम्बन्धित खनन उद्योग के विषय में सरकार की नीति औद्योगिक नीति संकल्प दिनांक 30 अप्रैल, 1956 में दी हुई है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

Manufacture of Small Car

*856. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Arjun Shing Bhadorla :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ramavtar Sharma :
Shri M. Meghachandra :
Shri Dhireswar Kalita :
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the **Planning** Commission had expresed their disapproval regarding the manufacture of small car;

(b) whether it is also a fact that the establishment of a factory in the public sector has almost been decided;

(c) if so, Government's clear cut policy in this regard; and

(d) the expenditure involved in the establishment of the factory, the extent of co-operation likely to be received from different countries separately and the terms and conditions thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) In the Programmes of Development and Investments proposed to the Planning Commission for the Fourth Five Year Plan, it had been suggested by the Industry Ministry that a project for the manufacture of 50,000 passenger cars per annum, including light duty vehicles, be included in the public sector, with a total investment of Rs. 350 million But it has not however been included in the Draft Outline so far.

(b) and (c) : Final decision as to whether the proposed project, when it is implemented, would be set up in the public sector or the private sector has not yet been taken. Goverment would, however, prefer the project to be taken up in the public sector in view of the large investment involved, if the resources needed for the project could be found.

(d) It is estimated that the investment on the establishment of a factory for an annual capacity of 50,000 cars would be of the order of Rs. 35 crores to Rs. 40 crores, with a foreign exchange content of about Rs. 15 crores. Exploratory talks have taken place with some parties, both Indian and foreign, who have offered to manufacture a low cost car in the private sector or in the public sector. Every party that has made an offer has been requested to furnish sufficient details of the offer to enable Government to examine its economic feasibility. On receipt of these details, all the schemes will be duly examined before taking a final decision in the matter.

अव्यवस्थित कपड़ा मिलों सम्बन्धी निगम

***858. श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 2 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अव्यवस्थित कपड़ा मिलों को चलाने के लिये प्रस्तावित निगम पर आरम्भ में कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी और उसे चलाने पर कितना खर्च होगा;

(ख) सर्वप्रथम कितनी अव्यवस्थित कपड़ा मिलों को चलाने का निगम का विचार है;

(ग) बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को चलाने के सम्बन्ध में निर्णय करते समय किन-किन बातों पर विचार किया गया है;

(घ) क्या इस योजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के ऋण से अथवा स्वतन्त्र साधनों से की जाती है; और

(ङ) क्या सरकार रूई का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई मिल खोलने के लिये विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यह विषय विचाराधीन है ।

(ख) से (घ) : इस समय ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) जी, नहीं ।

Production Capacity of H. E. C., Ranchi

*859 · **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 692 on the 26 May, 1967 and state :

(a) whether the present production of 15,000 metric tonnes of the Heavy Machine Building Plant of H. E. C., Ranchi has been treated as its target of production;

(b) if not, the reason for the present production being lower than the target; and

(c) whether this capacity is sufficient to meet the demands for machines in the country and if not, the reasons for imposing restrictions on the expansion of the said factory when machines have to be imported from abroad ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) : No, Sir, in fact, in addition to 15,000 tonns of mechanical equipment, the Heavy Machine Building Plant will also manufacture 11,240 tonnes of technological structurals during 1967-68, so that the total production planned is 26,240 tonnes. The capacity will progressively increase from year to year and eventually reach 80,000 tonnes. The utillisation of capacity will depend upon the orders in a particular year .

(c) Yes, Sir. Expansion can be considered when the demand justifies it

बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

*860. **श्री स्वैल** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थिति हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपने उत्पादों में विविधता लाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यह कारखाना अब किस प्रकार के औजार बना रहा है और कौन कौन से नये औजार बनाने का विचार है; और

(ग) क्या इन औजारों के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई योजना भी बनाई गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन मशीनी औजारों का इस समय निर्माण हो रहा है उनमें अत्यन्त सूक्ष्म खरादें, सामान्य प्रयोजन की खरादें, एल० श्रेणी की खरादें-टूरेट खरादों को सम्मिलित कर जल्दी मुड़ जाने वाली मशीनें स्वचालित इकहरे तकुए, घिसाई मशीनें (मैकेनिकल किस्म की और विद्युत नियंत्रित किस्म की), सुराख करने की आड़ी मशीनें, बेलनकार सान चढ़ाने की

मशीनें, गियर शेपर सूराख करने की बढ़िया मशीनें, विशेष प्रयोजन की मशीनें तथा ट्रांसफर लाइन मशीनें शामिल हैं। कम्पनी की योजना सर्फेस ग्राइंडिंग मशीनें, मल्टी टूल ऑटोमेटिक खरादें, कापीइंग खरादें, बहु तकुए वाली स्वचालित खरादें, गियर सापर, सूराख करने की आड़ी मशीनें और ब्रोचिंग मशीनें बनाने की है। इनके अलावा वह धातु से बनने वाली मशीनें जैसे इस्त्री, धातु की चादरें बनाने की मशीनों आदि का निर्माण करने पर भी विचार कर रही है। छपाई मशीनों, बिजली से चलने वाले चक्के अथा फ्लैंपिंग तरीके की मशीनें बनाने पर भी विचार कर रही है।

(ग) जी, हां।

Export of Cashew-nuts

***861 Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Arjun Shiogh Bhadoria : Shri Nar Deo Snatak : Shri Ram Avtar Sharma : Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that America is the main customer of Indian cashew-nuts and the demand therefor is constantly on the increase ;

(b) whether it is also a fact that India is unable to meet the American demand ;

(c) whether Government propose to increase the cashew-nut production with a view to meet the said demand ;

(d) if so, the steps proposed to be taken in this regard; and

(e) the additional quantity likely to be exported as a result thereof ?

The Ministre of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir. America accounts for about 50% of our exports at present.

(b) It cannot be said that India is unable to meet the demand. At the same time possibilities exist to further increase our exports to America.

(c) Yes Sir.

(d) Cashew Development Council is taking necessary action for developing Cashew plantations in different States of India. The target for Fourth Plan period is 3.28 lakh tonnes of raw cashewnut production in India as against the present estimated production of about 1.34 lakh tonnes.

(e) If Fourth Plan target is achieved, India would be able to export an additional quantity of about 15,000 tonnes per annum.

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले भारतीय रेलों के अधिकारी

***862. श्री बाबूराव पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल के कितने अधिकारी लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में काम कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक अधिकारी ने गत दो वर्षों अर्थात् 1965 और 1966 में कुल कितने मूल्य के माल का निरीक्षण किया था;

(ग) 1965 और 1966 में ब्रिटिश कम्पनियों को रेलवे उपकरण के लिये कुल कितने मूल्य के क्रयादेश दिये गये ;

(घ) क्या सरकार का विचार मितव्ययिता की दृष्टि से लंदन में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब ; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नौ, जिनमें से छः राजपत्रित हैं। इनमें तीन अधिकारियों के मुख्यालय यूरोप महाद्वीप में है।

(ख)

	लाख पौंडों में	
	1965	**1966**
रेलवे संयुक्त सलाहकार, लंदन	22.00	13.00
रेलवे उप सलाहकार, ज्यूरिच	34.00	20.00
रेलवे उप सलाहकार, बोन	21.00	14.00
रेलवे उप सलाहकार, वियाना/पेरिस	2.00	5 .00
रेलवे सहायक सलाहकार लंदन	4.00	3 .00

(ग) 1965 में 12 लाख पौंड

1966 में 5 लाख पौंड

(घ) से (च) कार्य भार तथा विदेशों में नवीनत्तम विकास कार्यों की जानकारी रखने के लिये अनुभवी इंजीनियरों की आवश्यकता को देखते हुए स्थिति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और कमी की जाती है।

चेकोस्लावाकिया से टैक्टरों का आयात

*** 863. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मु० कु० तापड़ियां :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामअवतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री रघुवीरसिंह शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री न० कु सौंधी :
श्री बेदव्रत बरुआ :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया तथा रूस से 20 अश्व शक्ति (हार्स पावर) के टैक्टरों का आयात करने तथा सरकारी क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की लागत से एक टैक्टर तथा फार्म उपकरण कारखाना लगाने के प्रस्ताव को टैक्टरों के व्यापारियों तथा निर्माताओं को समर्थन नहीं

मिला जैसा कि कहा गया है कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में नहीं है और इससे देश के एक महत्वपूर्ण उद्योग को भारी नुकसान पहुंचेगा :

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) टैक्टरों के आयात और सरकारी क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी टैक्टरों तथा औजारों का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना की स्थापना के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में छपाई की मशीनों का निर्माण

***864. श्री आत्म दास**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भारत में छपाई की मशीनों का निर्माण करने लगेगा

(ख) क्या यह निर्माण कार्य कुछ विदेशी फर्मों के सहयोग से किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई समझौता हो गया है;

(घ) क्या ऐसा कारखाना मध्य प्रदेश में स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उत्पादन में विविधता लाने और अपनी बेकार क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए कम्पनी का विचार अपने एक विद्यमान कारखानों में छपाई मशीनें बनाने का है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बातचीत की जा रही है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में रौलिंग मिल रोल्स का निर्माण

***865. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबकि हैवी इंजियरिंग कारपोरेशन, रांची में रोलिंग मिल रोल्स का निर्माण आरम्भ हो चुका है, जिसकी सप्लाई के लिये भारत के इस्पात रौलिंग मिलों

को इससे पूर्व ब्रिटेन, जर्मनी, जापान तथा रूस से आयात पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता था, स्वदेशी रोलिंग मिल रोल्स का मूल्य आयात शुल्क सहित आयातित रोल्स के लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य से दुगुने से भी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी माल के अत्यधिक मूल्य होने के क्या कारण है ; और

(ग) उनके मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि रिरोलिंग मिलों में बनी हुई निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत में अधिक वृद्धि हुए बिना ही स्वदेशी माल अच्छे आयात स्थानापन्न के रूप में अपना उचित स्थान ले सकें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नकली रेशम के कपड़ों के निर्यात सम्बन्धी नीति

*866. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के पश्चात नकली रेशम के कपड़े का निर्यात समाप्त हो जाने के कारण नकली रेशम उद्योग पूर्णतया नष्ट हो गया है ;

(ख) क्या आयात को निर्यात से पृथक करने के कारण रेयन सिंथटिक कपड़े का निर्यात बाजार समाप्त हो गया है क्योंकि सिंथटिक कपड़े का निर्यात मुख्य रूप से आयात हकदारी पर ही निर्भर करता था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम को दिये गये आयात लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया है और इस कारण उद्योग का काम-धन्धा समाप्त हो गया है ; और

(घ) नकली रेशम उद्योग को पुनः चालू करने हेतु सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रेयन तथा संश्लिष्ट कपड़ों के निर्यात के बदले संश्लिष्ट धागे के आयात सम्बन्धी आयात हकदारी योजना के वापिस लिये जाने से है । इस योजना की इस सदन में प्रतिकूल आलोचना हुई थी और अवमूल्यन के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया । इसके स्थान पर आयात अब राज्य व्यापार निगम के द्वारा किये जाते हैं और राज्य व्यापार निगम ऐसे निर्माताओं तथा निर्यातकों को वित्तीय समर्थन भी देता है जो पुराने बाजारों को बनाए रखने तथा नए बाजारों के विकास के लिये आतुर हों, फिर भी यह उचित नहीं समझा जाता कि ऐसे वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय जो विदेशों में भारी घाटे पर ही बिक सकते हैं ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । क्रयादेश दे दिये गये हैं और आयात शीघ्र ही किये जायेंगे । आशा है कि स्थानीय उत्पादन और आयातों के परिणाम स्वरूप कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग में उत्पादन को उचित स्तर पर बनाये रखना संभव होगा ।

छोटी (नैरो गेज) रेलवे लाइनों को हटाना

*867. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दाहेजसामनी सैक्शन की रेलवे लाइन को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में केन्द्रीय गुजरात वाणिज्य मंडल की ओर से दिनांक 7 जून, 1967 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार गुजरात में छोटी (नैरो गेज) अथवा मीटर गेज रेलवे लाइनों, जैसे नाडियाद-भाद्रन और नाडियाद-कपडवंज छोटी लाइन (नैरो गेज) सैक्शनों की रेलवे लाइनों को हटाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किन किन छोटी लाइनों को हटाने का प्रस्ताव है और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।
(ख) और (ग) इस समय नडियाद-भद्रन अथवा नडियाद–कपडवंज छोटी लाइन (नैरो गेज) सैक्शनों की रेलवे लाइनों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि छोटी रेलवे लाइनों को (जिनमें उपर्युक्त लाइनें भी शामिल हैं) रखने/बन्द करने अथवा उनमें से एक या अधिक छोटी लाइनों को चौड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के बारे में औचित्य का पता लगाने के लिये उनके कार्य संचालन का हाल में पुनर्विलोकन आरम्भ किया गया है । यह पुनर्विलोकन कार्य पूरा हो जाने, सभी तथ्यों पर विचार करने तथा सभी सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करने के बाद घाटे पर चलने वाले छोटी लाइन के किसी सैक्शन को बन्द करने के बारे में कोई निर्णय किया जायेगा ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में औजार और कलम-छोड़ हड़ताल

868. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री मुद्रिका सिंह :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री तु० राम :
श्री शिव चण्डिका प्रसाद :
श्री कार्तिक ओराओं :
श्री श्रीकांतन नायर :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मधु लिमये :
श्री नम्बियार :
श्री रवि राय :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री कंडप्पन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० कु० किस्कू :
श्री उमानाथ :
श्री चितरंजन राय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री एस्थोस :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के 16,000 कर्मचारियों ने 5 जून, 1967 से औजार तथा कलम-छोड़ हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) हड़ताल को समाप्त कराने के लिए तथा कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)–(क) और (ख) इस कम्पनी के 6982 कर्मचारी एक मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग पत्र के समर्थन में 5 जून, 1967 से 12 जून, 1967 तक औजार छोड़ हड़ताल पर रहे थे । ये मांगें सेवा की शर्तें, वेतन में वृद्धि तथा भत्ते और कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में थी ।

(ग) यह हड़ताल 13 जून, 1967 को समाप्त की गई थी । इनमें से अधिकांश मांगें 5 नवम्बर, 1966 को कर्मचारी संघ के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत आती है; किन्तु पटना उच्च न्यायालय ने समझौते की क्रियान्विति को रोकने के लिये आदेश जारी कर दिया है । प्रत्येक मामले पर विभिन्न मजदूर संघों द्वारा प्रतिनिधियों पर विचार किया जा रहा है और उन पर कार्यवाही की जारही है ।

कारों की मांग में वृद्धि

770. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री आत्मदास

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 125,000 व्यक्तियों ने कारें खरीदने के लिये डाक घरों में जमानत के रूप में 24 करोड़ रुपये जमा कराये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाकघर में प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् फिएट कार प्राप्त करने में सात वर्ष लगते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31 दिसम्बर, 1966 को देश भर के विभिन्न व्यापारियों के पास कारें खरीदने के लिये 1,21, 384 क्रयादेश बुक कराये गये थे । मोटर कार (वितरण तथा विक्रय) नियंत्रण के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यापारी के नाम में प्रत्येक क्रयादेश के लिये बचत बैंक में जमानत के रूप में 2,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं । इस आधार पर 31 दिसम्बर, 1967 को डाकखानों में इस खाते में जमा कुल राशि 24.27 करोड़ रुपये होगी ।

(ख) विभिन्न स्थानों में फियेट कार के लिये प्रतीक्षा की अवधि पृथक पृथक होती है। दिल्ली केन्द्र में प्रतीक्षा की अवधि 8 से 10 वर्ष तक बताई जाती है।

(ग) कारों के निर्माण की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हनुमानगढ़ और हिन्दूमलकोट के बीच बड़ी रेलवे लाइन

*** 4116. डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हनुमानगढ़ को हिन्दूमलकोट से मिलाने वाली बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के बीच एक मीटर गेज लाइन पहले से ही है। इन दो स्थानों के बीच बड़ी रेलवे लाइन की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य कदाचित हिन्दूमल कोट और श्री गंगानगर के बीच बड़ी रेलवे लाइन का उल्लेख कर रहे हैं। अप्रैल, 1967 तक इस रेलवे लाइन का 30 प्रतिशत कार्य हो चुका था। राजस्थान सरकार द्वारा अपने वचन के अनुसार मिट्टी का कार्य पूरा करने तथा इस परियोजना के लिये सेवाओं की व्यवस्था तथा रहने के लिये मकानों का निर्माण के लिये कुशल तथा अकुशल मजदूरों की व्यवस्था करने के छः महीने के बाद यह परियोजना पूरी हो जायेगी।

चुरू और नोहर के बीच रेलवे लाइन

4117. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चुरू कस्बे को तारानगर (राजस्थान) के रास्ते नोहर से एक रेलवे लाइन के द्वारा मिलाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) चुरू कस्बा सादूलपुर से होकर नोहर से रेल द्वारा मिला हुआ है। धन की कमी के कारण इस प्रस्तावित रेलवे लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

त्रिपुरा में कागज बनाने का कारखाना

4118. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री बि० कु० मोदक
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार का विचार त्रिपुरा में एक कागज बनाने का कारखाना, एक प्लाईवुड का कारखाना और एक पटसन मिल स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों तथा कारखानों को शीघ्र स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) प्लाईवुड बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक गैर सरकारी पार्टी को लाइसेंस दिया गया है। अभी कारखाना स्थापित किया जाना है।

फरवरी, 1965 में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिए एक गैर सरकारी पार्टी को आशय पत्र दिया गया था। यह आशय पत्र वापिस लेना पड़ा था; क्योंकि सरकार द्वारा मान्य शर्तों पर यह पार्टी मशीनों का आयात करने की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं थी। उस राज्य में पटसन कारखाना स्थापित करने का कोई अन्य प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जहां तक कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने का सम्बन्ध है, उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र में समूचे कार्यक्रम के अनुसार सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने पर विचार किया जायेगा।

Reversion of Firemen on the Eastern Railway

4119. Shri Ram Avatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Second Firemen of Sealdah Division had filed a suit (No. 2985 (w), 1966) in the calcutta High court against their reversion from firemen to cleaners;

(b) wheter the High Court issued injunction in which the entire Eastern Railway Administration has been instructed to stop such reversions forthwith;

(c) whether these reversions of the Second Firemen as Cleaners have been stopped in Sealdah, Asansol, Howrah and Dhanbad after the injunction was issued by the High Court;

(d) whether it is also a fact that the officials of Danapur Division have reverted a number of Second Firemen vide Divisional Superintendent, Danapur Order No. 'E' Office Order No. 1822/1966 in violation of the said injunction order; and

(e) if so, the reasons therefor and the action Government contemplate to take in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, it was not against the reversion order from Second Firemen to Cleaners but because some of the surplus Firemen were ordered for posting in the alternative category of Levermen Grade II/Shuntmen, that a suit was instituted in the Calcutta High Court.

(b) The High Court issued interim order of injunction against the orders of postings referred to above.

(c) Does not arise, in view of reply to (b) above

(d) and (e) 22 juniormost surplus officiating Second Firemen were reverted to the posts of Cleaners from which category they had been promoted earlier. But these reversions did not involve any violation of the order of injunction.

गोआ में जहाज बनाने के गैर–सरकारी छोटे कारखाने

4120. श्री शिंकरे: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य—मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ में जहाज बनाने के अनेक गैर सरकारी छोटे छोटे कारखाने हैं जहां पर बजरे बनाए जाते हैं;

(ख) क्या ये कारखाने गोआ के खान मालिकों तथा गोआ में खनन व्यवसाय ; में लगी हुई विदेशों फर्मों के विभिन्न टनेज के बजरों की आवश्यकना पूरी कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष सरकार ने किन कारणों से बजरों का आयात करने की अनुमति दी थी; और

(ख) क्या इन कारखानों के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है जिससे कि बजरों का आयात करने की आवश्यता न पड़े ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) देश में इस समय बजरे बाने के थोड़े से कारखाने हैं । जिनमें गोआ स्थित चार कारखाने भी शामिल हैं । गोआ स्थित कारखानों में अधिकांशत: बजरों की मरम्मत तथा देख भाल होती है ।

(ग) लोह अयस्क के निर्यात व्यापार की तत्काल आवश्यकता पूरी करने के लिये आयात की अनुमति दी गई थी क्योंकि बजरे बनाने तथा उनमें प्रयोग होने वाले आयातित इस्पात तथा इंजनों पर निर्भर रहने के कारण देश के निर्यात उनका शीघ्र निर्माण करने की स्थिति में नहीं थे ।

(घ) जब कभी बजरों के निर्माण/विस्तार के लिए कारखाना स्थापित करने/ वर्तमान कारखानों का विस्तार करने के लिये प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर उनके गुण और दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

मनीपुर को लोहे की नालीदार चादरों का नियतन

4121. श्री मेघचन्द: क्या इस्पात, खान और धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में मनीपुर को लोहे की नालीदार चादरें कितनी आवंटित की गई थीं;

(ख) वर्ष 1966-67 में मनीपुर सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को लोहे की नालीदार चादरें दी गई थीं; और

(ग) क्या यह सच है कि थंगाकुम्बी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोगों की प्राथमिकता के आधार पर लोहे की नालीदार चादरें दी गई थी, और यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में कितने व्यक्तियों को ये चादरें मिली ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) 3,000 टन।

(ख) 2440 व्यक्तियों को।

(ग) थंगाकुम्बी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर लोहे की नालीदार चादरें नहीं दी गई परन्तु उस निर्वाचन-क्षेत्र के 123 व्यक्तियों को नियमित आधार पर 127 टन लोहे की नालीदार चादरें दी गई।

सरकोणम में स्टेनलेस स्टील का कारखाना

4122. श्री सोमसुन्द्रम : क्या इस्पात खान, तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1968 में आरकोणम में स्टेनलैस स्टील का एक कारखाना चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान प्रगति क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

4123 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला सार्थ-समूह की फर्म हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता, स्टाक ऐक्सचेंज में डुप्लीकेट शेयर बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कैसे संभव हुआ है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि कलकत्ता में, हिन्दुस्तान मोटर्स के शेयर पावती-पत्रों का, जो विशुद्ध नहीं थे, अत्याधिक मात्रा में व्यापार हुआ। आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने

4124. श्री बाबूराव पटेल : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों ने क्या क्या, कैसे कैसे तथा कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया ;

(ख) ये उत्पादन किन किन देशों को निर्यात किये गये तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) अन्य देशों की तुलना में हमारे इस्पात उत्पादकों के मूल्य कैसे हैं; और

(घ) हमारे सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन लागत कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 857/67)

(ग) विदेशों में भारतीय लोहा और इस्पात स्पर्धी मूल्यों पर बेचा जाता है।

(घ) मेहताब समिति ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थी जिन पर सरकार विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की पत्र-पत्रिकायें

4125. श्री बाबूराव पटेल : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कितने और कौन-कौन से विभिन्न प्रकाशन तथा पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित किये जाते हैं;

(ख) प्रत्येक की कितनी प्रतियां छापी जाती है और कितनी लागत आती हैं

(ग) प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों की कितनी प्रतियां बिकती हैं और उनसे कितनी आय होती है;

(घ) इन पत्र-पत्रिकाओं से क्या विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है; और

(ङ) इस बात को देखते हुए कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को प्रति वर्ष भारी घाटा हो रहा है क्या इन पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द करके इस व्यय को रोका जा सकता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा समय-समय पर निकाले जाने वाली पुस्तिकाओं, विज्ञापनों और प्रचार संबंधी साहित्य के अलावा उनके निम्नलिखित नियमित प्रकाशन है :—

क्रम संख्या	प्रकाशन का नाम	छापी गई प्रतियों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लागत
1	2	3	4
1	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट	2000	30,000 रुपये
2	इस्पात क्वार्टरली	1000	18,000 रुपये
3	स्टेटिस्टिक्स फार आयरन एण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज इन इन्डिया	2000	24,000 रुपये

4	राउरकेला न्यूज	3000	65,000 रुपये
5	राउर केला समाचार-(उड़या भाषा में)	2000	
6	भिलाई स्टील प्लाण्ट मैगजीन	1500	18,000 रुपये
7	दुर्गापुर स्टील टाइडिंग्स	2000	50,000 रुपये
8	दुर्गापुर स्टील दर्पण (बंगाल में)	3000	

उपर्युक्त में से, स्टेटिस्टिक्स फार आयरन एण्ड स्टील इन्डस्ट्री इन इन्डिया अभी हाल में छापी जाने लगी है। जन साधारण के लिए इसका मूल्य 25 रुपये और हिन्दुस्तान स्टील लिमटेड के कर्मचारियों के लिए 10 रुपये हैं। दूसरे प्रकाशनों का कोई मूल्य नहीं रखा गया है और उनकी मुफ्त बांटा जाता है।

(घ) कम्पनीला के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कानूनन लाजिमी है। यह संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है और संसद सदस्यों और अन्य ऐसे लोगों को दी जाती है जो इसमें रुचि रखते हैं। इस्पात क्वार्टरली एक तकनीकी पुस्तिका है और इसका प्रकाशन इसी तिमाही से शुरू किया गया है, इसमें स्टील टेक्नोलौजी के क्षेत्र में नये तरीकों और प्रयोगों तथा मैनेजमेन्ट के बारे में जानकारी होती है। कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी जानकारी देने का यह एक उपयोगी माध्यम है। स्टेटिस्टिक्स फार आयरन एण्ड स्टील इन्डस्ट्री इन इन्डिया में भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के उत्पादन, प्रेषण, कच्चे माल की सुविधाओं के बारे में तथा विश्व इस्पात उद्योग के बारे में उपयोगी जानकारी होती है। देश में यह अपने ढंग का पहला प्रकाशन है और उद्योग के बारे में जानकारी देने तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक जानकारी देने के कारण इससे देश में इस्पात उद्योग की उन्नति में मदद मिलेगी। शेष प्रकाशन घरेलू पत्रिका और कर्मचारियों के लिए समाचार पत्र का काम देते हैं और उनमें कम्पनी के उत्पादन और विकास, कम्पनी की नीतियों, कर्मचारियों के सुझावों और कर्मचारियों के सभी वर्गों की गति विधियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें होती हैं। इनसे कर्मचारियों और प्रबन्धक वर्ग के बीच विचार का दुहरा आदान प्रदान हो जाता है।

(ङ.) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विचार में कर्मचारियों और प्रबंधकों वर्ग के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने, कर्मचारियों को कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की सूचना देने और इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकी विकास और सुधारों के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए ये पत्र पत्रिकाएं बहुत उपयोगी हैं।

आयात लाइसेंस जारी करना

4126. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी वस्तुओं के लिए जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है आयात लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं क्या हैं; और

(ग) भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग न करने और उनका आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) सामान्य नीति यह है कि जो वस्तुएं देश में बनती हैं अथवा जिनके निर्माण के लिये अप्रयुक्त क्षमता है, उन वस्तुओं का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है। विशेष प्रयोजन के लिये मशीनों के आयात तथा बहुत विशेषीकृत वस्तुओं के आयात जिनमें इडेंण्ट करने वाले के विशिष्ट विवरण के अनुसार वस्तुएं वैकल्पिक विशिष्ट विवरण द्वारा भी उपलब्ध नहीं है, तथा उन वस्तुओं के आयात के आयात जिन्हें भारतीय संभरणकर्त्ता भारत के आर्थिक हित में समय पर नहीं दे सकते हैं, अपवाद स्वरूप अनुमति दी जाती है।

मशीनों का निर्यात

4127. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी किस प्रकार की मशीनों का निर्माण किया जाता है जिनका निर्यात किया जाता है और जिनका देश में इसका निर्यात होता है उनके नाम क्या हैं; और

(ख) ऐसी मशीनों के लिये वार्षिक मांग क्या है तथा इस मांग को कहां तक पूरा किया गया है और पिछले पांच वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) उपलब्ध नवीनतम आकड़ों के अनुसार एक विवरण, जिसमें यह दिखाया गया है देश में किस प्रकार मशीनें बनाई जाती हैं तथा उनका निर्यात किन किन देशों को किया जाता है, सभा पटल पर रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 858/67)**

(ख) पिछले पांच वर्षों में वार्षिक मांग संकलित नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके लिये गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों के अलग अलग प्राक्कलन तथा जानकारी एकत्र करने होंगे। पिछले पांच वर्षों में निर्यात व्यवस्था द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :

रुपये लाखों में

	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67*
बिजली से चलने वाली मशीनों के भिन्न अन्य मशीनें	238	241	277	401	476	526
मशीनें (बिजली से चलने वाली)	102	129	157	246	320	438

(*केवल फरवरी, 1967 तक)

गोआ में खनन कार्यों के लिये लाइसेंस

4128. श्री शिंकरे: क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोआ में खनन कार्य के लिये नये लाइसेंस न देने की सरकार की नीति के बारे में गोआ वासियों में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त है;

(ख) क्या इस नीति ने नये उद्यमी गोआवासियों को खनन कार्य से वंचित किया है और खान-मालिकों के पुराने विशेषाधिकृत वर्ग को लाभ पहुंचाया है जो गोआ में भूतपूर्व पुर्तगाली शासन को स्थिर बनाने में सहयोगी थे; और

(ग) क्या सरकार वास्तविक राजनैतिक पीड़ितों के, जिन्हें स्वतन्त्रता संग्राम में अपने व्यवसाय से हाथ धोना पड़ा था, कई खानों में खनन-कार्य के लिये आवेदन-पत्रों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) गोआ में खनिज रियायतें जिसमें पूर्वक्षण के लाइसेंस भी शामिल हैं, खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार दी जाती हैं। प्रत्येक आवेदन पत्र पर उसके गुणानुसार विचार किया जाता है। वर्तमान तथा भावी खान स्वामियों में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है।

(ग) गोआ सरकार को अभी तक किसी राजनैतिक पीड़ित का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यदि ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हो तो उस पर उसके गुणों को देख कर, खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957 के अनुबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा।

गोआ में छर्रे बनाने का कारखाना

4129 : श्री शिंकरे क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन खान-मालिकों को गोआ में छर्रे बनाने के कारखाने स्थापित करने के लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक कारखाने के लिये अपेक्षित मशीनों का आयात करने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा मन्जूर की गई है ;

(ग) छर्रे बनाने के प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(घ) क्या ऐसे किसी कारखाने ने छर्रे बनाने का काम शुरू कर दिया है तथा क्या उनका निर्यात भी किया जाता है; और

(ङ) जो लाइसेंसधारी अब तक अपने कारखाने स्थापित नहीं कर सके हैं, उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उद्योग (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत गुलिकाएं बनाने का प्लांट लगाने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि गोआ में गुलिकाएं

बनाने के प्लांट लगने की दो निजी पक्षों मैसर्स चौगुले एण्ड कं० प्राईवेट लि० तथा मैसर्स वी० एम० सलागाकार एण्ड ब्रादर्स प्रा० लि०–की योजनाएं सरकार ने अनुमोदित कर दी हैं।

(ख) मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी प्रा० लि० के प्लांट के लिये मशीनों के आयात के लिये 222.21 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी गई। मैसर्स वी० एम० सालागकार एण्ड ब्रादर्स प्रा० लि० द्वारा लगाये जाने वाले प्लांट के लिये प्लांट तथा मशीनरी विदेश से मंगवाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी प्रा० लि०	0.55 मिलियन टन गुल्लिकाएं प्रति वर्ष
मैसर्स सलागाकार एण्ड ब्रादर्स प्रा० लि०	1.5 मिलियन टन गुल्लिकाएं प्रति वर्ष (प्रस्तावित)

(घ) हां, महोदय। मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी द्वारा स्थापित किये गए गुल्लिकाओं के प्लांट नें मार्च 1967 से उत्पादन शुरू कर दिया। अप्रैल 1967 से इस प्लांट से 64,632 टन गुल्लिकाएं विदेशों में भेजी जा चुकी हैं।

(ङ) परियोजना के लिए धन जुटाना, जिसमें विदेशों से मशीनें तथा प्लांट मंगवाने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें भी शामिल हैं। इस समय मुख्य कठिनाई समझी जाती है।

गोआ के छोटे खान-मालिक

4130. श्री शिकरे: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्ज मिनरल्स एण्ड माइन्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आँफ इण्डिया लिमिटेड, गोआ के छोटे खान-मालिकों से लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खरीदने और इस प्रकार उनकी सहायता करने के स्थान पर बड़े खान-मालिकों से सौदे कर रहा है तथा इससे गोआके छोटे खान-मालिकों को काफी निराशा हुई है;

(ख) क्या इससे बड़े खान-मालिकों को एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो गई जिससे वे छोटे खान-मालिकों से कम दर पर अयस्क खरीदते हैं जिससे न तो उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिलता है और न ही उनका खर्चा पूरा होता है।

(ग) क्या इन बड़े खान-मालिकों ने मिनरल्स एण्ड माइन्स ट्रेडिंग कारपोरेशन को अपने आपको छोटे खान-मालिक दिखाने तथा ऊंची दर पर अयस्क बेचने के लिये कुछ छोटी कम्पनियां स्थापित कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन छोटे खान-मालिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) जी, नहीं। मिनरल्स एण्ड माइन्स ट्रेडिंग कारपोरेशन क्रयादेशों को पूरा करने के लिए गोआ में अयस्क खरीदता है। इसकी खरीद में वह

छोटे खान-मालिकों को प्राथमिकता देता है। जब छोटे खान-मालिक अपेक्षित श्रेणी की तथा अपेक्षित मात्रा में सप्लाई नहीं कर सकते हैं तब यह कारपोरेशन अन्य खान–मालिकों के साथ जो अपने कार्य के आकार के अनुसार बड़े खान-मालिक कहाते हैं, करार करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे विभाग में मशीनीकरण की व्यवस्था

4131. श्री गणेश घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 1964 से कलकत्ता क्षेत्र में यातायात लेखा कार्य का कुछ भाग और ईंधन लेखा का कार्य कुछ भाग मशीनों द्वारा किया जाने लगा है जिसके कारण उन कामों के लिये मंजूर किये गये 360 पदों में से 126 पद समाप्त कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मशीनीकरण व्यवस्था लागू करने के कारण फालतू होने वाले सभी क्लर्कों को रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यातायात लेखा कार्य का एक भाग जुलाई 1966 से चरणों में मशीनों द्वारा किया गया है। ईंधन लेखा कार्य अगस्त, 1966 से मशीनों द्वारा किया गया है : इस मशीनीकरण व्यवस्था से कलकत्ता क्षेत्र में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के सेक्शनों में प्रभावित होने वाले 963 स्वीकृत पदों में से 224 कर्मचारी अब तक फालतू हो गये हैं।

(ख) मशीनों से लेखा कार्य व्यवस्था लागू करने से फालतू हुए सब क्लर्क इन रेलवे के वर्तमान पदों पर रख लिये गये हैं।

पूर्व रेलवे में संगणक लगाना

4132. श्री गणेश घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर 1967 से पूर्वान्तर रेलवे में (एक) स्टोर का पूरा हिसाब किताब (दो) ईंधन का पूरा हिसाब किताब (तीन) भविष्य निधि का पूरा हिसाब किताब (चार) यातायात के यंत्रीकृत अंश का हिसाब किताब और (पांच) वेतन बिलों के संकलन के सारे कार्य का हिसाब किताब लगाने के लिये संगणक लगाने का निर्णय किया गया है जिससे तत्काल कलकत्ता क्षेत्र में लगभग 1500 व्यक्ति तथा आसनसोल और दानापुर क्षेत्रों में 1000 व्यक्ति फालतू हो जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि इन व्यक्तियों की छटनी न की जाये और उन्हें नौकरी से न निकाला

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) ; (क) और (ख) पूर्व रेलवे में अक्तूबर, नवम्बर, 1967 में एक संगणक (कम्प्यूटर) लगाने का निर्णय किया गया है । आरम्भ में संगणक पर केवल वही कार्य किये जायेंगे जो इस समय यूनिट रिकार्ड मशीनों पर किये जा रहे हैं अर्थात् यातायात लेखे तथा ईंधन लेखे का कुछ भाग । अन्य कार्य जैसे भण्डार लेखा, वेतन बिल बनाना आदि, के लिये एक क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे संगणक प्रयोग में लाया जायेगा ताकि एक ही समय में काफी कर्मचारी बेकार न हो सकें । इस प्रकार फालतू हुए कर्मचारियों को रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जायेगा और इस समय सेवा कर रहे व्यक्तियों को इसके कारण निकाला नहीं जायेगा ।

रेलवे में अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

4133. श्री गणेश घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे केवल पूर्व रेलवे में ही कुल 40,000 क्लर्कों की छंटनी की जाने की संभावना है जो पूर्ण रूप से कमप्यूटरों का प्रयोग आरम्भ किये जाने पर फालतू घोषित कर दिये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । कमप्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने की वर्तमान प्रणाली के कारण किसी क्लर्क की छंटनी नहीं की जायेगी ।

भड़ौच और दहेज के बीच नैरो गेज सेक्शन का बन्द किया जाना

4134. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में भड़ौच और दहेज के बीच नैरो गेज सेक्शन बन्द किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भड़ौच के वाणिज्य मंडल ने तथा अन्य व्यक्तियों ने इस पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस समय इस सैक्शन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी पश्चिम रेलवे में कुछ नैरो गेज सैक्शनों को, जिनमें भड़ौच-सामनी-दहेज नैरो गेज सैक्शन भी शामिल हैं, रखने, समाप्त करने अथवा उन्हें बड़े गेज में बदलने के औचित्य का पता लगाने के लिये जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) जैसा कि उपरोक्त भाग (क) में कहा गया है इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

रेलवे भोजन यान

4135. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर लखनऊ जंकशन और सिलिगुडी के बीच चलने वाली 15 अप और 16 डाउन एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के साथ रेलवे भोजन यान लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा और यह भोजन यान कितनी दूरी तक जायेगी; और

(ग) क्या इसको विभागीय आधार पर चलाया जायेगा अथवा किसी अन्य अभिकरण के द्वारा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महिला कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

4136. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चार बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की महिला सफाई कर्मचारियों (सफाईवाली) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन महिला कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान बन्द कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन महिला कर्मचारियों को पहले दिये गये मकान भत्ते को वापिस जमा कराने के लिये कहा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) उनका मकान किराया भत्ता बन्द नहीं किया जाना चाहिये और उन्हें अब तक दिया गया मकान किराया भत्ता उनके वेतन में से न काटा जाये क्योंकि वे अपने पतियों के साथ रह रही हैं जो रेलवे कर्मचारी ही हैं और जिन्हें रेलवे क्वार्टर मिले हुए हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) उन्हें कोई मकान भत्ता नहीं मिल सकता जो अपने आवास पर कोई किराया खर्च नहीं करते हैं। चूंकि एक पत्नी को जो अपने पति के साथ रहती है मकान किराये के रूप में कुछ खर्च नही करना पड़ता है, इसलिये वह मकान किराया भत्ता नहीं ले सकती।

(ड) जी हां।

बस्तर में खनिजों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण

4138. श्री झा सुन्दरलाल : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में विभिन्न खनिजों तथा धातुओं का सर्वेक्षण करने तथा उनको निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सदन की पटल पर रखा जायगा।

रायपुर में जगदलपुर तक रेलवे लाइन

4139. श्री झा० सुन्दरलाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या निकट भविष्य में बस्तर जिले में रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) दांतेवाड़ा तथा ढल्ली राजहरा के बीच एक नई बड़ी रेलवे लाइन बनाने के लिये हाल ही में संभाव्यता तथा लागत संबंधी अध्ययन किये गये थे। इस लाइन की लम्बाई 136.5 मील होगी और इस पर 19.44 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जांच-पड़ताल से पता चला है कि यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी और इसलिये इसे रेलवे की चौथी योजना में शामिल करने की बहुत ही कम संभावना है।

इस्पात का मूल्य

4140. श्री शिवचन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन से पहले तथा उसके बाद भारत में इस्पात का प्रति टन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात मूल्य की तुलना में क्या था:

(ख) इस्पात पर से नियन्त्रण हटाए जाने के बाद इस्पात का प्रति टन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात मूल्य की तुलना में क्या है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात मूल्य की तुलना में रुपये के अवमूल्यन और इस्पात पर से नियन्त्रण हटाए जाने के पश्चात् भारत में इस्पात का मूल्य कितना बढ़ गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) समीकृत भाड़े और उत्पादन शुल्क में वृद्धियों को छोड़कर भारत में अप्रैल 1964 से लेकर इस्पात के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अवमूल्यन से लेकर 2–5–67 तक घरेलू मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अवमूल्यन के फलस्वरूप विनिमय दर में परिवर्तन होने के अलावा भारत में अवमूल्यन अथवा इस्पात के मूल्य और वितरण पर से नियन्त्रण हटाये जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नीचे की सारणी में कुछ किस्मों के इस्पात के अवमूल्यन के पूर्व और 2–5–67 के पश्चात् के मूल्यों की जापान और यू० के० के आन्तरिक मूल्यों से तुलना की गई है :–

(प्रति टन मूल्य रुपयों में)

इस्पात की किस्म	जापान 4–6–66	जापान 19–5–67	यू० के० वितरण के खर्च को निकाल कर जो 2 पौण्ड माना गया है 4–2–66	यू० के० 2–5–67	संयुक्त सयंत्र समिति के मूल्य 2–5–67 से पूर्व	संयुक्त सं० समिति के मूल्य उत्पादन-शुल्क और भाड़े (75 रु०) को निकालकर 2–5–67 से पूर्व	संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य 2–5–67 के मूल्य पश्चात	संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य उत्पादन-शुल्क और भाड़े (75 रु०) को निकाल कर 2–5–67 के पश्चात
छड़ 14 मिलीमीटर और उससे कम प्लेटें	507	729	548	874	738	538	790	590
संरचनात्मक	598	813	541	889	850	640	900	690
(ज्वाइस्टस)	520	1125	512	846	768	568	800	600

(छड़ों और संरचनात्मकों पर उत्पादन-शुल्क 125 रुपये है और प्लेटों पर 135 रुपये)

रेलवे भोजन यान

4141. श्री शिवचन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों में किन-किन लाइनों पर कितनी-कितनी भोजन यान चल रही हैं; और

(ख) चतुर्थ योजना की अवधि में इनकी संख्या में अनुमानतः कितनी वृद्धि की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बड़ी लाइन पर भोजन यानों की कुल संख्या 1 जनवरी, 1967 को 172 थी और मीटर गेज पर 43 थी। एक विवरण जिसमें उन गाड़ियों/सैक्शनों के नाम दिये हुए हैं जिन पर भोजन यान की व्यवस्था है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 859/67]

(ख) चौथी योजना अवधि में बड़ी लाइन पर 26 तथा मीटर गेज लाइन पर 6 भोजन यान जोड़े जाने का अनुमान है।

Import of Drilling Rigs

4142. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Northern Engineering Company of U. K. is giving priority to the supply of drilling rigs to India;

(b) whether Government propose to take ready-made drilling rigs from them or to obtain their parts and then assemble them in the country;

(c) the number of drilling rigs for which order has been placed by Government with the aforesaid company; and

(d) whether any scheme of manufacture of such rigs in India is also contemplated ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Export of H. M. T. Watches

4143. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether all the watches manufactured by the Hindustan Machine Tools cannot meet the requirements of the domestic market at present;

(b) whether watches manufactured by the Hindustan Machine Tools are also exported;

(c) if so, whether these watches compare favourably in foreign market; and

(d) if so, the number of H.M.T. watches exported and the names of the countries to which they are exported ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The watches have been well received for quality and performance.

(d) During 1966-67, 72 watches were exported to U.S.A., Canada. U.K., West Germany, Norway, Holand, Uganda, Kenya, Kuwait and New-Zealand.

Prices of Indian Steel in Turkey

4144. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian steel is selling at lower rates in Turkey as compared to the steel of other countries;

(b) whether it is due to the inferior quality of Indian steel or due to the lower cost of production as compared to that of other countries; and

(c) the cost of production of Indian steel per tone as compared to that of Western Countries ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) No steel has so far been exported to Turkey from India.

(b) Does not arise.

(c) The cost of production is not generally divulged by producers,

Export of Buttons

4145. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of centres in our country from which M.O.P. buttons are exported, the quantity of these exports, names of the countries to which they are exported and the amount of foreign exchange earned therefrom during 1966-67;

(b) whether the amount of foreign exchange earned through the export of M.O.P. buttons has gone down due to decrease in production; and

(c) if so, the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली से विशाखापत्तनम् को सीधी गाड़ी

4146. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से विशाखापत्तनम को एक सीधी गाड़ी अथवा एक सीधा डिब्बा चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कब तक अमल किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे उद्योगों के लिये मशीनें और सांचे

4147. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मशीनों और सांचों के मूल्य की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये अपेक्षित मशीनों और सांचों का मूल्य अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि देशी मशीनी पुर्जों के मूल्यों में काफी स्पर्धा है और बहुत से पुर्जे सस्ते मिलते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमदाबाद और कलोल के बीच मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के चलने का समय

4148. श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद और कलोल (छोटी लाइन) के बीच दुहरी रेलवे लाइन है, मेल/एक्सप्रेस तथा सवारी गाड़ियों को इन दो स्टेशनों के बीच की केवल 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्रमशः 43 मिनट और 65 मिनट लगते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले आठ वर्षों से दुहरी लाइन की व्यवस्था करने के बाद भी इन गाड़ियों द्वारा यह दूरी तय करने का समय कम नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस समय को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अहमदाबाद-कलोल (मीटर लाइन) खण्ड पर डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन समय 41 मिनट से लेकर 52 मिनट तक और सवारी गाड़ियों का 45 मिनट से 80 मिनट तक है।

(ख) और (ग) अक्टूबर, 1956 से अप्रैल, 1967 के बीच इस खण्ड पर चलने वाली गाड़ियों का चालन-समय उत्तरोत्तर 5 मिनट से 21 मिनट तक कम किया गया है। रेल पथ और कर्षण की वर्तमान स्थिति में इस समय गाड़ियों के चालन-समय को कम करने की गुंजाइश नहीं है। कुछ स्टेशनों पर ठहराया जाना बन्द करके चालन-समय घटाना भी व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वर्तमान उपयोगकर्त्ताओं को असुविधा होगी।

पाटन और भिलाड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन

4149. श्री ब० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में पाटन (नैरो गेज) और मिलाड रेलवे स्टेशनों को एक रेलवे लाइन के द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या उपरोक्त रेलवे लाइन के लिये उत्तर गुजरात की जनता की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिससे कि रानावाओ रेलवे स्टेशन के रास्ते पश्चिमी राजस्थान को सीधा मार्ग बन जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (घ) मिलडी और मेहसाना-पाटन-मेत्राना रोड सैक्शन के एक स्टेशन वागरोड (20 किलोमीटर) के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिये केवल प्रारम्भिक जांच-पड़ताल की जा रही है। इस रेल सम्पर्क के बन जाने से भिलडी और पाटन के बीच रेल सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

(ग) जी, हां।

Conversion of Yeotmal-Ellichpur N. G. Line into B. G.

4150. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have finalised any scheme for the conversion of Yeotmal-Ellichpur via Murtazapur narrow-gauge line into broad gauge line;

(b) whether the scheme has been included in the Fourth Five Year Plan ;and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. This is a line owned by a private Company though worked under a contract by the Government Railway. There is therefore no question of finalising any scheme of conversion to Broad Gauge.

(b) and (c) Do not arise.

Production of handloom cloth in Maharashtra

4151. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the total handloom cloth produced in Maharashtra during 1966-67;

(b) the total production of cotton cloth during the same period; and

(c) the total amount sanctioned to Maharashtra for the development of handloom industry in the State during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) 7,305 Million metres.

(c) Rs. 13.18 lakhs.

Railway Porters

4152. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Railways be pleased to state -

(a) whether a deputation of the National Federation of Railway Porters and Vendors met the Union Deputy Railway Minister on the 16th June, 1967;

(b) if so, the nature of representations made by them; and

(c) the action taken in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

मैसर्स नानक चन्द शादीराम

4153. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 2 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 646 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स नानकचन्द शादीराम नामक फर्म द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील पर इस बीच निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निचले न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड की पुष्टि की गई है या उसे बढ़ा दिया गया है; और

(ग) यदि इस अपील का अभी फैसला नहीं हुआ है, तो क्या केन्द्र ने नई मद्रास सरकार को इन कानूनी कार्यवाहियों को तेजी से चलाने की सलाह दी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

पूर्व और दक्षिण–पूर्व रेलवे में डीजल तेल की खपत

4154. श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेंन्डीज :**

क्या रेलवे मन्त्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व और दक्षिण–पूर्व रेलवे में डीजल तेल की कुल कितनी खपत है ;

(ख) इसमें से कितना डीजल तेल आयात किया जाता है; और

(ग) इस आयात का विदेशी मुद्रा में मूल्य कितना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है सभा-पटल पर रखा जाता हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 860/67**]

(ख) और (ग) समूचे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीज़ल तेल का आयात किया गया था । रेलों के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

बिस्कुट उद्योग के लिये आयात किये जाने वाले सामान का अंश

4155. श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिस्कुट उद्योग ने पिछले बारह महीनों में कुल कितने मूल्य का निर्यात किया;

(ख) इसी अवधि में बिस्कुट निर्माताओं को कुल कितने मूल्य का आयात करने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में बिस्कुट उद्योग के लिये आयात किये जाने वाले सामान में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में निर्मित सामान का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966–67 में (फरवरी, 1967 तक) आयात किये गये बिस्कुटों का मूल्य 27.29 लाख रुपये है ।

(ख) बिस्कुट निर्माताओं को कच्चे माल के रूप में कुल 18 लाख रुपये के मूल्य के आयात की अनुमति दी गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बिस्कुटों में आयात किये गये माल का अंश मुश्किल से 2 से 3 प्रतिशत है। बिस्कुट उद्योग दूध पाउडर, पैक करने के सामान तथा प्रतिआक्सीकारक (ऐंटी आक्सीडेंट) पदार्थ ही आवश्यक कच्चे माल के रूप में आयात करता है। देश के विभिन्न भागों में दूध पाउडर बनाने के लिये पर्याप्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। इन योजनाओं की कार्यान्विति के बाद आयात किया जाने वाला कच्चा माल यहाँ पर बनाना सम्भव हो सकेगा। पैक करने का अधिकतर सामान जैसे ग्रीज-प्रूफ कागज, सेलोफेन कागज आदि ज्यादातर देश में ही बनाया जाता है। कागज निर्माता अन्य किस्म की पैकिंग सामग्री का भी जो इस समय आयात की जाती है निर्माण करेंगे।

Clash Near New Hati Railway Yard (Sealdah Section)

4156. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Constables of the Railway Security Police were injured in a clash with an armed gang of persons while breaking wagons near new Hati Yard on the Sealdah Section of the Eastern Railway at a distance of 30 miles from Calcutta ; and

(b) if so, the numder of persons against whom action has been taken in this connection and the nature of action taken ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a)-Yes. One Senior Rakshak and one Rakshak of the Railway Protection Force received injuries during the encounter with criminals.

(b)-Three criminals were arrested and have since been released on bail. The case is still under police investigation.

Export of Trucks

4157. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India exported Tipper trucks to some European countries :

(b) the number of trucks exported since January, 1966, the names of countries to which these were exported and the foreign exchange earned thereby;

(c) whether there is a demand of Tipper trucks in some other countries alsoe ; and

(d) if so, the steps taken to meet the demand ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes. Sir.

(b) 70 Tipper Trucks exported to Bulgaria from Mach, 1967 to 20th June, 1967. This earned for the country approximately Rs. 28 lakhs (f. o. b.).

(c) Being explored.

(d) No difficulty is apprehended in arranging supply to meet the likely demand.

Jeep-Train Collision between Jhansi and Karari Stations

4158. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of Railways be Pleased to state :

(a) whether it is a fact that three persons died as a result of a collision between a Jeep and a goods train at a Railway crossing between Jhansi and Karari Railway Stations on the Central Railway, as reported in the Hindustan dated the 7th April, 1967 ;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the action taken by Government in that regard.

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Yes. A goods train collided with a jeep belonging to Fisheries Corporation, Jhansi at the unmanned level crossing between Jhansi and karari on 1. 4. 1967, as a result of which three occupants of the jeep were killed and one was grievously injured.

(b) The accident was due to the lapse of the driver of the jeep who failed to take necessary precaution while crossing the unmanned level crossing.

(c) Since the defaulting jeep driver died in the accident no action can be taken against him.

Robbery on Tissua Railway Station

4159. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 279 on the 31st March, 1967 and state :

(a) whether any member of the gang of dacoits which committed robbery on Tissua railway station near Bareilly on the 9th March, 1967 has been apprehended ;

(b) whether the stolen property has also been recovered on their disclosure ; and

(c) if so. the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Two accused have so far been arrested and they are awaiting identification proceeding.

(b) Not yet. The police investigation is in progress.

(c) Does not arise.

Import of Cloves, Black Pepper and Dry Fruits

4160. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal`:

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of cloves, black pepper and dry fruits for which import licences were issued during the last five years, State-wise and the names of the countries from where these articles were imported;

(b) the quantity of cardamom cloves, black pepper and dry fruits exported to the foreign countries and the amount of foreign exchange earned as a result thereof : and

(c) the names of the countries to which these articles were exported ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Import Licences are issued with value as limiting factor and not the quantity. Import Licensing statistics are also not maintained State-wise but for the country as a whole. The value of licences issued for dry-fruits, Black pepper and cloves during last five years are given in the statement No. I. Another statement No. II showing the countries from which these articles were imported is laid on the table of the Houese **[Placed in library, See No. LT--861/67]**

(b) and (c) : Statement showing the quantity and value of export of cardamoms, Cloves, Black pepper and dry fruits during the year 1962-63 to 1966-67 (April to February, 1967) is laid on the table of the house **[Placed in libray, See No. L.T-861/67]**

निर्यात संवर्द्धन परिषदें

4161. श्री हु० प० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक कितनी निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित की गई हैं ;

(ख) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद कोई ऐसी परिषद् स्थापित की गई है ;

(ग) क्या कुछ परिषदों ने विदेशों में कुछ चुने हुए बाजारों में शाखा कार्यालय खोले हैं अथवा संवाददाता नियुक्त किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे कैसा कार्य कर रही है ;

(ङ) देश में निर्यात-गृह कैसा कार्य कर रहे हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा इन निर्यात-गृहों को मान्यता देने की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में अब तक 19 निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित की गई हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ;

(घ) कुछ चुनी हुई विदेशी मंडियों में शाखा कार्यालय या कुछ निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा नियुक्त किये गये संवाददाता उन उत्पादों के लिये जिनसे उनका संबंध होता है विदेशों में निर्यात के अवसर उत्पन्न करने या उनकी सूचना देने में सहायता करते हैं । यह बताया गया है कि वे सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं ।

(ङ) सरकार निर्यात गृहों की कार्य प्रणाली का विस्तार से निरीक्षण नहीं करती है । फिर भी जहां कहीं सरकार से मान्यता या सुविधाएं मांगी जाती हैं संबंधित निर्यात गृह को निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है जिनके पालन न किये जाने पर मान्यता वापिस ली जा सकती है ।

(च) निर्यात गृहों को मान्यता देने सम्बन्धी पुनरीक्षित नीति की घोषणा सितम्बर, 1965 में की गई थी । बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था करना

4162. श्री यशपाल सिंह :
श्री रवि राय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में नया मंत्रालय के बनने के बाद कितने रेलवे फाटकों (लेवल क्रोसिंगस) पर आदमी रखे गये हैं; और

(ख) चालू वर्ष में तत्सम्बन्धी कार्य-क्रम क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे में बिना चौकीदार के फाटकों पर चौकीदार रखने के बारे में प्रगति का त्रैमासिक आधार पर लेखा रखा जाता है । 1 जनवरी, 1967 से 31 मार्च, 1967 की अवधि में बिना चौकीदार के लगभग 44 फाटकों पर चौकीदार रखे गये हैं और 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की एक वर्ष की अवधि में 157 फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था की गई ।

(ख) 1967-68 में चौकीदार की व्यवस्था करने हेतु अस्थायी तौर पर लगभग 577 फाटक चुने गये हैं । वास्तविक कार्यक्रम तभी तैयार किया जायेगा जब संबंधित राज्य सरकार किसी प्रस्ताव के बारे में अपने हिस्से के व्यय को वहन करने की स्वीकृति सहित अपनी स्वीकृति भेज देगी जैसा कि नियमों के अन्तर्गत आवश्यक है ।

मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग

4163. श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के भारी स्टाक जमा हो जाने के कारण मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस उद्योग को बचाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कोई प्रार्थना की है ;

(ग) क्या इस संकट के कारणों का पता लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो संकट के कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मध्य प्रदेश के कोयला–मुहानों पर कोयले के संचयों में थोड़ी सी कमी–बेशी हुई है। तथापि मासिक उत्पादन तथा संचयों का अनुपात समस्त भारत की औसत से बहुत नीचे है तथा उद्योग को किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रुटिपूर्ण रेल की पटरियां

4164. श्री यशपाल सिंह :
श्री जॉर्ज फरनेंडीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में रेल की पटरियां बनाने में प्रयुक्त होने वाले कार्बन तथा मैंगनीज की मात्रा में कमी के सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा नियंत्रण प्रयोगशाला के सीनियर केमिस्ट के विश्लेषण प्रतिवेदन के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला है ?

रेलवे मन्त्री (श्री के० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 862/67]**

लाइसेंस जारी करना

4165. श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल में घोषित की गई उदार नीति के अन्तर्गत कितने औद्योगिक कारखानों को लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) इस नीति के अन्तर्गत कितने पक्षों को कोई लाइसेंस नहीं दिये गये और उसके क्या कारण हैं ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) अवमूल्यन के बाद घोषित की गई आयात नीति तथा 1967–68 की लाल पुस्तक में कच्चे माल, पुर्जों आदि के आयात के लिये लाइसेंस देने की व्यवस्था है ताकि छोटे तथा बड़े प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में अधिकतम उत्पादन हो सके । इन उद्योगों के एककों को भी पहले के लाइसेंसों के प्रयोग किये जाने के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंसों के लिये लाइसेंस प्राधिकारी के पास जाने की अनुमति होगी ।

उन उद्योगों के बारे में भी जो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में नहीं आती हैं 1965–66 की तुलना में आयात को कुछ उदार कर दिया गया है । वर्तमान नीति के अनुसार ये एकक भी पिछले लाइसेंसो के प्रयोग का प्रमाण देकर आगे लाइसेंस के लिये लाइसेंस प्राधिकार को लिख सकते हैं । परन्तु उनके मामले में विदेशी मुद्रा का आवंटन विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

अवमूल्यन के बाद से तथा 3 जून, 1967 तक प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में छोटे तथा बड़े वास्तविक प्रयोक्ताओं को कुल 11, 168 लाइसेंस दिये गये थे जिनका मूल्य 375 करोड़ रुपये है ।

ओखला और बादली औद्योगिक बस्तियां

4166. श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला और बादली औद्योगिक बस्तियों में से कौनसी औद्योगिक बस्ती अधिक अच्छी तरह कार्य कर रही है तथा अधिक सफल रही है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात का कारण जानने का प्रयत्न किया है कि दूसरी बस्ती उतनी अच्छी तरह तथा सफलता से कार्य क्यों नहीं कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दोनों औद्योगिक बस्तियां खूब अच्छे ढ़ंग से कार्य कर रही हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांवों में उद्योगों की स्थापना

4167. श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 में सरकार द्वारा घोषित की गई गांवों में उद्योगों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों को कच्चे माल के नियतन के सम्बन्ध में विशेष प्राथमिकता दी जानी थी ; और

(ख) यदि हां, तो बादली औद्योगिक बस्ती में स्थित कारखानों को क्या प्राथमिकता तथा वरीयता दी गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) ; (क) जी हां। 1964-65 (1965-66 नहीं) में ग्राम औद्योगीकरण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित चार श्रेणियों के एककों को कच्चा माल आवंटित किया जाना था :—

(एक) 15,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों तथा गावों में स्थित औद्योगिक बस्तियों तथा अर्ध-औद्योगिक बस्तियों के एकक ;

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंचायत समिति उद्योग ;

(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे सामान्य सुविधा केन्द्र ;

(चार) 45 चुने हुए क्षेत्रों में योजना आयोग द्वारा चलाए गये ग्राम औद्योगीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के एकक ।

कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिये सी० सी० आई० एण्ड ई० अधिकतम सीमा-राशि में अबाध विदेशी मुद्रा में से 50 लाख रुपये इस प्रयोजन के लिये रखे गये थे । इसी प्रकार विभिन्न किस्मों के इस्पात के आयात के लिये 25 लाख रुपये की अधिकतम राशि रखी गयी थी ।

(ख) बादली औद्योगिक बस्ती के एककों से दिल्ली प्रशासन को कच्चे माल । पुर्जों के आवंटन के लिये चार आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे । सी० सी० आई० एण्ड ई० द्वारा वे विधिवत रूप से स्वीकार कर लिये गये थे और आयात लाइसेंस दे दिये गये थे ।

भारतीय बन्दरगाहों से पुनर्निर्यात

4168. श्री दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में भारतीय बन्दरगाहों से कितने मूल्य के माल का पुनर्निर्यात किया गया ; और

(ख) 1965-66 के आकड़ों की तुलना में यह कैसा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1966-67 'अप्रैल-फरवरी' में भारतीय बन्दरगाहों से 45.30 लाख डालर के मूल्य के माल का पुनर्निर्यात किया गया जबकि 1965-66 की इसी अवधि में 80.53 लाख डालर के मूल्य के माल का पुनर्निर्यात किया गया ।

गोआ के बन्दरगाहों से निर्यात

4169. श्री दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के बन्दरगाहों से निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1965–66 और 1966–67 में गोआ बन्दरगाह से निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०–863/67]**

आशय-पत्र जारी करना

4170. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966–67 में कितने आशय-पत्र जारी किये गये और इससे उद्योग की शीघ्र स्थापना के काम में कितनी सहायता मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 1966-67 में 306 पत्र जारी किये गये थे। यह औद्योगिक क्षमता के मोचन-निक्षेप को दूर करने में सहायक रहे हैं। यदि आशय पत्र जारी किये जाने के बाद कोई पार्टी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिये नियत अवधि में कारगर कदम नहीं उठाती और वैधता की अवधि को बढ़ाने के लिये कोई औचित्य भी सिद्ध नहीं करती, तो आशय-पत्र को रद्द कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से औद्योगिक क्षमता अन्य उद्यमों को दिये जाने के लिये मिलने में सहायता मिलती है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

4171. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में उद्योगों की स्थापना के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) उनमें कितनी पूंजी लगने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966–67 में उद्योगों की स्थापना के लिये 93 लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Prices of Export Commodities

4172. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is exporting certain articles at prices lower than their cost;

(b) if so, the names of such articles and the respective countries to which they are exported; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : Government does not maintain statistics of cost of production, However, individual exporters may sometimes be exporting at prices prevailing in the international market which are lower than prices in our domestic market.

(b) It would not be possible to compile this information from available statistics as costs very from product to product and unit to unit,

(c) The reasons would be peculiar to each producer and exporter and it would not be possible to compile this information.

कांगड़ा और मंडी में चाय बागान

4173. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा और मंडी (हिमाचल प्रदेश) के चाय बागानों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब प्रकाशित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वाणिज्य मंत्रालय अथवा चाय बोर्ड ने कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयातित मोटर गाड़ियां

4174. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** :
श्री गं० चं० दीक्षित :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री लाखन लाल गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम से आयातित इस्तेमाली मोटर-गाड़ियों के खरीदने के मामले में राज्य सरकारों को इन मोटर-गाड़ियों को खरीदने से पहले पर्यटन विभाग के महानिदेशक की सहमति प्राप्त करनी पड़ती है;

(ख) क्या विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए राज्य व्यापार निगम से ऐसी ही कारें खरीदने के मामले में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की सहमति भी लेनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के बारे में निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम तथा स्वतंत्र हैं, इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य नीति के रूप में यह निर्णय किया गया है कि 10,000 रुपये अथवा कम मूल्य (दी गई अथवा देय सीमा-शुल्क की राशि को मिलाकर) की आयातित कारें राज्य सरकारों को बेची जा सकती हैं लेकिन इस मूल्य से अधिक की कारें केन्द्रीय सरकार को ऐसी कार की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में संतुष्ट करने के बाद ही बेची जानी चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

रेलवे मन्त्रालय में मितव्ययिता

4175. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने मंत्रालय को प्रक्रियाओं में सुधार करके राजपत्रित अधिकारियों की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है ताकि कुछ मितव्ययिता की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) पुनर्विचार के परिणाम स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि रेलवे बोर्ड के कार्यालय में छः संयुक्त निदेशकों के पद, उप निदेशकों/सहायक निदेशकों आदि के आठ पद तथा अनुभाग अधिकारियों के चौदह पद समाप्त कर दिये जायें।

धोतियों का कपड़ा बनाना

4176. श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रमुख औद्योगिक कम्पनी समूह द्वारा धोतियों का कपड़ा बनाने में अवैध ढंग से किये गये परिवर्तन के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस औद्योगिक कम्पनी समूह का नाम क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) ये समाचार मिले हैं कि हरियाणा में भिवानी की टैक्नॉलॉजी इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्सटाइल्स ने नियंत्रण के प्रयोजनों के न्यूनतम निर्धारित लम्बाई से कम की धोतियां और साड़ियां बनाई है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

प्रबन्ध अभिकरण

4177. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें गत तीन महीनों में समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरणों के कार्य की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 1 मार्च, से 15 जून 1967 तक की अवधि में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 19 मामलों में प्रबन्ध अभिकरणों के कार्य की अवधि बढ़ाने को अनुमति कर दी गई।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में मकान किराया भत्ता

4178. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई : श्री ख० प्रधानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को कोई मकान किराया भत्ता दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 864/67]

कपड़े का निर्यात

4179. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई : श्री ख० प्रधानी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ महीनों में सूती कपड़े के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अवमूल्यन किये जाने पर भी भारतीय सूती कपड़े के अप्रतियोगी मूल्य।

(ग) व्यापार तथा उद्योग के परामर्श से उपायों पर विचार किया जा रहा है।

हथकरघा कपड़े का निर्यात

4180. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में हथकरघा कपड़ा निर्यात संवर्धन संगठन ने स्वयं, जिसमें इसकी सहयोगी संस्थाएं शामिल नहीं हैं; कितने हथकरघा कपड़े का निर्यात किया; और

(ख) इसी अवधि में इसकी सहयोगी व्यापारी संस्थाओं को कितना हथकरघा कपड़ा बेचा गया, ताकि वे आये हुए क्रयादेशों के अनुसार कपड़े का निर्यात कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रायल में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) हस्त-शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम ने मार्च-अप्रैल, 1967 में 1,42,351.66 रुपये के मूल्य के हथकरघा कपड़े का निर्यात किया। निगम ने इसी अवधि में अपने व्यापारिक सहयोगियों को 63,264.49 के मूल्य का हथकरघा कपड़ा बेचा। इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन व्यापारिक सहयोगियों ने निगम से खरीदे गये माल में से वास्तव में कितने माल का निर्यात किया।

उड़ीसा और राजस्थान की कोयले की आवश्यकता

4181. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत तीन महीनों में उड़ीसा और राजस्थान ने विभिन्न किस्मों के कोयले की कितनी-कितनी मांग की; और

(ख) मांग कहां तक पूरी की गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोयले की मांग के श्रेणीवार आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। तथापि 1967 के लिये उड़ीसा और राजस्थान

राज्यों की कोयले की नियंत्रित श्रेणियों (एच० एच०, श्रेणी 1 तथा इससे ऊपर की श्रेणी) की आवंटित मांगों के आंकड़ों का प्राथमिकतावार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 865/67]**

(ख) राज्य सरकारों की समस्त मांगे पूरी की गई।

उड़ीसा में औद्योगिक कारखाने

4182. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उड़ीसा में कितने और कौन-कौन से औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) उक्त अवधि में इस प्रायोजन के लिये उड़ीसा को वास्तव में कितनी सहायता देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सम्बलपुर जिले में बाढगढ़ में एक सीमेंट कारखाने का निर्माण 1967-68 में पूरा हो गया है। अन्य परियोजनाएं, जो राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है लेकिन 1967-68 में पूरी नहीं हो सकें, इस प्रकार हैं :–

(1) कलिंग आयरन वर्क्स
(2) रि–रौलिंग मिल्स
(3) केबल परियोजना
(4) फैरो–क्रोम परियोजना
(5) तालचेर उद्योग समूह

(ख) राज्य योजना के लिये कुल मिलाकर सहायता के रूप में वर्ष 1967-68 में राज्य सरकार को 26 करोड़ रुपए की राशि अस्थाई रूप से नियत की गई है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

4183. श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक ओरांओं :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के प्रधान ने उनके मंत्रालय को उन व्यापारिक फर्मों की सूची भेजी है, जिनके साथ उसके व्यावसायिक सम्बन्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन फर्मों में निगम के प्रधान के इस समय कितने हिस्से है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं । समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रधान के लिये इन व्यापारिक फर्मों की सूची सरकार को भेजना आवश्यक नहीं है, जिनके साथ उनके सम्बन्ध हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रांची स्थित हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन

4184. श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक ओराओं :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में प्रत्येक परियोजना का अनुमानित पूंजी परिव्यय कितना था; और

(ख) अब तक उन कामों पर कितना कितना वास्तविक पूंजी परिव्यय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में परियोजनावार अनुमानित पूंजी परिव्यय तथा 31 मार्च, 1967 तक वास्तविक परिव्यय इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	पूंजी परिव्यय	31 मार्च, 1967 तक वास्तविक परिव्यय
(1) हैवी मशीन बिलडिंग प्लांट (स्ट्रक्चरल फैबरीकेशन शॉप सहित)	4797	4419
(2) हैवी मशीन टूल्स प्लांट	2446	1338
(3) फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	11120	6822

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

4185. श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक ओराओं :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के उत्पादन लक्ष्य क्या थे और मार्च, 1967 तक कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) क्या उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के कारखानों के उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार हैं :–

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

	लक्ष्य		वास्तविक उत्पादन	
	मीट्रिक टन	मूल्य (लाख रुपयों में)	मीट्रिक टन	मूल्य (लाख रुपयों में)
1963–64	600	10.9	640.8	11.61
1964–65	7798.5	212.5	3208.3	72.11
1965–66	9451.5	344.0	10980.5	285.4
1966–67	19519.0	749.5	14307.4 (अस्थायी)	471.4

फाउंड्री फोर्ज प्लांट

	लक्ष्य		वास्तविक उत्पादन	
	मीट्रिक टन	मूल्य (लाख रुपयों में)	मीट्रिक टन	मूल्य (लाख रुपयों में)
1964–65	1322	36.2	952.38	23.34
1965–66	2686	61.56	2466.00	48.23
1966–67	7181	155.61	4137.00 (अस्थायी)	77.74

हैवी मशीन टूल्स प्लांट

1966–67 में 12 मशीनों (33.32 लाख रुपये के मूल्य की) के कार्यक्रम के विरुद्ध 7 मशीनें, जिनका मूल्य 11.55 लाख रुपये का, तैयार की गई ।

उत्पादन में कमी के कारण निम्नलिखित थे :–

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

उत्पादन पर प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण आवश्यक मात्रा में कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स का न मिलना था ।

फाउंड्री फोर्ज प्लांट

(1) पर्याप्त मोलडिंग एरिया का नहीं मिलना ।

(2) वाटर लाइन और पुर्नजिवित (रिक्यूपरेटर) का खराब हो जाना ।

(3) मिश्रित धातु प्राप्त करने में कठिनाई ।

हैवी मशीन टूल्स प्लांट

उत्पादन अक्टूबर, 1966 में आरम्भ हुआ था । कमी का कारण प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं ।

Export of Cycles

4186. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of cycles exported during the past two years;

(b) the names of countries to which they were exported and the names of the Indian companies which exported them;

(c) the extent of profit earned or loss sustained by exporting these cycles; and

(d) whether Government propose to take some decision in respect of the loss sustained by the export of cycles ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Liberary See No. LT-866/67]

(c) and (d) No information is available about the extent of profit earned or loss sustained in individual cases as the amount would differ from individual to individual and Contract to contract, Government is, however, already allowing cash assistance of 25% of the f.o.b. value of exports on an average basis.

Use of Hindi In Railway

4187. Shri Vishwanath Pandey : Will the Minister of Railway be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the use of Hindi in his Ministry as well as in various Railway Zones;

(b) the time by which work regarding switch over to Hindi would be completed in his Ministry as wall as in various Railway Zones; and

(c) the number of employees in his Ministry as well as in Railway Zones who do not know Hindi ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) :(a) and (b) Based on Governments, general policy, steps have been taken for gradual introduction of Hindi in Railway offices. It is not, however, possible to indicate the time by which switch-over to Hindi will be Completed.

(c)	Ministry of Railways	—	461*
	Zonal Railways	—	1,77,967*

*These exclude Class IV staff, industrial establishments, work-charged staff and employees who were 45 years of age or above as on 1.1.1961, for whom in-service training in Hindi is not obligatory.

Lalgarh Hospital in Bikaner Division

4188. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the time by which health services would be started in the newly constructed Lalgarh Hospital in Bikaner Division of the Northern Railway;

(b) the number of Doctors, Nurses, Compounders and Midwives to be appointed there; and

(c) the total number of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the number of posts filled and the number of posts remaining vacant so far ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) In the newly constructed Lalgarh Hospital of Bikaner Division of Northern Railway, the Chest Clinic started functioning from 1.4.66 and the General Hospital from 11.4.67.

(b) The No. of posts sanctioned for this Hospital are as follows :

(i)	Medical Officers	6
(ii)	Nurses	15
(iii)	Pharmacists	5
(iv)	Midwives	1

(c) Reservations for Scheduled Castes Tribes are not made on Divisional or Hospital basis but for the Medical Cadre of the Railway as a whole. However, one post each in the category of Medical Officers and Pharmacists is at present held by Scheduled Castes.

तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन

4189. **श्री प० गोपालन :**　　　　**श्री उमानाथ :**
श्री चक्रपाणि :　　　　**श्री नम्बियार :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिये कितने और किन-किन वर्षों में सर्वेक्षण किये गये थे;

(घ) पिछले सर्वेक्षण प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सर्वेक्षण पर कुल कितना व्यय हुआ ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) चौथी योजना में नई लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) अभिदर्शश (किकनेसैंस) इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पहले 1901-1902 में और बाद में 1956-57 में किये गये थे।

(घ) लाइन की लम्बाई 147 मील होगी और 11.62 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान था। इस लाइन के घाटे में चलने की आशा थी।

(ङ) 1956-57 में सर्वेक्षण पर 1,88,366 रुपए खर्च किये गये थे।

केरल में नारियल जटा उद्योग

4190. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा-उद्योग के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस उद्योग में यन्त्रीकृत प्रक्रिया आरम्भ हो गई है;

(ग) इस समय इस उद्योग में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं; और

(घ) 1960 में कुल कितने व्यक्ति कार्य करते थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है।

(ग) लगभग 5-6 लाख।

(ख) लगभग $4\frac{1}{2}$-5 लाख।

विवरण

(क) केरल तथा देश के अन्य भागों में भी नारियल जटा के उद्योग के विकास के लिये नारियल जटा बोर्ड द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम अधोलिखित है :-

(1) विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय किये गये हैं। केरल में नारियल जटा उद्योग निर्यात-प्रधान है और इसकी अर्थ-व्यवस्था का निर्यात-मांग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। नारियल जटा बोर्ड ने प्रचार कार्य किये हैं जैसे विदेशों में प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेना, प्रचार साहित्य का प्रकाशन, एक वृत्त चित्र का निर्माण आदि।

(2) नारियल जटा और उससे बने पायदानों के लदान से पहले उनका अनिवार्य निरीक्षण की व्यवस्था की गई है।

(3) उत्पादन के त्रिविधिकरण, परम्परागत वस्तुओं के लिये आधुनिक नमूने तैयार करने तथा प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया गया है।

नारियल जटा बोर्ड ने केरल राज्य में एलप्पी में एक राष्ट्रीय नारियल जटा प्रशिक्षण तथा नमूना केन्द्र स्थापित किया है, जिसमें नारियल जटा की वस्तुओं के निर्माण के तरीकों में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह केन्द्र नारियल जटा उत्पादों के लिये नए नमूने भी तैयार करता है और उनका प्रचार भी करता है।

(4) केरल में कलावूर में स्थित बोर्ड का केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्थान नारियल जटा और उसके उत्पादों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं, और मूलभूत प्रायोगिक, दोनों पर अध्ययन कर रहा है। इन अध्ययनों के परिणाम नारियल जटा उद्योग को उपलब्ध किये जाते हैं।

(5) एक विस्तार सेवा स्थापित की गई है; जिसके अन्तर्गत बोर्ड की अनुसंधान संस्थान के अधिकारी नारियल जटा कारखानों का दौरा करते हैं तथा वहां पर तकनीकी राय देते हैं।

(6) भारत में नारियल जटा उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिये नारियल जटा बोर्ड नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और एर्णाकुलम में प्रदर्शन कक्ष तथा बिक्री डिपो चला रहा है। बोर्ड ने नारियल जटा की वस्तुओं की बिक्री के लिये अनेक नगरों ने मान्यता प्राप्त व्यापारी की नियुक्त किये हैं।

(ख) नारियल जटा की चटाइयों के बनाने में हाल में मशीनों का प्रयोग आरम्भ किया गया है। हाल में एक कारखाना स्थापित किया गया है और नारियल जटा बोर्ड स्वयं केरल राज्य में कलावूर में पांच शक्ति चालित करघे वाला एक चटाई निर्माण कारखाना स्थापित किया है, शक्ति चालित करघों से चटाई बनाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में भी शीघ्र ही एक अन्य कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, केरल सहित भारत के अनेक भागों में नारियल से मशीनों द्वारा जटा उतारने तथा रबड़ मिश्रित नारियल जटा उत्पाद बनाने के अनेक कारखाने स्थापित हुए हैं।

गाड़ियों का देरी से चलना

4191. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में विभिन्न रेलों में विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलवे में मुख्य लाइनों तथा ब्रांच लाइनों पर गाड़ियों का देरी से चलना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस स्थिति में सुधार हुआ है अथवा नहीं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) 1965 की तुलना में कुल रेलों में 1966 में सवारी गाड़ियों के समय पर चलने में सुधार हुआ है, और कुछ में अन्य रेलों में गिरावट आई है जैसा कि सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण में बताया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 867/67]

(ग) समय-पाबन्दी अभियान तथा सभी स्तरों पर सवारी गाड़ियों पर कड़ी निगरानी आरम्भ की गई है ?

Platforms on Bhatni Junction

4192. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of platforms on Bhatni Junction on the North-Eastern Railway for the stoppage of passenger trains;

(b) the total number of trains that stop at Bhatni;

(c) whether there is any proposal to increase the number of platforms at the said Railway Station;

(d) whether it is a fact that 278 Down (Barhaj Bazar-Bhatni Jn.) and 72 Down (Varanasi-Bhatni) trains stop at Bhetni Jn. on the places other than platforms; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C, M. Poonacha) : (a) Three,

(b) Thirty two.

(c) No.

(d) Yes.

(e) Two of the three platforms are occupied by main line passenger trains. Reception of 278 Dn and 72 Dn on the third platform line is not operationally convenient at that time. This would, however, be feasible after completion of remodelling of Bhatni junction.

Platform at Turtipar Railway Station

4193. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the level of platform at Turtipar Railway Station on the North Eastern Railway is too low and most of the passengers slip while boarding and detraining from the trains and are injured;

(b) whether Government are contemplating to raise the level of the said platform; and

(c) if so, when, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The existing platform at Turtipar station is a rail level one. No reports of passenger slipping while boarding or getting down from trains and receiving injuries, have however been received.

(b) and (c) Proposal to raise the platform has been included in the current year's Works Programme of the Railway.

अरकोणम इंजीनियरिंग वर्कशाप के परिसर में कंक्रीट की वर्कशाप

4194. श्री सम्बन्धन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरकोणम इंजीनियरिंग वर्कशाप के परिसर में कंक्रीट की वर्कशाप कब आरम्भ की गई थी;

(ख) इस वर्कशाप पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) यह वर्कशाप अब किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) अरकोणम स्थित इंजीनियरी वर्कशाप में कंक्रीट शाप 1944 में एक बहुत छोटे पैमाने पर आरम्भ की गई थी परन्तु 1962 से 1964 तक की अवधि में सामान्य रिमाडलिंग योजना के अन्तर्गत 65,500 रुपये की लागत पर कंक्रीट शॉप को अन्य स्थान पर स्थापित किया गया। कंक्रीट शॉप को 1–7–1966 से बन्द करना पड़ा क्योंकि रेलवे में निर्माण-कार्य में सामान्य रूप से कमी के कारण पर्याप्त काम नहीं था, विशेष रूप से आर० सी० सी० पाइपों का जिसके मुख्य रूप से अधिकांश आर्डर मिलते थे।

अरकोणम इंजीनियरी वर्कशाप

4195. श्री सम्बन्धन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961–62 से 1966–67 तक अरकोणम इंजीनियरी वर्कशाप के लकड़ी के कारखाने में कितना लकड़ी का काम हुआ; और

(ख) बाद के वर्षों में उत्पादन में यदि कोई कमी हुई तो उसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1961-62 से 1966–67 में अरकोणम इंजीनियरी वर्कशाप के लकड़ी के कारखाने में हुए काम का ब्यौरा इस प्रकार है :

1961–62	130 टन चिरी लकड़ी
1962–63	132 ,,
1963–64	139 ,,
1964–65	148 ,,
1965–66	113 ,,
1966–67	78 ,,

(ख) लकड़ी के कारखाने में उत्पादन रेलवे में निर्माण-कार्य कम हो जाने और उसके परिणामस्वरूप लकड़ी की मांग में कमी हो जाने के कारण कम हुआ है।

नेवेली लिग्नाइट निगम

4196. श्री सम्बन्धन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम के लिये अर्जित की गई भूमि का प्रतिकर सभी भूस्वामियों को दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को अन्तिम दल को किस तारीख को प्रति कर दिया गया था तथा प्रतिकर का भुगतान किस प्रकार किया गया था;

(ग) क्या पहले किये गये अनुमानों में संशोधन किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हां, महोदय। लोगों के अन्तिम दल को 22-12-1966 को मुआविजा दिया गया। मुआविजा नकदी के रूप में दिया गया।

(ग) और (घ) हां, महोदय। इन प्रतिवेदनों पर निगम द्वारा प्रचलित कानून के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

बिड़ला ब्रदर्स को औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना

4197. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रोफेसर आर० के० हजारी द्वारा औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने की नीति के बारे में प्रस्तुत किये गये अन्तिम प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद बिड़ला ब्रदर्स को कितने नये औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : प्रोफेसर आर० के० हजारी द्वारा औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने की नीति के बारे में प्रस्तुत किये गये अन्तरिम प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद बिड़ला सार्थ समूह की एक फर्म को एक लाइसेंस दिया गया है।

वन्य पशुओं का निर्यात

4198. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री भगवान दास** :
श्री उमानाथ : **श्री वि० कु० मोदक** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962-63, 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में कितने मूल्य के वन्य पशुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इन पशुओं के निर्यात के सम्बन्ध में बीजक में कम राशि दिखाई जाने के किसी मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने बीजक में दिखाई गई कीमत को विदेशों में ग्राहकों द्वारा वास्तव में दी गई कीमत से मिलाया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क)

1962–63	49,31,602.21 रुपये
1963–64	37,35,785.23 रुपये
1964–65	29,14,929.34 रुपये
1965–66	27,24,062.71 रुपये

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारत के रिजर्व बैंक को, जिसके पास निर्यातकों द्वारा फाइल किये गये जी०आर० प्रपत्र सीमा-शुल्क गृहों द्वारा भेजे जाते हैं, जांच-पड़ताल करने की जरुरत पड़ती है ।

ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेन्ज

4199. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड, कलकत्ता के गठन का ब्योरा क्या है;

(ख) इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसने अपने उद्देश्य को कहां तक पूरा किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ईस्ट इंण्डिया जूट एन्ड हेसियन एक्सचेंज लिमिटेड, कलकत्ता—जूट वस्तु निर्माताओं, जूट गुड्स शिपर्स, जूट वस्तु व्यापारियों, कच्चे जूट व्यापारी तथा दलालों की संस्था है । इस एक्सचेंज का प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड में निहित है और यह निदेशक बोर्ड अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुन लेता है ।

(ख) ईस्ट इण्डिया जूट एन्ड हेसियन एक्सचेंज बनाने का प्रारम्भिक उद्देश्य कच्चे जूट तथा जूट की वस्तुओं में सट्टा बाजार को नियमित तथा नियंत्रित रखने को कहा है । इस एक्सचेंज को यह सुनिश्चित करना होता है कि भिन्न-भिन्न किस्मों के वायदे ठेकों में व्यापार ठोस लाइनों तथा एक्सचेंज के उपनियमों के अनुसार किया गया है । महत्वपूर्ण उपनियमों पर वायदा बाजार आयोग/भारत सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है ।

(ग) इस एक्सचेन्ज ने अपना कार्य अब तक सन्तोषजनक रूप से निभाया है ।

Allotment of Railway Rest/Guest Houses to Non-Officials

4200 Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Rest Houses/Guest Houses have been provided for officers at all important Railway Stations including the Jhajha Station of the Eastern Railway;

(b) whether permission is granted to the Members of Parliament and the Ministers of the States to stay in the said Rest Houses/Guest Houses in time of need;

(c) if so, the reasons why Shri Rama Nand Tiwari, Minister for Police, Bihar State and a Member of Parliament were not allowed to stay there on the occasion of the Zonal Conference of the Workers of loco workshop, Jhajha organised on the 19th May, 1967 although a request to that effect was made by the Reception Committee; and

(d) the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Rest/Guest Honses have been provided at some of the important Railway Stations including Jhajha Station of the Eastern Railway.

(b) Under the extant rules accommodation in Railway Rest Houses can be allotted to non Railway Government Officers (including State Ministers) on tour on Payment of prescribed charges. but not to non Officials including Members of Parliament when their visits are not connected with Railway working.

(c) No written requisition from them for allotment of such accommodation was received by the Eastern Railway authorities. Some person, on behalf of a Reception Committee at Jhajha had verbally approached the Eastern Railway authorities for allotment of Railway Rest House for the visiting M. Ps and Ministers. He, however, did not give any written requisition even though requested for the same. In the circumstances, no further action was taken by the Eastern Railway authorities.

(d) Does not arise in view of reply to (b) and (c).

संयुक्त संयंत्र समिति

4201. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त संयंत्र समिति ने मुख्य उत्पादकों से एक टन पर 1 रुपये के आधार पर अब तक कितनी राशि एकत्र की है; और

(ख) यह राशि किन मदों पर खर्च की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31 मार्च, 1967 तक 134 लाख रुपये समकारी निधि ।

(ख) भाड़ा के घाटे को पूरा करने के लिए 134 लाख रुपयों में से 60 लाख रुपये इस निधि में डाल दिये गये और 46.25 लाख रुपये संयुक्त संयंत्र समिति के खर्च की पूर्ति के लिए दिए गये ।

ओलावाक्कोट क्रिओसोट कारखाना

4202. श्री नायनार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलावाक्कोट (केरल राज्य) के क्रिओसोट कारखाने को बन्द करने का विचार है, जिसके 160 कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इस समूचे कारखाने को बन्द कर दिये जाने की संभावना से रेलवे विभाग ने इसका 50 प्रतिशत कार्य कम कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं। इस कारखाने को बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) काम में कमी केवल अस्थायी तौर पर है और वन विभागों द्वारा जितनी मात्रा में स्लीपरों की सप्लाई करने का वचन दिया था, उतनी मात्रा में सप्लाई न किये जाने के कारण है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

रूरकेला इस्पात कारखाने के कर्मचारी

4203. श्री दे० अमात : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला के सब श्रेणियों के वेतन-भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी स्थानीय व्यक्ति हैं तथा कुल कर्मचारियों में उनकी प्रतिशतता कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस समय राउरकेला इस्पात कारखाने की वेतनावलि में 28,494 कर्मचारी हैं। इनमें उर्वरक कारखाने और रक्षित खानों में काम करने वाले कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

(ख) स्थानीय कर्मचारियों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते।

भारत ऐल्यूमिनियम कम्पनी

4204. श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरम :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी में अब तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०, नई दिल्ली द्वारा कोरबा (म०प्र०) और कोयना (महाराष्ट्र) एल्यूमिनियम परियोजनाओं को पूरा करने के लिये निम्न उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं :

1. प्रस्तावित प्लांटों को अयस्क देने के लिये स्फोदिज निक्षेपों के विस्तृत अन्वेषण पूर्ण हो गये हैं तथा प्लांटों को आवश्यक बिजली प्रदान करने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों से बात चीत चल रही है।

2. एल्यूमिना अवस्था तक की कोरबा परियोजना के प्राक्कलनों की स्वीकृति के लिये तथा एल्यूमिना प्लांट को स्थापित करने और शुरू करने हेतु हंगेरी के मैसर्स चैमोकाम्पलैक्स के साथ परामर्श सम्बन्धी समझौते के अनुमोदन के लिये भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। कोरबा प्रद्रावक के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा एल्यूमिनियम सीमिस के निर्माण की सुविधाओं के विषय में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी रूस के मैसर्स तजाजप्रोमएक्सपोर्ट के साथ एक ठेका कर रही है।

3. जहां तक कोयना परियोजना का सम्बन्ध है, परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का परीक्षण किया जा चुका है तथा योजना व उस पर आने वाली लागत के अनुमानों पर सरकार विचार कर रही है।

निर्यात में वृद्धि

4205. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 से 1966 तक की अवधि में पिछले वर्षों की तुलना में निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, और उसके क्या कारण है;

(ख) निर्यात से होने वाली आय तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अवमूल्यन के पश्चात् किन-किन देशों को हमारा निर्यात बढ़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1956–67 से लेकर 1966–67 तक की अवधि में भारत के निर्यातों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 868/67]** मुख्यतः सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये संवर्द्धन-उपायों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष निर्यात में वृद्धि होती रही है। सिवाय वर्ष 1965–66 और 1966–67 जबकि निर्यातों में गिरावट आई है।

(ख) अवमूल्यन का निर्यातों पर तुरन्त प्रभाव पड़ा वह कुछ अनिश्चित सा था लेकिन (निर्यात स्थिति का गौर से अवलोकन करने पर पता लगता है कि) निर्यातों में उत्तरोत्तर धीरे-धीरे वृद्धि होने लगी है और भविष्य आशापूर्ण दिखाई देता है। अवमूल्यन के पश्चात् निर्यातों की प्रवृत्ति का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जो यह बताता है कि जून से लेकर अगस्त 1966 की अवधि में–पिछले वर्ष में उसी अवधि की तुलना

में 16.8 प्रतिशत निर्यात गिर गये थे। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 868/67]** अगले तीन महीनों में (सितम्बर–नवम्बर) निर्यातों में यह गिरावट घटकर 10.5 प्रतिशत तक आ गई थी। इसके अगले तीन महीनों में (दिसम्बर, 1966–फरवरी, 1967), निर्यातों में गिरावट और कम होकर 5.4 प्रतिशत रह गई थी। मार्च–मई, 1967 के दौरान इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आ गया और 2.2 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 1966–67 में अप्रैल–मई महीनों की तुलना में 1967–68 में उन्हीं दो महीनों (अप्रैल-मई) में यह वृद्धि बढ़कर 8 प्रतिशत तक हो गई है।

वर्ष 1965–66 की तुलना में 1966–67 में किये गये कुल निर्यातों तथा आयातों का ब्यौरा देने वाला एक अन्य विवरण भी सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 868/67]**

(ग) जून-फरवरी, 1965–66 की तुलना में जून-फरवरी, 1966–67 के दौरान जिन देशों को निर्यात अधिक किया गया है, उनके नाम बताने वाला एक अन्य विवरण (विवरण 4) सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 868/67]**

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

4206. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों को किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी गई; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उड़ीसा राज्य में लघु उद्योगों के संवर्द्धन तथा विकास के लिये केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन, कटक स्थित लघु उद्योग सेवा संस्था तथा उसके क्षेत्राधिकार के भीतर विस्तार केन्द्र के माध्यम से यथासंभव सहायता पहुँचा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ ये चीजें शामिल हैं :

1. आधुनिक तथा समुचित तकनीकी प्रक्रियाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह।

2. आधुनिक योजनाओं, डिजायनों, ड्राविंग तथा तकनीकी बुलेटिनों का तैयार करना।

3. उत्पादन प्रबन्ध, वित्तीय लेखा-जोखा, लागत नियंत्रण तथा विपणन प्रबन्ध जैसे विषयों पर मैनेजमेंट एप्रेसियेशन पाठ्यक्रम तथा विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों का चलाना।

4. मशीन शौप प्रैक्टिस, टूल रुम प्रैक्टिस, फिटिंग, ब्लैकस्मिथी, कार्पेन्टरी और डाई एन्ड टूल मेकिंग जैसे विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का चलाना।

5. सरकारी भण्डार खरीद कार्यक्रम में भाग लेने के लिये लघु एककों के नाम सूची में दर्ज करना।

6. लघु उद्योगों का विकास कैसे तथा किस हद तक हो सकता है, इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये आर्थिक जांच-पड़ताल (अन्वेषण) का आयोजन।

7. आशातीत उत्पादन के लिये आर्थिक जानकारी सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था करना।

औद्योगिक विस्तार सेवा, जिसकी व्यवस्था कटक स्थित लघु उद्योग सेवा संस्था ने की है, और विस्तार केन्द्र गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा सरकारी विभाग को निम्न विषयों सम्बन्धी बहुत-सी पूछ-ताछों के बारे में जानकारी देते हैं :

1. समुचित कच्चे माल की उपलब्धता तथा प्रयोग।

2. विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में छपी योजनाओं तथा परियोजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों की सप्लाई।

3. ऐसी प्रक्रियाओं तथा कार्यों के लिये जो लघु एककों के साधनों के बाहर हैं, वर्कशॉपों तथा विस्तार केन्द्रों के माध्यम से नाम मात्र चार्ज पर आम सुविधा सेवाओं की उपलब्धि।

यह संस्था राज्य सरकारों तथा वित्तदाता संस्थाओं को लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं का निर्धारण करने में मदद देने के लिये उन्हें मूल जानकारी भी देती है। निर्यात संवर्द्धन तथा ग्रमीण औद्योगिक विकास के लिये सहायता—इस संस्था के कुछ अन्य क्रियाकलाप हैं।

(ख) तकनीकी सहायता

1.	विशुद्ध तकनीकी मामलों पर दी गई सलाहों की संख्या	950
2.	नये उद्योगों को चलाने के बारे में दी गई सलाहों की संख्या	1005
3.	प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों के बारे में दी गई सलाहों की संख्या	54
4.	आर्थिक जानकारी दी गई मामलों की संख्या	197
5.	निर्यात सहायता दी गई मामलों की संख्या	93
6.	अन्य मामलों पर दी गई सलाहों की संख्या	1720

(II) चलती-फिरती गाड़ियां

1.	चलायी गई गाड़ियों की संख्या	2
2.	उन केन्द्रों की संख्या जहां का दौरा किया गया	10
3.	आयोजित प्रदर्शनों की संख्या	10
4.	प्रशिक्षित किये गये शिल्पियों की संख्या	288

(III) प्रकाशन

1.	तैयार किये गये–डिजायन, ड्राविंग तथा ब्लू प्रिन्ट	51
2.	तयार की गई आदर्श योजनाएं	6
3.	एरिया सर्वे रिपोर्ट्स–जिन्हें अन्तिम रूप दिया गया	2
4.	ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिये योजना	13
5.	राज्य सरकारों के लिये योजनाएं	47

(IV) एस० आई० एस० आई० वर्कशौपों तथा विस्तार केन्द्रों का काम-काज

1.	उन उद्यमकर्ताओं की संख्या जिन्होंने वर्कशौपों तथा विस्तार केन्द्रों का दौरा किया	323
2.	उन उद्यमकर्ताओं की संख्या जिन्हें वस्तुतः सहायता दी गई	303
3.	निष्पादित कामों की संख्या	784
4.	रुपयों में अर्जित राजस्व	10,477.57

(V) प्रशिक्षण :

1.	प्रबन्ध पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	47
2.	अन्य तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	15

(VI) सरकारी भण्डार खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत अलिस्टमेन्ट :

1.	एस० आ० एस० आई० की सिफारिशों पर एन० एस० आई० सी० में दर्ज एककों की संख्या	13

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

4207. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1967 में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये उस राज्य को कोई ऋण अथवा अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में वास्तविक व्यय और उसी वर्ष के अन्तिम तीन महीनों के लिये पूर्वानुमानित व्यय के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान और ऋणों के अन्तःकालीन भुगतान की मंजूरी इस शर्त पर दी जाती है कि ये

आंकड़े उसी वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार से प्राप्त लेखा-परीक्षित आकड़ों के आधार पर कुछ अदल-बदल के साथ मेल खाते हों। उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1966–67 के दौरान अपने राज्य की योजना-योजनाओं की क्रियान्विति, लघु उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये मार्च, 1967 में निम्नलिखित राशियों के लिये अन्तःकालीन भुगतान की मंजूरी दी गई थी :—

लघु उद्योग		औद्योगिक बस्तियां
ऋण	अनुदान	(रुपये-लाखों में)
2.95	1.48	9.00

उड़ीसा में औद्योगिक कारखाने

4208. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में उड़ीसा राज्य में स्थापित किये गये नये औद्योगिक कारखानों के नाम क्या हैं तथा उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में उनके लिये सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वर्ष 1966–67 में उड़ीसा राज्य में स्थापित नये उद्योगों के बारे में पूरी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथापि, उक्त वर्ष में केन्द्रीय क्षेत्र में बारगढ़ में एक सीमेंट कारखाना बन रहा था और रुरकेला इस्पात कारखाने का प्रथम प्रक्रम विस्तार को क्रियान्वित किया जा रहा था। उपरोक्त सीमेंट कारखाना इस बीच पूरा हो चुका है और रुरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के हेतु उड़ीसा सरकार के लिये वर्ष 1966–67 में 4 करोड़ 97 लाख रुपये का नियतन किया गया था।

उड़ीसा के लिये कोयले के डिब्बों का नियतन

4209. श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में उड़ीसा के लिये कोयले के कितने डिब्बे नियत किये गये थे; और

(ख) उसी अवधि में उड़ीसा को कितने डिब्बों की आवश्यकता थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय तथा राज्य प्राथमिकताओं के अधीन जनवरी, फरवरी और मार्च 1967 में उड़ीसा को भेजे गये नियंत्रित तथा अनियंत्रित कोयले/कोक के कोयला वैगनों की संख्या क्रमशः 11,163, 8,399 तथा 10,949 थी।

(ख) कोयले/कोक की आवश्यकता का ठीक पता नहीं है क्योंकि अनियंत्रित कोयला/कोक इडेंटों के आधार पर लदाया जाता है जो कि बंटन होने तक बार बार होते रहते हैं। तथापि 1967 में अनियंत्रित कोयले के लिये राज्य सरकार ने राज्य द्वारा नियंत्रित प्राथमिकताओं के 307 वैगन प्रति मास की सिफारिश की।

उड़ीसा में हस्तशिल्प उद्योग का विकास

4210. श्री ख० प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका - श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में उड़ीसा सरकार को राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी रकम मंजूर की थी; और

(ख) 1967–68 में उस राज्य को इस कार्य के लिये कितनी रकम देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1966–67 में उड़ीसा सरकार को राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों का विकास करने के लिये 75 हजार रुपये का अनुदान तथा 38 हजार रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वस्तुतः खर्च की गई राशि के आंकड़ों की प्राप्ति पर इन राशियों में समायोजन किया जा सकता हैं।

(ख) वर्ष 1967–68 में इस राज्य के लिये कितनी राशि मंजूर की जायेगी, इसका पूर्वानुमान लगाना अभी कठिन है क्योंकि वह उड़ीसा राज्य द्वारा वस्तुतः खर्च की गई राशि पर निर्भर करेगी।

M/s. Hindustan Vehicles Ltd., Patna

4211. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government had entrusted the management and operation of the Hindustan Vehicles, Ltd., Patna (Bihar) to the Government of Bihar after taking over the Company under the Industries Development and Regulation Act, 1951 on the 24th September, 1965;

(b) whether the then State Government had declared a lock-out there within a few months after the assumption of management and the workers were paid off;

(c) whether it is also a fact that hundreds of workers of the factory have remained unemployed due to its closure and it has also adversely effected the production of cycles in the country; and

(d) if so, whether Government propose to give financial assistance to the Government of Bihar in order to enable the latter to re-open this factory and whether they propose to investigate into the bungling of lakhs of rupees in the said factory ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Ahmed): (a) to (c) Under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government by a notified order dated the 24th September, 1965. authorised an officer nominated by the Government of Bihar to take over the management of M/s. Hindustan Vehicles Ltd., Patna, as Authorised Controller. The Government of Bihar have reported that the liabilities incurred by the previous management of the Company were far in excess of the assets and that several legal proceedings in law courts were pending against the Company for recovery of dues. All the assets were also found to have been mortgaged. The factory had been closed down by the previous management and it could not be re-commissioned in the above circumstances. The workers were laid off in September, 1956. The closure of the factory has not affected the country's overall production of cycles which is on the increase.

(d) There is no such proposal.

मैसर्स डालमिया एण्ड जैन को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

4212. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या औद्योगिक विकास तथा समवायकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विवियन बोस आयोग द्वारा दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् मैसर्स डालमिया एण्ड जैन को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : विवियन बोस अयोग द्वारा दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् मैसर्स डालमिया एण्ड जैन की फर्मों को दो लाइसेंस दिये गये थे ।

Railway Line from Etawa to Bhind

4213. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether any public demand for laying down new railway line from Etawa Railway Station in U. P. to Bhind Railway Station in Madhya Pradesh and for converting the narrow gauge from Bhind to Gwalior into broad-gauge, in view of the security of the country, is under consideration; and

(b) if so, the action taken thereon ?

Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Coach Attendants of Northern Railway

4214. Shri Gunanand Thakur :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any representation has recently been received by his Ministry from the Coach Attendants of the Northern Railway ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. However, a representation regarding imposition of Safawallah's duties has been received by the Northern Railway Administration.

(b) In addition to other duties, the attendants are required to keep the compartments, corridors and was-basins and mirrors clean while the train is on the run. In regard to commode and floor in the bath-rooms, the attendents are not expected to do any cleaning themselves but they are to ensure that they are cleaned by the staff kept for this purpose at different stations. There is no proposal to revise these instructions.

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अधिक ली गई राशि को लौटाने के मामले

4215 श्री कंवरलाल गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अधिक ली गई राशि को लौटाने के अनेक मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड के निदेश के बावजूद सैंकड़ों मामलों अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है यद्यपि कई वर्ष बीत चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कुछ न कुछ मामले तो सदैव ही अनिर्णित पड़े रहते हैं क्योंकि जब कोई दावा किया जाता है तो उसे निपटाने में कुछ समय तो अवश्य ही लगता है ।

(ख) यह सच नहीं है कि सैंकड़ों मामले कई वर्षों से अनिर्णित पड़े हैं ।

(ग) माननीय सदस्य यदि कुछ बहुत पुराने मामलों की जानकारी दें, जिन्हें अब तक निपटाया नहीं गया है तो समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

Misuse of Railway Passes on Eastern Railway.

4216. Shri Rabi Ray : Will the Minister of Rilways be pleased to state :

(a) the number of employees apprehended on the Eastern Railway for misusing the Railway passes, the category of passes and the nature of punishment awarded to them;

(b) whether it is a fact that the relatives of some officials in the Office of the Chief Engineer, Gorakhpur were apprehended for misusing the duty and privilege passes; and

(c) if so, the nature of punishment awarded ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A statement is laid on the **Table of the House [Placed in Library, See No. LT-873/67]**

(b) Only in one case relatives of an official were apprehended for the misuse of pass.

(c) Apart from full fare and penalty which the employee deposited, his pay was reduced by Rs. 50/- per month for a period of one year,

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, लिमिटेड

4217. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ इंजीनियर (टैक्निकल), चीफ इंजीनियर (सिविल) और वर्कस मैनेजर तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की कारों की देख-रेख पर पृथक् पृथक् कितना धन खर्च किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सब अधिकारियों को शहर के कार्य-स्थल तक जाने के लिए 40 रुपये प्रति मास की मामूली दर पर पूरे समय के लिए स्वतन्त्र रूप से कर दी गई है; और

(ग) लॉग-बुक में की गई प्रविष्टियों के अनुसार पिछले 6 महीनों में उपरोक्त प्रत्येक कार औसतन प्रति मास कितने मील चली तथा वसूल की गई राशि की तुलना में अवक्षयरण, ड्राइवर का वेतन और कराधान और बीमा सहित देखरेख पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए इन कारों की देखरेख पर वस्तुतः कितना व्यय हुआ ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ० अ० अहमद) : (क) जनरल मैनेजर को दी गई कार पर औसत कुल मासिक खर्च 800 रुपये है और डिप्टी जनरल मैनेजर के कार पर 700 रुपये है, अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कारें नहीं दी गई हैं ।

(ख) शहर से कार्य-स्थल तक जाने के लिये स्वतन्त्र रूप से किसी को कोई कार नहीं दी गई है किन्तु जनरल मैनेजर, चीफ इंजिनियर (तकनीकी), वर्क्स मैनेजर तथा चीफ इंजीनियर (सिविल) शहर स्थित निवास स्थान से कार्य–स्थल तक आने में स्टाफ कारों का प्रयोग करते हैं और उनसे 40 रुपये प्रतिमास लिया जाता है ।

(ग) जनरल मैनेजर तथा डिप्टी जनरल मैनेजर को सरकारी काम के लिये दी गई कारें क्रमशः औसतन 2239 किलो मीटर प्रति मास चलती हैं । इन दो कारों के रख-रखाव का खर्च उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है । चीफ इंजीनियर (तकनीकी) तथा वर्क्स मैनेजर द्वारा संयुक्त रूप से प्रयुक्त कार औसतन 3889 किलोमीटर प्रति मास चलती है और और उसका खर्च 935 रुपये प्रति मास है । चीफ इंजीनियर द्वारा प्रयुक्त कार औसतन 2535 किलोमीटर प्रतिमास चलती है और उसका खर्च 875 रुपये प्रतिमास है, इस खर्च में रख-रखाव खर्च, मूल्य–ह्रास, ड्राइवर का वेतन, कराधान, बीमा आदि खर्च शामिल हैं ।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हैदराबाद

4218. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय राजनैतिक नेता भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड जैसे एककों के दैनिक प्रशासन पर प्रभाव डाल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के हैदराबाद एकक के उप-महा-प्रबन्धक की नियुक्ति राजनैतिक बातों के आधार पर की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त एकक में नियुक्ति करने की इस समय नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) आंध्र प्रदेश तथा उसके साथ लगते हुए अन्य राज्यों में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों से चयन करके शिल्पियों, अर्द्ध-दक्ष श्रमिकों, तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों, टाइपिस्टों तथा अनुसचिनीय कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। अदक्ष कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियां आन्ध्र प्रदेश के रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से की जाती हैं। अन्य सब पदों पर नियुक्तियों का आधार अखिल भारतीय है और योग्यता के आधार पर इन पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं।

चाय का निर्यात

4219. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में केवल चाय ही एक ऐसी वस्तु है जिसका निर्यात करने पर उत्पादन शुल्क वापिस नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का विचार ऐसी रियायत देने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्यात के समय उत्पादन शुल्क को निर्यात शुल्क के साथ मिला दिया जाता है, जिसका निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि चाय पर लगाए गए

उत्पादन शुल्क को व.पस नहीं किया जाता है। जब तक चाय पर निर्यात शुल्क लागू है, तब तक प्रशासनिक दृष्टि से बजाये इसके कि पहले उत्पादन शुल्क लगाया जाय और फिर उसे वापस किया जाय, यह सरल है कि उत्पादन शुल्क को ध्यान में रखते हुए निर्यात शुल्क का निर्धारण किया जाये। यही कारण है कि जबकि आय-व्ययक प्रस्तावों में चाय के उत्पादन शुल्क को बढ़ाया गया है, इसके निर्यात शुल्क को कम किया गया है।

खुर्दा रोड जंकशन पर महिला यात्री मार्ग दर्शक

4220. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि खुर्दा रोड जंक्शन पर महिला यात्रियों के मार्ग दर्शन के लिये कोई महिला यात्री मार्ग दर्शक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Price of Tools given with Motor Cars

4221. Shri Mirtyunjay Prasad :
Shri D. N. Singh :
Shri Hari Krishna :
Shri Prem Chand Verma :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1399 on the 2nd June, 1967 and state :

(a) wheather it is a fact that the cost of the tools is shown separa ly in the account books by the manufacturers of the Ambas ador, Fiat and Standard cars ;

(b) if so, the reasons for the Governm nt not looking into their quality usefulness and durability ; and

(c) wheather Government propose to fix the number, quality and prices of the said tools so that in case the customers find these tools unsatisfactory, costlier or inferior to those available in the martket, they may refuse them and have the cost thereof refunded ?

The Minister of Industrial development and Company affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Government are not aware whether or not cost of the tools supplied to the customers is separatly shown by the manufactures of cars in their actual Books.

(b) and (c) It is proposed to set up shortly a Committee to go into the quality of cars manufactured in the country. The question of the quality and the number of tools supplied by the car manufacturers will also be looked into by this Committee.

Production of Cars

4222 Shri Mrityunjay Prasad :
Shri Hari Krishna :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Prem Chand Verma :

Will the Minister of **Industrial Development & Company Affairs** be pleased to state ;

(a) The reasons for lesser production of Bedford, Fiat, Standard, Leyland, Tempo and Tata Mercedes vehicles the production possible under the existing capacity ;

(b) whether any efforts are being made to increase the production of the said vehicles ;

(c) the amount of foreign exchange demanded by the Hindustan Motors in December, 1966 for necessary spare parts and raw material to increase the production capacity of Ambassader Cars to 30,000; and

(d) the amount of foreign exchange demanded by the Premier Automobiles to develop their factory to increase the production capacity of Fiat Cars to 30,000 and the amount of exchange asked for importing spare parts and raw marerial after the capacity has been increased ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) The short-fall in production during January to May 196 , as compared to corresponding period last year, is limited only to Bedford Commercial vehicles, Standard one ton truck and Tempo three wheeler. The production of Tata Mercedez Benz and Leyland Commercial vehicles as also of Fiat and Standard Herald cars has, in fact, shown an increase during the same period as compared to the production during the corresponding period last year.

The fall in production of commercial vehicles is due to slackness in the demand for these types of vehicles. Till the demand puts up, there is little scope to increase production.

(c) In December,1966 M/s.Hindustan Motors Ltd.,Culcutta had asked for allocation of foreign exchange to the extent of Rs. 908 lacs for one year so as to enable them to step up their production to the level of 30,000 cars per annum.

(d) In January, 1967 M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay had submitted a proposal for effecting substantial expansion of their capacity for the production of Fiat cars to 30,000 Nos. per annum. They had indicated that they would need Rs. 3.75 crores in foreign exchance for the import of capital goods. No indication had been given by them about their requirements of foreign exchange for the import of components and raw material for the proposed expansion.

Distribution of Cement in Bihar

4223. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Mudrika Singh :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact there is much bungling in the distribution of cement in Bihar State ;

(b) whether it is a fact that even after taking advance from the wholesale and retail dealers, the proprietors agents of cement factories supply cement only after three or four months ; and

(c) if so, the steps being taken to check this bungling ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) No, Sir.

(c) Quarterly supplies made to the stockists during 1965-1966 and Quarter I/67 are indicated below :-

Control period		After decontrol	
Quarter	Tonnes	Quarter	Tonnes
I/65	32,462	I/66	63,324
II/65	39,210	II/66	58,759
III/65	46,707	III/66	73,969
IV/65	53,732	IV/66	72,124
		I/67	77,369

It will be seen that supplies have been improving constantly. Sometimes some delay may have occured due to unavoidable difficulties like Railway restrictions on movement but in such cases where the delay is more than 45 days selling agents have instructions to pay interest on advances. The cement Allocation & Coordinating Organisation has specially appointed a Liaison Officer at Bhagalpur to ensure prompt and equitable distribution of cement in Bihar, especially North Bihar. The Liaison Officer at Bhagalpur and the Regional Coordinating Officer Calcutta, keep themselves in toutch with the Government Officials and others so that complaints are promptly dealt with.

पायदानों पर यात्रा

4224. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 342-डाउन गाड़ी में पायदान पर यात्रा करते समय वर्ष 1967 में अब तक कुल कितने यात्रियों को चोट लगी :

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

(ग) क्या यह सच है कि 342-डाउन गाड़ी में 5 अथवा 6 डिब्बे होते हैं जबकि उसमें निर्धारित डिब्बों की संख्या 11 हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस लम्बी यात्रा गाड़ी में कम डिब्बे लगाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस गाड़ी के कारण घायल हुए व्यक्तियों अथवा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को कुल कितनी राशि दी गई है ?

रेल्वे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चोट लगने की कोई घटना नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) 342 डाउन गाड़ी के कुछ अवसरों पर उसके निर्धारित डिब्बों की संख्या जो कि दस है सो तीन या चार डिब्बे कम लगाकर चलाया गया है । इसके लिये कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(च) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

37-अप तथा 38-डाउन रेल गाड़ियां

4225. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 37-अप तथा 38 डाउन रेलगाड़ियों की समय-पाबन्दी की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) इन गाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : अप्रैल से मई 1967 तक की अवधि में 37-अप पंजाब मेल की फिरोजपुर स्टेशन पर ठीक समय पर पहुंचने की प्रतिशतता 8.2 है और 38-डाउन पंजाब मेल को दिल्ली स्टेशन पर ठीक समय पर पहुंचने की प्रतिशतता लगभग 10 है।

(ख) 57-अप/38 डाउन मेल गाड़ियों सहित सब यात्री गाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने का मामला रेलवे प्रशासन के सब स्तरों पर परीक्षाधीन है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि गाड़ियां ठीक समय पर चलें रेलवे को गाड़ियों के निर्धारित समय का पुनरीक्षण करने को कहा गया है।

बहादुरगढ़ और नई दिल्ली के बीच 1 डी० एस० बी गाड़ी

4226. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहादुरगढ़ और नई दिल्ली के बीच 1 डी० एस० बी० गाड़ी खाली रेक की शक्ल में चलती है;

(ख) यात्रियों को इस गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि 17 बजे से 22.30 बजे के बीच रोहतक से कोई डाउन गाड़ी नहीं चलती है ;

(घ) क्या यह खाली गाड़ी को नियमित गाड़ी के रूप बदलने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है: और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) इसके अतिरिक्त कि इस गाड़ी को नियमित गाड़ी में बदलने का कोई यातायात औचित्य नहीं है, इस गाड़ी को नियमित में बदलने से लाइन की क्षमता कम होने के कारण माल के लाने ले जाने पर कुप्रभाव पड़ेगा।

(ग) जी हां, 17 बजे से 22.18 के बीच कोई गाड़ी नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले की सप्लाई

4227. गा० च० दीक्षित : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने ओबटा तापीय बिजली घर को सिंगरोली कोयला खानों से कोयला सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले की सप्लाई किस तारीख तक आरम्भ करदी जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बिजली सम्बन्धी बोर्ड ने अभी तक ओबरा ताप बिजली घर के लिये सिंगरोली का कोयला खरीदने के हेतु राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के साथ मिल कर कोई प्रबन्ध नहीं किया है ।

(ग) दोनों पक्षों के बीच में प्रबन्ध तै हो जाने पर, रेल की पटरी डालने का काम शुरू किया जा सकता है । यह कार्य ओबरा ताप बिजली घर को रेल द्वारा कोयला देने के लिये आवश्यक है । इस कार्य के पूर्ण होने में लगभग दो वर्ष लग जायेंगे । इसके बाद शीघ्र ही कोयला दिया जाना आरम्भ हो जायगा ।

बालाघाट तथा जबलपुर जिलों में तांबे के खनिज-भण्डार

4228. श्री गं० च० दीक्षित : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा जबलपुर जिलों में तांबे के खनिज-भण्डारों का गहन-सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी) : (क) और (ख) तीसरी योजना काल में इमालिया, भूला तथा नवालिया में भूवैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवालिया–अंगावन, सलारपुर, बरगांव और जबलपुर जिले के भूला में भूभौतिकी अन्वेषण किये गये परन्तु किसी खनन योग्य निक्षेप का पता नहीं चला ।

बालाघाट जिले में तांबा धातु के लिये खनिज कार्य स्फटिक नसों तथा कणाश्म तक सीमित है । जबलपुर के इमालिया क्षेत्र में खनिजयुक्त खण्ड लगभग 100 मीटर तक पाया गया है । दोनों क्षेत्रों से इकट्ठे किये हुये नमूनों की जांच की जा रही है ।

Insceticide Spraying Machine

4229. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that small size insecticide spraying machine has been manufactured in Durgapur; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Ahmed) : (a) and (b) A project for developing a light and cheap spraying equipment having no moving parts for insecticides, pesticides etc. is in operation at the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, and a sprayer of capacity about 30 litres per hour has been designed and fabricated. A sencond prototype of the sprayer with some improvements has been fabricated and trials are going on.

The insecticide sprayer under development is a machine having a similar operating principle as that of the imported 'Swing Fog' sprayer available in the market. The unit is a low volume sprayer having a spraying reach of about 6 to 8 ft. The unit can be shoulder mounted during the spraying operations and weighs about 12 Kgms. without petrol and insecticide and about 18 Kgms. with them.

बिड़ला सार्थ समूह

4230. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :
श्री श्रीधरन :
श्री प० मु० सैयद :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बिड़ला फर्मों को लाइसेंस दिये हैं जिनके पास उनको दिये गये लाइसेंसों की तुलना में कम मूल्य की आस्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो 1960 से मई, 1967 तक की अवधि में बिड़ला की ऐसी कितनी फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) इस अवधि में विभिन्न फर्मों को तथा बिड़ला की फर्मों को कुल कितने–कितने लाइसेंस दिये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) से (ग) इसमें कोई संदेह नहीं कि लाइसेंस देते समय आवेदक फर्मों की पूंजी आस्तियों पर विचार किया जाता है परन्तु उस समय अन्य बातों जैसे अनुसूचित उद्योग के विकास की केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर शुदा योजना यदि कोई है, तथा जहां ऐसी कोई योजना नहीं होती वहां अनुसूचित उद्योग की वर्तमान क्षमता, मांग तथा पूर्ति की स्थिति, कच्चे माल, सयन्त्र तथा

मशीनों की अपलब्धि पर भी ध्यान दिया जाता है। आवेदन पत्रों को मंजूर करने से पहले परियोजना पर धन लगाने की प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त उद्योग की मंजूरशुदा योजना के अनुकूल प्रस्तावित उद्योग के स्थान को उपयुक्तता, प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता, रेल यातायात की उपलब्धता, तकनीकी जानकारी तथा तकनोकी व्यक्तियों की उपलब्धता, विदेशी निर्माताओं के साथ सहयोग, यदि कोई है, आदि बातों पर भी पूरा विचार किया जाता है।

जनवरी 1960 से मई 1967 तक विभिन्न फर्मों को कुल 7,065 लाइसेंस दिये गये। बिड़ला तथा अन्य औद्योगिक समूहों को दिये गये लाइसेंसों की पृथक पृथक तिथियां इस समय उपलब्ध नहीं है। उक्त अवधि में दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा जिसमें लाइसेंसों के नाम तथा उनकी किस्में शामिल हैं "वीकली बुलटेन ऑफ इंडस्ट्रीयल लाइसेंस इम्पोर्ट लाइसेंस् एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस" साप्ताहिक और इण्डियन ट्रेड जनरल तथा मंथली जनरल ऑफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया गया है। ये सब प्रकाशन सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बसर तथा मंचेरियल के बीच रेलवे लाइन

4231. श्री नारायण रेड्डी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिलाबाद जिले में बसर तथा मंचेरियल के बीच मुधोल भैंसा, निरमल आदि से होकर एक सीधी रेलवे लाइन निकालने के बारे में सरकार द्वारा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या इस योजना को चौथी पन्चवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई सर्वेक्षण करने का सरकार इस समय विचार कर रही है।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में नई लाइनें बिछाने के लिये दिये जाने वाले धन की सीमित राशि को देखते हुए निकट भविष्य में इस योजना को हाथ में लेना बड़ा मुश्किल है।

मध्य प्रदेश में लघु उद्योग

4232. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कितने लघु उद्योगों ने भारत-चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रतिरक्षा उत्पादन में सहयोग देने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या ये प्रस्ताव प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल थे और यदि हां, तो उनमें से कितने प्रस्तावों का प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये उपयोग किया गया;

(ग) इन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त फर्मों की कमियों को दूर करके उनकी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) लगभग 50 ने ।

(ख) समय समय पर 12 एककों को आयुध संस्थानों द्वारा निविदायें भेजी हैं और अब तक मध्य प्रदेश के छोटे पैमाने के उद्योग 6,70,000 रुपये के आर्डरों को क्रियान्वित कर चुके हैं ।

(ग) शेष एककों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण हैं:–

(1) इन एककों द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों की आयुध संस्थानों को आवश्यकता नहीं है ।

(2) प्रतिरक्षा आर्डरों को क्रियान्वित करने के लिये कुछ एककों की मशीनें तथा दक्ष कारीगरी उपयुक्त नहीं है ।

(3) कुछ एककों ने प्रतिरक्षा संस्थाओं के साथ अपने आपको पंजीकृत नहीं करवाया है ।

(घ) छोटे पैमाने के उद्योगों की कमियों को दूर करने तथा उनकी क्षमता एवं कारीगरी में सुधार कराने के लिये राज्य के उद्योग निदेशालय के सहयोग से लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर कार्य कर रहा है ।

रुई का मूल्य

4233. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कृषि-मूल्य आयोग ने कपास के मूल्यों की सांविधिक उच्चतम सीमा को हटाने की सिफारिश की है और इसके स्थान पर सरकार द्वारा कपास की खरीद के लिये समाहार मूल्यों की व्यवस्था का सुझाव दिया है;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग ने सरकार द्वारा कपास का व्यापार करने की, जिसमें आयात भी शामिल है, एक दीर्घकालीन योजना का भी सुझाव दिया है जिससे सरकार देश में प्रतिवर्ष कातने योग्य रुई की कुल सप्लाई की 20 प्रतिशत मात्रा पर अपना नियंत्रण रख सके; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1967-68 की फसल के लिये कच्ची कपास की मूल्य नीति के बारे में कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

4234. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच कोरबिया गांव में रेलवे का एक हाल्ट बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) कोरबिया गांव में हाल्ट स्टेशन बताने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

कामरेडी के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतरना

4235. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के काचेगुडा-मनमाड छोटी लाइन सेक्शन में कामरेडी के निकट लगभग दो वर्ष पहले पटरी से कितने माल-डिब्बे उतर गये थे;

(ख) क्या इन माल-डिब्बों में जो माल था उसके लिये दावे किये जा चुके हैं और उसे दुर्घटना स्थल से हटा लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के कठोर तथा गैर जिम्मेदारी रवैये के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1 फरवरी, 1966 को लगभग 8.45 बजे 807 डाउन मालगाड़ी के जबकि वह टालमाडो और कामरेडा स्टेशनों के बीच चल रही थी, 516/3-4 किलोमीटर पर माल से भरे 4 माल डिब्बे और एक माल ब्रेकवान पटरी से उतर गये थे तथा माल से भरे 14 डिब्बे और एक खाली तेल का डिब्बा उलट गये थे।

(ख) टाइलों की एक खेप को छोड़ कर पटरी से उतरे तथा उलटे डिब्बों से उतारे गये माल को मोटरगाड़ियों द्वारा कामरेडी भेजा गया था तथा उस माल का डिब्बों में पुनः लदान करके उसे 3 फरवरी से 9 फरवरी, 1966 तक रवाना कर दिया गया था। टाइलों को जिन्हें कामरेडी के निकट निजामाबाद भेजना था, 11 फरवरी, 1966 के उन के गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर माल-डिब्बों का नियतन

4236. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को निजामाबाद रेलवे स्टेशन से 'ङ' श्रेणी में माल-डिब्बों के

नियतन के मामले में हो रही घोर अनियमितताओं के बारे में आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले की बीड़ी निर्माण संस्था से अप्रैल मई, 1967 में कोई शिकायत मिली थी;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की गयी धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, निजामाबाद स्टेशन से बीड़ियां ले जाने के लिये माल डिब्बों की सप्लाई के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) निजामाबाद स्टेशन से शीघ्रता से बीड़ियों को ले जाये जाने की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की गई है । 1 जनवरी से 20 जून, 1967 तक की अवधि में इस स्टेशन पर माल डिब्बों में बीड़ियों का लदान किया गया था और 20 जून को माल डिब्बों की कोई मांग बाकी नहीं थी । वास्तव में मार्च 1967 से प्रत्येक महीने के अन्त में कोई मांग बाकी नहीं थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात का उत्पादन

4237. श्री देवव्रत बरुआ :
श्री वी० ना० शास्त्री :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ था; और

(ख) यह उत्पादन 1965–66 के आंकड़ों की तुलना में कितना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) वर्ष 1965-66 और 1966–67 में इस्पात पिण्डों और तैयार इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित है:—

(हजार टन)

	1965-66	1966–67
इस्पात पिण्ड	6526.2	6595.8
तैयार इस्पात	4509.3	4461.5

Reinstatement of Railway Drivers after Accidents

4238. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the conditions on which the Drivers involved in train accidents are reinstated and the number of such Drivers reinstated during the last five years on the North-Eastern, Central and western Railways; and

(b) the number of Drivers discharged during the last ten years on the above Railways whose provident Fund and other Accounts were cleared soon after the discharge and the number of those whose accounts were not cleared ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the sabha.

Imports of Sports Goods

4239. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of firms in foreign countries from whom sports goods were imported during the last five years;

(b) the amount of foreign exchange spent on them;

(c) whether Government have also exported sports goods to foreign countries; and if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) Import statistics indicating the foreign firms from whom the goods are imported are not maintained. However, a statement showing country-wise value of import of sports goods during 1962-63 to 1966-67 (upto Feb., 1967) is laid on the Table of the House **[Placed in Librany. See no. L T-869 67]**

(c) Yes, Sir.

(d) A statement showing exports of sports goods to various countries during 1962-63 to 1966-67 (upto Feb. 1967) is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See no. L T-869 67]**

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को आवंटित इस्पात का कोटा

4240. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में हिन्दुस्तान मोटर लिमिटेड को इस्पात का कितना कोटा दिया गया था;

(ख) इस कम्पनी ने इस्पात का वस्तुतः कितना उपयोग किया और कितना इस्पात काले बाजार में बेचा; और

(ग) क्या सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1965–66 और 1966–67 में हिन्दुस्तान मोटर्स को मोटर कारों वाणिज्य-गाडियों और

खोदाई करने वाली मशीनों के निर्माण के लिए क्रमशः 7120 टन और 7400 टन इस्पात का कोटा दिया गया ।

(ख) और (ग) उन्होंने 1965-66 के वर्ष में मोटर कारों और वाणिज्य-गाड़ियों के निर्माण के लिए 17,895 मीटरी टन और खोदाई की मशीनों के निर्माण के लिए 122 मीटरी टन नियंत्रित किस्म के इस्पात का इस्तेमाल किया। 1966-67 के वर्ष में इस्तेमाल किये गये इस्पात की रिपोर्ट तकनीकी विकास के महा-निदेशक के पास अभी नहीं पहुंची है। इस्तेमाल किये गये इस्पात के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उसकी जांच तकनीकी विकास के महानिदेशक द्वारा कर लेने के बाद सूचना सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे लाइनों के निकट की मिट्टी खोदना

4241. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुहरी रेलवे लाइनें बिछाने के लिए पार्श्ववर्ती खेतों से मिट्टी खोद ली जाती है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि खोदने से भूमि कटने लगती है और इससे वहां पर गड्ढे बन जाते हैं और जिससे अन्ततोगत्वा उनके आस-पास रहने वाले व्यक्ति दुर्घटना-ग्रस्त हो जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की वांछनीयता पर विचार किया है कि रेलवे लाइनों के निकट खाइयां अथवा गड्ढे न खोदे जायें तथा भराई के लिये मिट्टी निकट के बनों से अथवा किसी ऊंची जगह को खोद कर प्राप्त की जाये ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पार्श्ववर्ती भूमि में खोदे गये गड्ढों से, कभी जहां कहीं रेलवे द्वारा ऐसी भूमि का अर्जन किया जाना सम्भव होता है, कभी कभी मिट्टी ले ली जाती है।

(ख) साधारणतया रेलवे भूमि में ये गड्ढे इस प्रकार खोदे जाते हैं कि इन में पानी नहीं ठहरता और इनसे साथ लगने वाली भूमि में कटाव पैदा नहीं होता। क्योंकि ये गड्ढे केवल रेलवे की भूमि में खोदे जाते हैं, इसलिये इन के कारण कोई दुर्घटना नहीं होती।

(ग) जहां कहीं भूमि का अर्जन कठिन होता है तथा उसमें देर लगने की सम्भावना होती है, वहां अधिकतर मिट्टी या तो ऊंची जगहों से अथवा बेकार पड़ी भूमि से लाई जाती है।

मध्य प्रदेश की गोटीटोरिया–मोहपानी कोयला खानें

4242. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गोटीटोरिया-मोहपानी कोयला खानों में कोयले की चार पर्तें हैं;

(ख) क्या तीसरी और चौथी पर्तों में कोयला बंगाल अथवा बिहार के कोयले से बढ़िया है अथवा उतना ही अच्छा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त खानों में कुछ लाख टन सर्वोत्तम कोयला है; और

(घ) क्या सरकार उपरोक्त खानों में काम आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रैड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में कोयला 'सब-बिटुमिनस' प्रकार का है तथा उसमें मद तथा चमकते कोयले की बारी बारी से पर्तें हैं । यह आम तौर से मंद कोकिंग कोयला है जिसकी तुलना पश्चिमी बंगाल और बिहार की महत्वपूर्ण दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों के धातु-कार्मिक कोयले के साथ नहीं की जा सकती । अनुमान है कि खान क्षेत्रों में कोयले के संचय सम्भवतः 6 मिलियन टन के स्तर के होंगे यद्यपि इसमें सन्देह है कि इस कोयले को मुनासिब खर्च पर निकाला जा सकेगा । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पुरानी खानों के दक्षिणी क्षेत्र में अन्वेषणात्मक व्यधन कर रही है और करती रहेगी । सब प्रकार से वर्तमान अन्वेषण पूर्ण हो जाने पर ही अधिक स्पष्ट रूप से स्थिति का पता चल सकेगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे की जोनल तथा डिवीजनल सलाहकार परिषदें

4243. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की जोनल तथा डिवीजनल सलाहकार परिषदों में गैर-सरकारी व्यक्तियों का नाम-निर्देशन किन सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जाता है;

(ख) क्या व्यापारियों के प्रतिनिधियों को भी उपरोक्त परिषदों में नामजद किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या जंगलात के ठेकेदारों के प्रतिनिधियों को भी उनमें नामजद किया जाता है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे की जोनल तथा डिवीजनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को नामजद करने का सिद्धान्त यह है कि रेलवे का इस्तेमाल करने वाले विभिन्न वर्गों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय ।

(ख) और (ग) जी हां, यदि वे निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत आते हों ।

हस्तशिल्प तथा हथकरघा माल निर्यात निगम

4244. श्री जार्ज फरनन्डीज : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मई, 1966 तथा 3 जून, 1967 के बम्बई के एक साप्ताहिक पत्र 'दी करंट' में भारतीय हस्तशिल्प तथा हथ करघा माल निर्यात निगम सीमित के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन विभिन्न आरोपों में कोई सार है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) "दी करंट" के दो संस्करणों में हस्तशिल्प तथा हथकरघा माल निर्यात निगम के विरुद्ध लगाये गये अधिकतर आरोप तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है और उन में से कुछ आरोप उस निगम से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पनियों के संतुलन पत्र

4245. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने के औसतन कितने समय बाद सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें अपने लेखापरीक्षित संतुलन–पत्र प्रस्तुत करती हैं; और

(ख) क्या यह अवधि गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिये निर्धारित अवधि की तुलना में अधिक है और इस संबन्ध में दोनों ही क्षेत्रों को बराबर समय देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1965–66 आर्थिक वर्ष में, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अपनी साधारण निकाय बैठकों में अंशधारियों के समक्ष लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने को ली गई अवधि का औसत 6 महीने तथा 12 दिन था। सरकारी कम्पनियों के 72–5 प्रतिशत ने, अपने आर्थिक वर्ष की समाप्ति से 6 महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर अपने लेखा परीक्षित संतुलन-पत्र प्रस्तुत कर दिये। शेष में से, 19-6 प्रतिशत ने उन्हें अवधि का विस्तार प्राप्त करके, जो तीन महीने तक स्वीकार योग्य है, 9 महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर दिया। कम्पनियों के 7-8 प्रतिशत ने अपने संतुलन-पत्र 9 महीने की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किये।

(ख) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा इसी वर्ष में, ली गई अवधि का औसत सरकार क्षेत्र की कम्पनियों से 5 दिन अधिक अर्थात् 6 महीने तथा 17 दिन था। वार्षिक साधारण बैठकों में, अंशधारियों के समक्ष लेखा परीक्षित संतुलन पत्र आदि प्रस्तुत करने की समय-सीमा दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिये समान है, तथा इस मामले में वह समकक्ष हैं।

ईदगाह, आगरा से चलने वाली गाड़ियां

4246. श्री चित्तरंजन राय :
श्री रामेश्वर सिंह :
श्री य० अ० प्रसाद :
कुमारी रजनी गंधा :
श्री प० मु० सैयद :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईदगाह, आगरा जंक्शन से चलने वाली गाड़ियां बिना परीक्षण प्रमाण पत्र के चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच महीनों में बिना इस प्रमाण पत्र के कितनी गाड़ियां चलीं; और

(ग) सुरक्षा नियमों का इस प्रकार उल्लंघन किये जाने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Out-Agencies

4247. **Shir Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether Government started any scheme to open out agencies at such-places where there are no Railway lines and the quantity of goods to be transported is in abundance,

(b) If so, the number thereof and the places where such out-agencies have been opened. and

(c) the annunal income the railways from these out-agencies ?

The Minisrer of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) It has long been the policy of the railways to open Out Agencies at places which are away from the railway line but are connected to some railway station by road transport and have considerable traffic.

(b) The number of out Agencies at present working is 179. A statement showing their names and the names of the railway stations servlng them is laid on the table of the House (Placed in Library See No, L. T. 870167)

(c) The railways do not get any income from Out Agencies as such, They are worked by contractors, who provied road transport between the Out Agency and the rail-head and levy a separate charge for it.

खेल कूद के सामान का निर्यात

4248. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा:**
श्री रामचन्द्र उलाका:
श्री शंकरराव माने:
श्री तुलसीदास दासप्पा:

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल अच्छे किस्म के माल का निर्यात किया जाय सरकार का विचार खेल-कूद के सामान का लदान से पूर्व निरीक्षण कराने की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इस उद्योग की प्रगति में जो अपनी धाक जमा चुका है, बाधा पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार खेल कूद का सामान बनाने वाले उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से इस समस्या का कोई हल खोज निकालने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, इसके विपरीत इस जांच के परिणामस्वरूप विदेशी खरीददारों का हमारे उत्पादों की किस्म में अधिक विश्वास पैदा होने के कारण हमारे निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ग) लदान से पूर्व निरीक्षण करने की योजना को लागू करने से पहले उद्योग से अवश्य परामर्श लिया जायेगा तथा उनकी समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद्

4249. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री शंकरराव माने :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद् 4,07,800 रुपये प्रति वर्ष व्यय करेगी और क्या इस राशि का $\frac{1}{3}$ भाग सदस्यों के चन्दे से और $\frac{2}{3}$ भाग सरकारी अनुदानों से पूरा किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बम्बई का मूल्यवान पत्थर आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं की एशोसिएशन की महासभा ने रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद की अनिवार्य सदस्यता पर सर्वसम्मति से अपना असन्तोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके असन्तोष के मुख्य कारण क्या थे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं. वर्ष 1967-68 के लिये रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद् के मंजूरशुदा व्यय के प्राक्कलन की राशि 2,21,800 रुपये हैं। इसमें से व्यापार का अंशदान 75,800 रुपये होने की संभावना है तथा सरकार के अनुदान की राशि 1,25,100 रुपये होने का अनुमान है;

(ख) वर्ष 1967-68 के प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 871/67]

(ग) और (घ) यह सूचना दी गई है कि बम्बई के मूल्यवान पत्थर आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं के ऐसोसियेशन की महासभा उस नियम के विरोध में संकल्प पास किया है,

जिसके अन्तर्गत निर्यात के रूप में पंजीकरण कराने के लिये परिषद् का सदस्य होना अनिवार्य घोषित किया गया है। उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि उन निर्यातकों को जो ऐसे उत्पादों का निर्यात करते हैं, जो विभिन्न परिषदों के अधीन हैं, एकसे अधिक परिषद् की सदस्यता शुल्क देनी होगी।

Platform at Nivari Station

4250. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the level of the platform of Nivari station on the Jhansi-Manikpur railway line is very low resulting in inconvenience and mishaps to the passengers; and

(b) if so, when Government expect to get the level of the platform raised for the safety and convenience of passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No. It is provided with a medium level (1"-6 high) platform.

(b) Does not arise.

Nivari Station

4251. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Nivari station is the only main station in District Tikam Garh on the Jhansi-Manikpur line;

(b) whether it is also a fact that all the goods meant for Tikam Garh, such as fertilizer, sugar foodgrains etc. are unloaded on this very station; and

(c) whether Government propose to provide goods sheds at the said station as the goods keep on lying at the station itself due to Nivari being at a distance of 50 miles and in the absence of goodss heds. the goods are damaged in the rainy season ?

The Minister of Railways ((Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) No. Bulk of the traffic in fertillizer, sugar, foodgrains, etc; for Tikamgarh is handled at Lalitpur which is a station on the Bombay-Delhi Main-line and Tikamgarh is served by an out-Agency with Lalitpur as the serving station. Tikamgarh is also served from Mauranipur on Jhansi-Manikpur section where large scale Goods shed facilities are available.

(c) No. There is no traffic justification for provision of goods shed facilities at Nivari.

आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता

4252. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री स्वैल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के उन श्रेणियों के कर्मचारियों को 22 नवम्बर, 1965 से आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता नहीं दिया है जिन्होंने मकान भत्ता लिया था;

(ख) क्या सरकार ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर दिया है और 18 अप्रैल 1967 को एक नया परिपत्र भी जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार अब उन कर्मचारियों को हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बकाया राशि अर्थात (प्रतिकरात्मक भत्ता) देने का विचार कर रही है ?

रेलवेमन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जुलाई 1961 से जब गोहाटी को "ग" श्रेणी का नगर घोषित किया था तो यह आदेश जारी किया गया था कि गोहाटी में तैनात कर्मचारी या तो "ग" श्रेणी के नगरों में मिलने वाला मकान भत्ता या आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता, दोनों में से एक जो उन्हें अधिक लाभदायक हो ले सकते हैं। आसाम में डिब्रूगढ़ को भी 1 जुलाई 1965 से 'ग" श्रेणी का नगर घोषित किया गया था। इन तिथियों से इन दो नगरों में तैनात कर्मचारियों को यह विकल्प है कि यदि वे चाहें तो "ग" श्रेणी के नगरों में मिलने वाला मकान भत्ता ले सकते हैं और यदि वे चाहें तो आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता ले सकते हैं. अर्थात इन दोनों में से उन्हें जो अधिक लाभदायक हो, वे उसे ले सकते हैं। इस आशय के आदेश 22.11.65 को जारी किये गये थे।

(ख) जी हां, 18 अप्रैल 1967 को जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित दो नगरों में तैनात कर्मचारियों को 1 मार्च, 1967 से मकान भत्ते के अतिरिक्त आसाम प्रतिकरात्मक भत्ता भी दिया गया है।

(ग) 18 अप्रैल, 1967 को जारी किये गये परिपत्र के द्वारा सरकार ने अपने नये निर्णय की घोषणा की है, जो कि केवल 1 मार्च, 1967 से लागू है, अतः बकाया राशि के भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में उपरि पुल

4253. श्रीमती सुशीला रोहतगी: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को पता है कि कानपुर (उत्तर प्रदेश) मुरें रेलवे फाटक पर यातायात के बार-बार रुकने के कारण जनता को बहुत परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कानपुर (उत्तर प्रदेश मुरें रेलवे फाटक पर एक उपरि पुल बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) मुरें रेलवे फाटक (महात्मा गान्धी मार्ग पर स्थिति) के स्थान पर सड़क का एक नीचला पुल बनाने का प्रस्ताव कानपुर नगर महापालिका द्वारा आयोजित किया गया है। आवश्यक तकनीकी विबरण को अन्तिम रूप दे दिया गया है और रेलवे ने भी चालू वर्ष में

लागत के अपने हिस्से की व्यवस्था करली है। यह मालूम हुआ है कि नगर महापालिका जिसे सड़क की लागत देनी है काम के अपने हिस्से के लिये अभी वित्तीय व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही सड़क अधिकारी सड़क निर्माण कार्य आरम्भ करते हैं, रेलवे साथ ही अधो मार्ग पर काम आरम्भ कर देगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात के उत्पादन में बहुतायत

4254. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात के उत्पादों की भरमार हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किस्मों के उत्पाद कितनी मात्रा में जमा हो गये हैं तथा उनकी इतनी भरमार होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस समय चपटे इस्पात के उत्पादों की प्रति वर्ष कितनी कमी रहती है; और

(घ) 1966-67 में उनका कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा 1967-68 में उनका कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) मुख्यतः मर्चेन्ट प्रोडक्स, ढांचों और रेल की पटरी का उत्पादन कुछ फालतू हुआ है। साधारणतया इस्पात का स्टाक जमा नहीं होता क्योंकि आर्डरों पर ही माल तैयार किया जाता है, और जब आर्डर नहीं होते तो उत्पादन को डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। जहां ऐसा करना संभव नही होता वहां आर्डरों की प्रत्याशा में माल तैयार कर लिया जाता है। इस समय भिलाई में मर्चेन्ट मिल के उत्पादों का स्टाक 45,000 टन के लगभग है। राउरकेला, दुर्गापुर, टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में स्टाक नाम मात्र को है।

(ग) इस्पात की कमी मुख्यतः मोटी प्लेटों (जिनमें बायलर क्वालिटी की प्लेटें शामिल हैं), अधिक पतली चादरों और जस्ती चादरों की हैं। ऐसा अनुमान है कि मोटी प्लेटों की कमी लगभग 70,000 टन और अधिक पतली चादरों की कमी लगभग 80,000 टन प्रति वर्ष है। जहां तक जस्ती चादरों का सम्बन्ध है ऐसी आशा है कि सितम्बर 1967 के पश्चात जब जस्ते का आयात होने लगेगा और राउरकेला का विस्तार पूर्ण हो जायेगा स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा :—

(घ) (मात्रा टनों में। मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ग	1966-67 का आयात (फरवरी 1967 तक)		1967-68 का अनुमानित आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1) टिप्लेट की चादरें	34,081	466.4	48,730	674.1
(2) प्लेटें	30,702	328.8	42,058	454.0

(3)	वोचांदरें	114,484	1490.6	153,695	2121.5
(4)	हूप और स्टिप्र	14,549	225.4	16.081	248.6

सरकार द्वारा कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना

4255. श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी : क्या वाणिज्य मन्त्री 2 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 8 कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जिनका प्रबन्ध सरकार ने 1965-66 और 1966-67 में अपने हाथ में ले लिया था;

(ख) इसके परिणामस्वरूप उनका कहां तक आधुनिकीकरण किया गया है और उनके कार्य संचालन में कितना सुधार किया गया है;

(ग) इन मिलों की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुनः उसके प्रबन्धकों को ये मिल सौंपने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क)

(1) यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई ।

(2) म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर ।

(3) न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, भोपाल ।

(4) हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन ।

(5) स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, इन्दौर ।

(6) श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पांडीचेरी ।

(7) औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड, औरंगाबाद ।

(8) महालक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड, बेवाड़ ।

(ख) और (ग) जानकारी प्राप्त की जारही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

तांबे तथा जस्ते का उत्पादन

4256. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तांबे तथा जस्ते का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) तांबे तथा जस्ते की इन खानों के नाम क्या हैं और उनमें कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या तांबे और जस्ते की अन्य कई खानें पाई गई हैं: और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनसे लगभग कितना तांबा तथा जस्ता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) 1965 और 1966 के दौरान तांबा धातु का उत्पादन क्रमश: 9360 टन तथा 9438 टन था । इन दो वर्षों में देश में जस्ते का कोई उत्पादन नहीं हुआ । तथापि 1965 और 1966 में जस्ता संकेन्द्रितों का उत्पादन क्रमश: 9,641 टन तथा 8,900 टन था । इनमें से जून/जौलाई 1965 में 2,569 टन सकेन्द्रित प्रद्रावण में लिये जापान भेजे गये और बदले में 1966 में 1,182 टन जस्ता धातु प्राप्त हुई ।

(ख) तीन तांबा अयस्क की खानें हैं अर्थात मोसाबोनी सुरदा तथा पाथर घोड़ा । 1965 और 1966 के दौरान इन खानों के अयस्क का उत्पादन क्रमश: 4,68,000 टन तथा 4,81,000 टन केवल एक जस्ता खान है अर्थात जवार खान जहां से जस्ता और सीसा अयस्क निकलता है । 1965 और 1966 के दौरान इस खान से अयस्क का उत्पादन क्रमशः 1,61,968 टन और 1,51,000 टन था जिसमें से इन दो सालों में क्रमशः 9,641 और 8,900 टन जस्ता सकेन्द्रितों का उत्पादन हुआ ।

(ग) और (घ) हां महोदय । राजस्थान में मधान-कुधान कोलिहान, और दरीबा के तांबा अयस्क के निक्षेपों से क्रमश: 21,000 टन, 10,000 टन तथा 1,500 टन तांबा धातु प्रति वर्ष उत्पादित होने का अनुमान है । कुछ और भी तांबा निक्षेप हैं अर्थात बिहार में राखा, रोम, सिद्धेश्वर तामा पहाड़ और रामचन्द्र पहाड़; राजस्थान में सलादीपुरा, मद्रास में मामन्दुर, आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुण्डाला और मेलाराम । इन निक्षेपों के बारे में अन्वेषण अभी पूर्ण नहीं हुए है और तांबे के होने वाले उत्पादन को बताना असम्भव नहीं है । तथापित उनके अयस्कों के संचयों का अनुमान निम्न प्रकार है :—

	संचय (मि० टन में)	श्रेणी
(1) राखा	33.80	1.32 प्रतिशत तांबा
(2) रोम सिद्धेश्वर	32.00	1.15 प्रतिशत ,,
(3) तामा पहाड़	25.40	1.2 प्रतिशत ,,
(4) रामचन्द्र पहाड़	1.4	1.0 प्रतिशत ,,
(5) सलादीपुर	15.0	2.82 प्रतिशत तक जस्ता 0.9 प्रतिशत सीसा और तांबा 0.3 प्रतिशत
(6) मामन्दुर	0.9	0.63 प्रतिशत तांबा 2.00 प्रतिशत सीसा और 2.73 प्रतिशत जस्ता

(7) अग्निगुंडाला	11.613	5.78 से 9.59 प्रतिशत सीसा और 1.5 से 1.71 प्रतिशत तांबा
	3.621	3 प्रतिशत सीसा और 0.5 से 0.56 प्रतिशत तांबा
(8) मैलाराम	प्राप्य नहीं	

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने एक खान परीक्षा के रूप में खोलने की शक्य रिपोर्ट तैयार की है जिसके अनुसार लगभग 3500 टन तांबा धातु प्रति वर्ष उत्पादित हो सकेगा।

राजस्थान के सलादीपुर तथा दरीबा राजपुरा में और मद्रास के मामन्दुर में जस्ता अयस्क के संचयों का पता चला है। इसमें अयस्क के संचय के अनुमान के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

	संचय (मिलियन टनों में)	श्रेणी
(1) सलादीपुर	15.00	2.82 प्रतिशत तक जस्ता, 0.9 प्रतिशत सीसा और 0,3 प्रतिशत तांबा
(2) दरीबा-राजपुरा	9.45	5 से 6 प्रतिशत तांबा सीसा और जस्ता
(3) मामंदुर	0.9	0.63 प्रतिशत तांबा 2.00 प्रतिशत सीसा और 2.73 प्रतिशत जस्ता

गोमांस का निर्यात

4257. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत से कितना गोमांस बाहर भेजा गया;

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गोमांस का निर्यात बढ़ गया है और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गाय की खाल का भी निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने मूल्य की खालों का निर्यात किया गया;

(घ) क्या भारत भी अन्य देशों से गोमांस का आयात करता है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन देशों से और गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के गोमांस का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गोमांस के निर्यात पर आजकल प्रतिबन्ध लगा हुआ है। परन्तु गोजातीय अन्य पशुओं का मांस गत पांच वर्षों में जितना निर्यात किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है :

	मूल्य लाख रुपयों में
962–63	2.45
1963–64	3·24

इसके बाद इस मांस का निर्यात नहीं किया गया।

(ख) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी सहयोग

4258. श्री मधु लिमये :
डा० राममनोहर लोहिया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औद्योगिक विकास में विदेशी सहयोग के बारे में एक प्रारूप संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) एक ऐसा नीति वक्तव्य तैयार करने के लिये ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है जिसमें विदेशी सहयोग के विषय में सरकार की नीतियों का उल्लेख होगा। इसे अन्तिम रूप से तैयार करने में अभी समय लगेगा। इस वक्तव्य के तैयार हो जाने पर इसे सभा-पटल रख दिया जायेगा।

विदेशी फर्मों को रायल्टी

4259. डा० राममनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों/कम्पनियों को रायल्टी देने के प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार इस विषय पर कोई कानून बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पन्ना की हीरे की खानें

4260. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की पन्ना हीरा परियोजना पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने मूल्य की हीरे की खानें हैं तथा सरकार को उनसे प्रति वर्ष कितनी रायल्टी मिलती है ;

(ग) क्या पन्ना हीरा परियोजना को चलाने में कोई हानि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इस हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मार्च 1967 के अन्त तक पन्ना हीरा परियोजना पर 189.76 लाख रुपये की राशि व्यय की है।

(ख) 1963–64 के दौरान निकाले गये तथा बेचे गये हीरों और उनसे प्राप्त हुए स्वामित्व की मात्रा नीचे दी जाती है :—

	1963	1964	1965	1966
निकाले गये हीरे (कैरेटों में)	719.84	1061.75	1358.73	875.48
बेचे गये हीरे (कैरेटों में)	607.65	763.18	854.00	1553.71
विक्रय मूल्य (रुपयों में)	7,41,928	3,95,510	6,12,182	14,45,180
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्वामित्व (रुपयों में)	1,48,386	79,102	1,22,436	2,89,036

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की पन्ना हीरा खनन योजना जिसमें रामखेड़िया और मझगवान की दो खानें शामिल हैं, अभी निर्माण अवस्था में है। अतः हानि होने अथवा हानि को रोकने के उपाय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि पूर्वेक्षण तथा

सीमित खनन परीक्षण कार्यों के दौरान, मई 1967 के अन्त तक 10601 कैरेट हीरे प्राप्त हुए हैं। इसमें से अभी तक 6,791 कैरेट हीरे 29.30 लाख रुपये के बेचे जा चुके हैं।

भिलाई में नेहरू संस्कृति भवन (नेहरू हाउस आन कल्चर)

4261. श्री बाबूराव पटेल : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई में नेहरू संस्कृति भवन के निर्माण पर कितना खर्च किया गया है और इसका विशिष्ट प्रयोजन क्या है;

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है, नेहरू भवन पर खर्च की गई राशि को बचाया जा सकता था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नेहरू सांस्कृतिक भवन लगभग ढ ई लाख रुपये की लागत से तैयार हुआ है। यह भवन भिलाई के सामूहिक समाज के, जिसमें भारत के सभी भागों के नागरिक हैं, बहुमुखी सांस्कृतिक जीवन के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रगतिशील उपक्रम में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ खर्च करना अनिवार्य है।

(ग) सरकार इस बात की विशेष रूप से इच्छुक है कि उनके कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण का समुचित ध्यान रखा जाय।

भारती मिल्स, पांडिचेरी

4262. श्री उमानाथ : श्री रमानी :
श्री प० गोपालन : श्री चक्रपाणि :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पांडिचेरी स्थित भारती मिल्स को अपने हाथ में लेने के बाद वहां उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) मिल्स के बन्द होने से पहले वहां लगे कुल मजदूरों तथा कर्मचारियों की संख्या क्या थी ;

(घ) सरकार द्वारा मिल्स को अपने हाथ में लेने के बाद कितने मजदूरों तथा कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया गया है; और

(ङ) यदि पुनः काम पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या मिल्स के बन्द होने के समय काम पर लगे लोगों की कुल संख्या से कम है तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 फरवरी, 1967 ।

(ग) लगभग 1200 श्रमिक ।

(घ) 827 श्रमिक ।

(ङ) सभी कारीगरों को काम पर न लगाये जाने का कारण यह है कि मिल के पुनः चालू होने के बाद उसमें कुल 25000 तकुओं और 386 करघों में से केवल 16000 तकुए और 144 करघे काम कर रहे हैं ।

भारती मिल्स, पांडिचेरी

4263. श्री उमानाथ :　　　　**श्री रमानी :**
श्री प० गोपालन :　　　　**श्री चक्रपाणि :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती मिल्स, पांडिचेरी के सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने पर ऐसे मज़दूरों की छंटनी की गई है जो मिल्स के बन्द होने से पहले काम पर लगे हुए थे, यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ख) क्या उनको कोई प्रतिकर दिया गया है; और यदि हां, तो किस आधार पर;

(ग) क्या कुछ मजदूर रोजगार के बिना रह गये हैं अथवा छंटनी कर दिये गये हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और सरकार उन्हें किस प्रकार रोजगार देना चाहती है; और

(घ) क्या मिल्स के सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने पर काम में वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार द्वारा मिल को अपने हाथ में लिये जाने के बाद लगभग 500 स्थायी और अस्थायी मजदूरों की, जिनमें अर्ध-क्लर्क भी सम्मिलित है, छंटनी की गई है ।

(ख) 268 श्रमिकों को औद्योगिक वाद-विवाद अधिनियम के अनुसार प्रतिकर दे दिया गया है और शेष श्रमिकों को वर्गों में विभाजित करके दिया जा रहा है ।

(ग) श्रमिक जिन्हें पुनः काम पर लगाया गया या जिनकी छंटनी की गई ।

(घ) जी, नहीं ।

पहाड़ा स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना

4264. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जून, 1967 को उत्तर रेलवे में मिर्जापुर और चुनार रेलवे स्टेशनों के बीच पहाड़ा रेलवे स्टेशन के निकट हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी की एक बोगी के पटरी से उतर जाने के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति घायल हुए थे;

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे; और

(घ) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) 10 जून 1967 को जबकि 11 अप हावड़ा दिल्ली ऐक्सप्रेस पहाड़ा स्टेशन के अप स्टार्टर तथा अप एडवांसड् स्टार्टर सिगनलों के बीच रूकी, तो यह पाया गया कि इंजिन से सातवें से नवें डिब्बों के बफर परस्पर फंसे हुए हैं। जब गाड़ी रूकी तो कोई भी डिब्बा रेलवे पटरी से उतरा हुआ नहीं पाया गया। इस दुर्घटना में 8 लोगों को मामूली चोट आई।

(ग) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है।

(घ) रेलवे को लगभग 5575 रुपये की हानि हुई।

गोग्रा में रेल के माल डिब्बों की उपलब्धता

4265. श्री शिकरे : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कोलेम, कैले और करचोरेम स्टेशनों से मरमागोआ पत्तन तक लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के परिवहन के लिये गोआ में खान मालिकों को पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे देने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोग के लिये कितने मालडिब्बों की आवश्यकता है और किस हद तक उनकी कमी है; और

(ग) खान मालिकों की असुविधा को कम करने और अयस्क के शीघ्र परिवहन के लिये, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा साधन है सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) रेलवे गोवा-क्षेत्र में लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के यातायात की मांग को पूरा करने के लिये पूर्णतः तैयार है। वहां माल डिब्बों की कमी नहीं है और गोआ क्षेत्र में माल के यातायात के लिये जितनी भी मांगे थी उनको इस समय पूरा किया जा रहा है।

रेलगाड़ियों से रेलवे उपकरणों की चोरी

4266. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों से उनमें लगे हुए सामान तथा उपकरण की चोरी की घटनायें बहुत अधिक बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में और चालू वर्ष में अब तक सारे देश में रेलवे को इसके कारण कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि इन कार्यवाहियों का कोई परिणाम निकला है, तो क्या ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1965–66 की तुलना में 1966–67 में रेलगाड़ियों में लगा जो सामान और उपकरण चोरी में चला गया है, उसका कुल मूल्य कुछ अधिक है ।

(ख) 1966–67 में रेलवे को कुल 20,67,111 रुपये की हानि हुई है और अप्रेल से मई 1967 तक चालू वर्ष में 2,72,836 रुपये की हानि हुई है ।

(ग) रेलवे प्रशासन इस बात का प्रयास करता है कि उन स्थानों का पता लगाया जाये जहां से चोरियां की जाती हैं और साथ ही अपराधियों और चोरी के माल को प्राप्त करने वालों का पता लगाया जाये । कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी हैं । जैसे बिजली के सामान को डिब्बों में बन्द कर दिया जाता है, वेल्डिंग कर दिया जाता है और तार आदि को चौखटे के नीचे लगाया जाता है, ताकि असामाजिक तत्व इसे चुरा न सके ।

(घ) निम्नलिखित आंकड़ों से मालूम होता है कि 1965–66 की अपेक्षा 1966–67 में रेलवे सुरक्षा बल के प्रयासों के परिणामस्वरुप कुछ अधिक माल बरामद किया गया है :

वर्ष	बरामद किये गये माल का मूल्य (रुपयों में)	पकड़े गये लोगों की संख्या
1965–66	3,34,057	1313
1966–67	4,40,415	1554

मैसूर राज्य के धारवार जिले में पैदा होने वाली कपास

4267. **श्री श्रगाड़ी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में रायचूर जिले के तीन तालुकों यथा कोप्पल, येलबुरगी तथा कुश्तीगी में उत्पादित कपास का मैसूर राज्य के धारवार जिले में उत्पादित 'ए' श्रेणी की कपास के साथ वर्गीकरण करने का निश्चय किया गया था;

(ख) मैसूर सरकार को इस निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये किस तारीख को निदेश दिया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निर्णय को छः वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(घ) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) जी, हां । 1961–62 के मौसम (सितम्बर, 1961) से ऐसा कर दिया गया है । कपास नियन्त्रण आदेश 1955 के उपबन्धों के अनुसार कपड़ा आयुक्त द्वारा कपास का मूल्य नियंत्रित करने के उद्देश्य से कपास

का वर्गीकरण किया गया था। राज्य सरकारों का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये इस मामले में मैसूर सरकार को अनुदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर में कपास परिवहन जांच-पड़ताल चौकियां

4268. श्री अगाड़ी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में कोप्पल येलबुर्गी और कुश्तिगी तालुकों और धारवार जिले की सीमाओं के बीच अभी तक कपास परिवहन जांच पड़ताल चौकियां विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त तीनों तालुकों में कपास उत्पादकों का माल ढोने वाले लोगों पर धारवार जिले के अधिकारियों द्वारा मुकद्दमे चलाये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो जून 1961 से अब तक कितने मुकद्दमे चलाये गये है, जांच-पड़ताल चौकियों पर कितने मामले पकड़े गये किन्तु जिन पर मुकद्दमा नहीं चलाया गया, और ये सब घटनाएं किन-किन तारीखों को हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बस्तर में कागज बनाने का कारखाना

4269. श्री झा सुन्दरलाल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है निकट भविष्य में बस्तर (मध्य प्रदेश) में कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) बस्तर जिले के दंडकारण्य में कागज बनाने के कारखाने की स्थापना की सम्भावना पर फिलाहाल विचार किया जा रहा है।

Import of Milk Powder

4270. Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the value of milk powder, butter, ghee and cheese imported from abroad during the last five years; and

(b) the value of milk powder received free of cost from foreign countries during the same period ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a)

		Value in lakhs of Rs.	
Year	Milk Powder	Butter & Ghee	Cheese & Curd
1961–62	760.49	0.01	4.36
1662–63	756.95	–	6.03
1963–64	790.33	0.28	20.98
1964 65	658.87	50.14	2.86
1965–66	614.26	69.56	2.94

(b)	1961–62	* N. A,
	1962 63	513.43
	1963-64	751,06
	1964 65	582.31
	1965-66	983.40

Use of Hindi in the Ministry of I. D. and C. A.

4271. Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Raj Sewak Yadav :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) the Member of sectinns in the Administrative Divisions of his Ministry where the work is done originally in Hindi;

(b) whether it is a fact that the demand by the high officers for English translation of papers recaived and documents prepared originally in Hindi, is the main obstacle in the development of Hindi; and

(c) if so, the steps taken to remove the said obstacle ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) None of the Sctions has yet started to do work in Hindi.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

Hindi work in Railway Ministry

4273. Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

* N. A, : Not available

(a) the number of sections in the Administrative Division of his Ministry where the work is done originally in Hindi;

(b) whether it is a fact that the demand by the high officers for the English translation of the papers received and documents prepared originally in Hindi is the main obstacle in the use of Hindi; and

(c) if so, the steps taken to remove the said obstacle ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) One

(b) No.

(c) does not arise.

रेलवे में गन्ने की चोरी

4274. **श्री मु० कु० तापड़िया** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के मार्ग में गन्ना लूटने तथा उसकी चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) 1966-67 में इस प्रकार की कितनी घटनायें हुई ; और

(ग) इन घटनाओं को भविष्य में न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) 1966-67 के दौरान केवल उत्तर-पूर्व रेलवे पर गन्ने की चोरी की चार शिकायतें मिली है तथा 1965-66 में भी इतनी ही शिकायतें मिली थी।

(ग) मार्ग में गन्ने की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं ;

(एक) गन्ने से लदी गाड़ियों पर कड़ी नजर रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं ;

(दो) गन्ने के मौसम में गन्ने से लदी पूरी गाड़ियों की रक्षा के लिए अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाते हैं ; और

(तीन) रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी गन्ने से लदे डिब्बों की रक्षा करने वाले कारखाने के चौकीदारों की भी सहायता करते हैं।

उत्तर रेलवे के लखनउ डिवीजन में माल बेचने का ठेका

4275. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में 14 ठेकेदारों को केवल एक वर्ष के लिये माल बेचने का ठेका दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्यतया ये ठेके तीन वर्ष के लिये दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सामान्यतः माल बेचने के ठेके तीन वर्ष के लिये दिये जाते हैं और यदि ठेकेदार की सेवा संतोषप्रद होती है तो ठेके की अवधि पुनः बढ़ा दी जाती है। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के 18 ठेकेदारों के ठेके 1967 के दौरान माल बेचने के ठेके एक वर्ष के लिये बढ़ाये गये थे क्योंकि उनकी सेवा संतोषजनक नहीं थी, उन्हें अपनी सेवा सुधारने का यह एक और मौका दिया गया है। यदि उनकी सेवा न सुधरी तो उनके ठेके समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

लखनऊ डिवीजन में भोजन व्यवस्था के बारे में शिकायतें

4276. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में आमिष तथा निरामिष भोजन परोसने की व्यवस्था के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) क्या 1965-66 में प्राप्त हुई शिकायतों की तुलना में इन शिकायतों की संख्या बढ़ रही है ;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 30।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

N. E. Railway Training School, Muzaffarpur

4277. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Molahu Prasad :

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Apprentices recruited from the open market were provided free messing against the departmental rules in the North-Eastern Railway Training School, Muzaffarpur from October, 1961 to Decemer, 1965 resulting in expenditure of Rs. 22397.77 p; and

(b) if so, the name of the Officer held responsible for this lapse and the action taken against him ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The entire question of over payment involved and fixation of responsibility is under consideration.

Railway Loco Workshp, Banda

4279. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees working in the Loco Workshop at Banda Junction on the Jhansi-Manikpur Railway section; and

(b) the number of Fitters amongst them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) 117.

(b) 6.

कालोल स्टेशन के निकट माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

4280. **श्री मेघचन्द्र :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जून, 1967 को पश्चिमी रेलवे के कलोल स्टेशन के निकट मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो पटरी से उतरने के क्या कारण थे और उसके परिणाम स्वरूप कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सन्तालपुर के निकट माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

4281. **श्री मेधचन्द्र :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि 12-6-67 को पश्चिमी रेलवे के सन्तालपुर रेलवे स्टेशन के निकट मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो पटरी से उतरने के कारण क्या थे और इसके परिणाम स्वरूप कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सन्तालपुर स्टेशन पर 11-8-1967 को एक मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई थी । जिसके परिणाम स्वरूप 13 माल डिब्बे पटरी से उतर कर पलट गये थे और एक माल डिब्बे के अगले दोनों पहिये उत्तर गये थे ।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है। रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान लगभग 18000 रुपये लगाया गया है।

Conversion of M. G. Line Between Barauni and Katihar into B. G.

4282. Shri Sitaram Kesri : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether there is a scheme to convert the metre-gauge line between Barauni and Katihar into a broad-gauge line; and

(b) if so, when that scheme is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Export of Spices to Sudan

4283. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Gopal Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Aurjnn Singh Bhadoria :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great demand of Indian spices in Sudan;

(b) whether Government are formulating any scheme to promote the consumption of Indian spices in other countries; and

(c) the quantity of spices exported to different countries and the amount of foreign exchange earned thereby during 1966-67 ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) A total quantity of 48,000 M. Tonnes of spices worth Rs. 26.2 crores was exported to different countries during 1966-67.

Prices of Imported Tractors

4284. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ramavtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shai Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of imported tractors are less than those of the indigenously manufactured tractors;

(b) whether it is due to the fact that duty on imported tractors is less; and

(c) if so, whether Government are formulating a scheme to give incentive to the Indian manufactures of tractors ?

The Minister of Industrial Develoment and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes.

(b) Tractors ment for agricultural purposes are exempt from customs duty. However, the cost of indigenous tractors is comparatively high for various reasons such as high cost of imported and indigenously bought out components, high cost of raw materials, payment of customs duty on certain components which can be used in other industries besides agricultural tractors, etc.

(c) Government are providing all possible facilities to the indigenous manufacturers to maximise their production. exchange for the import of plant and machinery required by them as also for the import of components and raw materials.

हिमाचल प्रदेश को नियत की गई लोहे की नालीदार चादर

4285. श्री हेमराज : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में हिमाचल प्रदेश को लोहे की नालीदार चादरों की कितनी मात्रा मंजूर की गई ; और

(ख) उक्त अवधि में इसमें से कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क)

	1965-66	492 टन
	1966-67	1341 टन
(ख)	1965-66	407 टन
	1966-67	1289 टन

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्यात

4286. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 20 करोड़ रुपये की लागत का निर्यात किया और क्या इस्पात निर्यातक संघ ने इस राशि को चुनौती दी है ;

(ख) यदि हां, तो संघ के अनुसार उक्त वर्ष में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कितना निर्यात किया गया ;

(ग) क्या सरकारी आंकड़ों और उपरोक्त संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में अन्तर के बारे में जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच से क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : 1966-67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 8.79 करोड़ रुपये के कच्चे लोहे और इस्पात का

निर्यात किया। इस राशि के बारे में कोई विवाद नहीं है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्यात किये गये माल को शामिल करके, भारत का 1966-67 के वर्ष का कच्चे लोहे और इस्पात का कुल निर्यात 20 करोड़ रुपये का था।

मैसूर में उद्योगों की स्थापना

4287. **श्री क० लकप्पा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना काल में सरकार का मैसूर राज्य में नये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है और क्या इस उद्देश्य के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य के कुरकुन्ता में सीमेंट कारखाना और बेलरी-होस्पेट लोह-अयस्क परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इन परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं। और लोह अयस्क परियोजना के सम्बन्ध में आगे पूछताछ जारी है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

4288. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कुल कितना धन लगा हुआ है ;

(ख) विनियोजन से कितना मुनाफा होता है ; और

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31-3-67 तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पर लगभग 162 करोड़ रुपये लगाया जा चुका है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के चालन को सुचारु बनाने के उद्देश्य से उसके पुनर्गठन के बारे में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

मैसूर में तुमकुर जिले में नये उद्योगों की स्थापना

4289. **श्री क० लकप्पा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में नये उद्योग स्थापित करने का तब वचन दिया था जब वहां पर पोलीटेक्निक भवन का उद्घाटन करने गये थे ;

(ख) यदि हां तो उसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Loco Running Staff Committee, E. Rly.

4290. Shri Ramavtar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Eastern Railway Loco Running Stalf Committee have submitted a memorandum to him and to the General Manager, Eastern Railway in connection with their eleven-point demands;

(b) if so, the nature of their demands and the time by which Government propose to meet them, and

(c) if not, the reason therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as received.

नकली रेशमी धागे की कीमत

4291. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नकली रेशमी धागे पर मूल्य और वितरण नियंत्रण' के हटाये जाने के बाद धागे की कीमत 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कीमतों में असामान्य वृद्धि हो जाने के कारण नकली रेशम का बुनाई का उद्योग ठप्प हो गया है और अमृतसर में दो लाख से भी अधिक कारीगर बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'मूल्य तथा वितरण नियंत्रण' हटाने के बाद सरकार ने राहत देने के लिये उत्पादन शुल्क कम कर दिया है परन्तु इससे कातने वालों को लाभ हुआ है, उपभोक्ताओं को नहीं ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । हां सरकार को अमृतसर के कुछ एककों से ऐसी खबर मिली है कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं ।

(द) जी नहीं।

(घ) सरकार बुनाई उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है और सरकार ने उनकी सहायता के लिये 6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा नाइलोन के धागे के आयात के लिये नियत की है। इसका आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा। परन्तु आयात में कुछ देरी इसलिये हुई क्योंकि यह माल उधार मंगाया जाना था। संश्लिष्ट धागे (सिन्थेटिक यार्न) की सप्लाई के बारे में राज्य व्यापार निगम ने जापान, पश्चिमी जर्मनी तथा अमरीका के साथ लगभग 2.09 करोड़ रुपये के मूल्य का एक समझौता किया है तथा जुलाई 1967 के अन्त तक माल आना शुरू हो जायगा। देशी रेयन धागे का मूल्य आयातित या देशी संश्लिष्ट धागे की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है। जैसे ही संश्लिष्ट धागा आना शुरू होगा तैसे विस्कोज और रेशेदार धागे की कीमतों में सामंजस्य होगा और वे उचित स्तर पर ठहर जायेंगी।

नकली रेशम उद्योग

4292. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको नकली रेशम उद्योग की समस्याओं के बारे में पंजाब उद्योग तथा वाणिज्य संस्था अमृतसर की ओर से अप्रैल 1967 को कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में अन्य बातों के अतिरिक्त त्रिपक्षीय समिति का निर्माण मूल्य तथा वितरण नियन्त्रण लागत ढांचे से प्रशुल्क आयोग द्वारा जांच सूत के कारखाना द्वारा मूल्य निर्धारित करने राज्य व्यापार निगम द्वारा नकली सूत का तुरन्त आयात तथा व्यवहार्य निर्यात नीति की घोषणा की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) नकली रेशम उद्योग की सहायता करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

सरकार उन कठिनाइयों से अवगत है जो नकली रेशम बुनने वालों के सामने नकली रेशमी धागा उचित दामों पर न मिलने के कारण आती हैं। देशी सैलूलोज धागों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, केवल संश्लिष्ट धागे का अभाव है, जो 6-6-1966 से पहले नकली रेशम के कपड़े से सम्बन्धित इ० पी० स्कीम के अधीन आयात दी जाती थी। सरकार यह पहले ही घोषणा कर चुकी है कि नकली रेशमी कपड़े के निर्यात और संश्लिष्ट धागे के आयात के सम्बन्ध में क्या क्या उपाय किये जायेंगे। ऐसी एक योजना तैयार की गई है जिसके अधीन राज्य व्यापार निगम के सह-नियातकों को देशी धागा रियायती दामों पर मिलेगा और उन्हें नकद सहायता भी मिलेगी। जहां तक संश्लिष्ट धागे का सम्बन्ध है, 6 करोड रुपये के मूल्य के धागे का विदेशों से विदेशी ऋण के अधीन मंगाने का प्रबन्ध कर लिया गया है। राज्य व्यापार निगम ने जापान, पश्चिमो जर्मनी

के और अमरीकी व्यापारियों से 2.09 करोड़ के समझौते से कर लिये हैं और अगले महीने के अन्त तक आना शुरु हो जायेगा। देशी रेयन धागे का मूल्य आयातित या देशी संश्लिष्ट धागे की उपलब्धता से जुड़ा है। जैसे ही संश्लिष्ट धागा आना शुरू हो जायेगा वैसे ही विस्कोज और रेशेदार धागे की कीमतों में सामंजस्य स्थापित हो जायेगा और वे उचित स्तर पर ठहर जायेगी। इस सुझाव पर कि कताई पर आने वाले खर्च और बुनाई उद्योग के लिए धागे का उचित मूल्य स्थिर करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कातने वालों, बुनकरों और सरकार के प्रतिनिधियों की समिति बनाई जाये, रेयन और संश्लिष्ट रेशे/धागे पर लगे नये उत्पादन शुल्कों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

Export of Locks

4293. **Shri Brambanadji**
Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Y. S. Kushwah

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a great demand of Aligarh locks in the foreign countries,

(b) if so, the companies which have decided to export locks,

(c) whether Government have decided to give some assistance to these Companies; and

(d) the value of locks exported during the last five years ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Official statistics of exports are maintained for a commodity as a whole and not on unit wise or regional basis. However, Czechoslovakia has shown interest in the import of Aligarh locks and has imported locks of the value of Rs 16 lakhs in 1965-66. Further export orders of the value of about Rs 32 lakhs are understood to be under negotiation with the same country.

(b) The main parties exporting locks and padlocks from Aligarh are the following :

1. M/s Implements Mfg. Co., Aligarh
2. ,, Allen & Alvan Pvt. Ltd., Aligarh.
3. ,, Eden & Co. Pvt. Ltd., Aligarh.
4. ,, Indian Trading Corporation, Aligarh.
5. ,, Mona & Co., Aligarh.
6. ,, May & Co., Aligarh.
7. P. P. Products, Aligarh.

(c) Assistance against exports given by the Government is not unit wise but for export comodity as a whole. The assistance presently available is as follows :--

1. Brass locks & padlocks ;
Import replenishment 60% of f. o. b. value
Cash assistance 10% of f. o. b, value

2. Ferrous locks & padlocks :
Import replenishment 5% of f. o. b. value
Cash assistance 20% of f. o. b. value.

(d) Foreign exchange earned by export of locks during the last five years is as follows :

Year	Value in '000' of Rs.
1962-63	642
1963-64	975
1964-65	1123
1965-66	2886
1966-67 (Upto February, 1967)	1098

औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली

4295. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशानिक सुधार आयोग के एक उच्च शक्ति प्राप्त अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि कि औद्योगिक लाइसेंस देने की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार करली हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुछ लोगों के हाथ में ही आर्थिक शक्ति आ जाने के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशें और औद्योगिक लाइसेंस पद्धति से सम्बन्धित सभी समस्याएं सरकार के विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

4296. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समदाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बेलाडिला में कच्चे लोहे का कारखाना तथा पैल्लेटाइजेशन प्लांट

4297. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश मेंबेलाडिला के स्थान पर प्रस्तावित कच्चे लोहे का कारखाना तथा पैल्लेटाइजेशन प्लांट स्थापित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : बेलादिला में पिग आयरन प्लांट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जहां तक गुल्लिकायें बनाने के प्लांट का सम्बन्ध है, कच्चे लोहे के चूर्ण से गुल्लिकाएं बनाने की योजना बनाने से पहले, यह आवश्यक है कि उस विशेष कच्चे लोहे के अयस्क की गुल्लिकाएं बनाने के लिए उपयुक्तता के बारे में तकनीकी अध्ययन किये जांय । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो कि कच्चा लोहा परियोजनाओं की योजनाएं बनाने और उनको पूरा करने के लिये सरकारी निकाय है । ने बेलादिला के कच्चे लोहे के चूर्ण से गुल्लिकाएं बनाने की शक्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक अमरीकी फर्म से बात चीत शुरू की थी । अमरीकी फर्म द्वारा इसमें अपर्याप्त दिलचस्पी लेने के कारण यह प्रस्ताव छोड़ देना पड़ा । इसके बाद निगम ने यह कार्य जापानी फर्म को सौंपा । अध्ययन चल रहा है गुल्लिकाएं बनाने का प्लांट स्थापित करने का निर्णय इन अध्ययनों के परिणामों पर आश्रित होगा ।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

4298. **श्री गा० शं मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उज्जैन में टेलीफोन तार कारखाना; पूर्वी मध्य प्रदेश में कागज तथा लुगदी का कारखाना की स्थापना में विलम्ब होने अथवा उन्हें समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सरकारी क्षेत्र की तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

टेलीफोन केबल कारखाना

दूसरे केबल कारखाने के स्थान के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने 10 स्थानों में से एक के रूप में उज्जैन की सिफारिश की थी ।

अन्य राज्य सरकारों से इसी प्रकार की सिफारिशें प्राप्त हुई थीं । इन प्रस्तावों पर गौर से विचार किया गया था । तकनीकी सुविधाओं, जलवायु की हालतों और निर्मित

वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी बातों पर विचार करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश किये गये किसी भी स्थान को उपयुक्त नहीं पाया गया था। हैदराबाद के निकट चेरापल्ली के स्थान पर दूसरा केवल कारखाना स्थापित करने के लिये पहले से ही निर्णय कर लिया गया है।

कागज तथा लुगदी कारखाना : मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य क्षेत्र में एक कागज। लुगदी कारखाना स्थापित करने के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है और वह विचाराधीन है।

मशीनी औजार कारखाना : आरम्भ में यह प्रस्ताव था कि हिन्दुस्तान मशीनरी औजार लिमिटेड का एक कारखाना चतुर्थ योजनावधि के अन्त तक मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाये। चूंकि मशीनी औजारों की मांग हाल में काफी गिर गई इसलिये कम्पनी ने अपनी विस्तार योजनाओं को फिल्हाल स्थगित कर दिया है। कुछ समय तक मण्डी की प्रवृत्ति का निरीक्षण करने के पश्चात वे स्थिति का पुर्नावलोकन करेंगे।

रेलवे द्वारा ऐल्यूमिना फेरिक का आयात

4299. श्री सु० कु० तापड़िया
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि जनवरी-फरवरी 1967 के दौरान रेलवे ने 1 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन ऐल्यूमिना फैरिक आयात किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं विशेष रूप से जबकि वह वस्तु भारत में बनाई जारही है।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई कारों के बारे में बुकिंग

4300. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई कारों की बुकिंग में कमी हो रही है;

(ख) जनवरी 1967 से लेकर अब तक मासवार कितनी कारें बुक की गई है और 1965 तथा 1966 में इसी अवधि में कितनी कारें बुक की गई थी; और

(ग) ऐसे मामले, कितने हैं जिनमें लोगों ने विभिन्न कारें बुक करा रखी हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

4301. श्री न० कु० सांघी :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के सब प्रक्रमों में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या विस्तार के सभी प्रक्रमों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के द्वितीय तथा तृतीय चरण के बारे में जानना चाहते हैं। जहां तक द्वितीय चरण में विस्तार का सम्बन्ध है, जिससे कारखाने के पिण्ड उत्पादन की वार्षिक क्षमता 1 मिलियन टन से बढ़कर 1.6 मिलियन टन हो जायेगी, धमन भट्टी नं० चार को गर्म करने का कार्य आरम्भ हो चुका है और आशा है कि काक ओवन और उपोत्पाद संयंत्र का कार्यभार जुलाई 1967 तक ले लिया जायेगा, ऐसी आशा है कि सितम्बर 1967 तक जब कि स्केल्प मिल तैयार हो जायेगा । कारखाने का विस्तार पूरा हो जायेगा । कई कारणों से प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सकी है–इनमें धमन भट्टी में होने वाली दुर्घटना, श्रमिक अशांति और कुछ ठेकेदारों द्वारा समय पर कार्य पूरा न करना भी सम्मिलित है । कारखाने के विस्तार के तृतीय चरण के बारे में, जिसमें कारखाने की क्षमता 1.6 मिलियन टन इस्पात पिण्ड से बढ़कर 3.4 मिलियन टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष हो जायेगी, अभी विचार किया जा रहा है ।

Collision at Ranipur Station

4302. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train and a passenger train were involved in an accident at Ranipur Railway Station on the 8th June, 1967;

(b) if so, the number of passengers who were seriously injured and the number of those who lost their lives as a result there of; and

(c) the persons who were at fault for the said accident ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes

(b) Only one passenger sustained grievous injuries. No one was killed in the accident.

(c) A statutory enquiry into this accident was held by the Additional Commissioner of Railway Safety, Bombay. He has not finalised his report so far.

इंजीनियरी सामान का निर्यात

4303. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में इंजीनियरी सामान के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अप्रैल 1966 से फरवरी 1967 तक के दौरान 1965–66 की उसी अवधि की अपेक्षा इंजीनियरी के सामान के निर्यात में 8 लाख डालर की गिरावट हुई है (मार्च 1967 के सरकारी आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं)।

(ख) अवमूल्यन और निर्यात सहायता की समाप्ति के पश्चात समायोजन की अवधि थी जिसका आरम्भ में निर्यात पर बुरा असर पड़ा। पुनरीजित सहायता अगस्त, 1966 में घोषित की गई थी और उसके बाद प्रवृत्तियां प्रोत्साहन रही हैं।

(ग) सरकार द्वारा किये गये उपचारीय उपाय इस प्रकार है :—

(1) पंजीयत निर्यातकों के लिये आयात नीति का लागू किया जाना जिसके अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग आने वाली आयातित सामग्री और पुर्जों को बदलने के लिये आयात की अनुमति दी जाती है।

(2) चुनीदा वस्तुओं पर 10 प्रतिशत तक नकदी के रूप में सहायता;

(3) निर्यात के सामान के उत्पादन के लिये स्वदेशी लोहा और इस्पात की पूर्ति।

भारतीय इस्पात का निर्यात

4304 **श्री गा० शं० मिश्र** :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन कौन से देशों को भारतीय इस्पात तथा इस्पात उत्पादकों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) गत वर्ष प्रत्येक देश को कितना निर्यात किया गया तथा इस वर्ष कितना निर्यात किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) गत वर्ष तथा इस वर्ष प्रत्येक देश को बिलेट का कितना निर्यात किया गया ;

(घ) क्या देश में बिलेट की पहले ही कमी; और

(ङ) यदि हां तो कितनी कमी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : 1966-67 में भारतीय इस्पात के निर्यात का देशवार विवरण **[सभा पटल पर रखा जाता है देखिये संख्या एल० टी० 872/67]** चालू वर्ष में कितना निर्यात किया जायेगा और किन किन देशों को किया जायेगा प्राप्त होने वाले आर्डरों पर निर्भर करेगा ।

(ग) गत वर्ष बिलेट का निर्यात नहीं किया गया । इस वर्ष में अभी तक 11,300 टन बिलेट जापान को और 9,900 टन बिलेट पश्चिमी कोरिया को भेजे गये हैं ।

(घ) पुनर्वलन मिलों जी मांग घट जाने के कारण, इस समय कमी नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

4305 श्री रा० बरुआ : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार करने लिये अन्तिम रूप से अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : इस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

कपड़ा मिलों द्वारा रुई का स्टाक जमा करना

4306. श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है कि कुछ सूती कपड़ा मिलें रुई के स्टाक जमा कर रही हैं;

(ख) यदि हां तो उसके परिणाम क्या हैं;

(ग) इस बारे में दोषी पाई गई मिलों के नाम क्या हैं; और

(घ) इन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) से (घ) कुछ मिलों द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक रूई का स्टाक रखने सम्बन्ध में सामान्य आरोप लगाये गये हैं और उनकी जांच चालू है।

सवारी कारों का निर्माण

4307. श्री योगेन्द्र शर्मा:
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवायकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बनाई जा रही सवारी कारों का स्तर बहुत गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी कारों की किस्म को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में निर्मित सवारी कारों में दोषों के बारे में शिकायतें बढ़ती रही हैं।

(ख) और (ग) देश में निर्मित कारों के गिरते हुए स्तर के कारणों की जांच करने और उपचारीय उपाय सुझाने के लिये सरकार का विचार एक समिति नियुक्त करने का है।

रेलवे विद्युतीकरण के कलकत्ता डिवीजन के कर्मचारी

4308 श्री उमानाथ : **श्री मुहम्द इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री अब्राहम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिया था कि विद्युतीकरण परियोजना के कलकत्ता डिविजन के जिन कर्मचारियों की छंटनी की जाने की सम्भावना है, उन्हें छंटनी के बाद अन्य पदों पर लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें नोटिस देने से पहले उन कर्मचारियों को अन्य पदों पर लगाया जाये; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ख) और (ग) कर्मचारियों और कुछ संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। छंटनी किये गये कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु निर्माण कार्य पूरा होने पर यह संभव न होगा कि मजदूरों को छुट्टी न दे।

देहरादून के निकट फास्फेट के भण्डारों का पाया जाना

4309 श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या इस्पात, तथा खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में देहरादून के निकट फास्फेट के बड़े भन्डार पाये गये थे;

(ख) यदि हां तो वाणिज्यिक आधार पर उन्हें निकालने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन भण्डारों में पाये गये फास्फेट की किस्म, मात्रा तथा सम्भावित उपयोगों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) इन निक्षेपों के वाणिज्य विदोहन की योजना पर तभी विचार किया जायेगा जब कि फास्फोरस अयस्क की प्राप्तिओं के विस्तृत अन्वेषण पूर्ण हो जायेंगे। इन अन्वेषणों द्वारा खनिज की श्रेणी तथा उसके गुण को निश्चय करना है और इसको कम खर्च पर निकालने के तरीके का और शोधन करने के साध्य तरीके का पता लगाना है। इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बड़े पैमाने मानचित्रण, व्यधन, गढे और खाइयों आदि खोदने का काम करने के लिये विस्तृत अनुसंधान कर रही है। अयस्क के नमूने अभिशोधन तथा दूसरे परिक्षणों के लिये वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भेजे गये हैं।

यह भी प्रस्ताव है कि इन अनुसंधानों तथा धातु कार्मिक परिक्षणों के लिये फास्फोरस भूविज्ञान और खनन सम्बन्धी विदेशी विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता प्राप्त की जाय। इस विषय में कई एजेन्सियों के प्रस्ताव आये हैं जो विचाराधीन हैं।

(ग) अनुमान है कि हर सौ मीटर की गहराई में 8 से 10 मिलियन टन के स्तर के संभावित संचय हैं जिसमें 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत फास्फोरिक आक्साइड है। फास्फेट की चट्टानें यदि उपयुक्त हुई तो फास्फेटिक उर्वरक बनाने में प्रयोग की जायेगी। निक्षेपों की वर्तमान विस्तृत जांचों के पूर्ण हो जाने पर इसके दूसरे प्रयोगों की सम्भावनाओं का पता लगाया जायेगा।

भिलाई तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात कारखाने

4310 श्री शिव चन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि रुरकेला, दुर्गापुर और बुकारो स्थित इस्पात कारखानों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो आंशिक रूप से कुप्रबन्ध तथा आंशिक रूप से विदेशी सहयोगियों के साथ किये गये करारों की प्रतिकूल शर्तों के कारण है;

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या भिलाई इस्पात कारखाने को, जो विदेशी सहयोग से बना है, इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भिलाई इस्पात कारखाने के लिये विदेशी सहयोगियों के साथ किये गये करार की शर्ते रुरकेला, दुर्गापुर और बुकारो के करारों की शर्तों से किस प्रकार भिन्न है ?

इस्पात,खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ) : निस्सन्देह सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को भी गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों जैसे टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी और इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी की तरह असंतोषजनक तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के कच्चे माल, कर्मचारियों की अधिकता मजदूर संबन्ध तथा इस्पात की मांग में कमी आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं देश की परिस्थितियों में अन्तरनिहित हैं। इनका सम्बन्ध उन बाह्य स्त्रोतों से नहीं है जिनसे इन कारखानों के निर्णय के लिए सहायता ली गई है। इन समस्याओं को हल करने के लिऐ कच्चे माल की कमी किस्म में सुधार करने, कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत करने,और उत्पादन को मांग के अनुरुप बनाने आदि के प्रश्नों पर विशेष रुप से ध्यान दिया जा रहा है।

बोकारो अभी निर्णय की प्रथमावस्था में है अतः दूसरे इस्पात कारखानों की तरह यहां परिचालन संबन्धी समस्याएं नहीं हैं।

छोटी कार का निर्माण

3311 श्री कामेश्वर सिंह :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री बीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री सिद्धेवर प्रसाद :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली एक फर्म ने सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके अन्तर्गत पहले वर्ष में एक मुश्त 8,000 छोटी कारों का निर्माण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रया है;

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) कार की वास्तविक की लागत कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समावाय कार्य मंत्री (श्री फखरुदीन अली अहमद) : (क) से (ग) कम लागत की कार के निर्माण के लिये एक उपक्रम स्थापित करने के लिये दिल्ली की एक फर्म से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आरम्भ में इसकी क्षमता 8,000 कार प्रति वर्ष होगी और चतुर्थ वर्ष में 25,000 कार प्रतिशत होगी। आस्ट्रेलिया की एक फर्म से सहयोग प्राप्त करने का विचार है। यह दावा किया गया है कि कार की कीमत 7,000 रु० होगी। यह कहा गया है कि परियोजना के लिये अपेक्षित संयंम और मशीनें विदेशी सहयोग कर्ता द्वारा दी जावेगी जिसे पुनर्भुगतान पांच वर्षों में भारत में निर्यात कार के पुर्जों के निर्यात द्वारा दिया जायेगा। यह दावा किया जाता है कि कार 100 प्रतिशत स्वदेशी होगी।

(घ) देष में कम कीमत की कारों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा प्राप्त किये गये कई प्रस्तावों में से यह एक है।

जैसा कि अन्य मामलों में प्रस्ताव के बारे में अतिरिक्त जानकारी जानने के लिये फर्म को एक प्रश्नावली भेजी गई है।

Powerlooms in Madhya Pradesh

4312. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the number of licences issued for powerlooms in Madhey Pradesh during 1965-66 and 1966-67 separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : No permit was issued during 1965-66. During 1966-67, 2060 permits covering 2925 powerlooms were issued.

Reservation at Burhanpur Railway Station

4313. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Burhanpur on the Central Railway have to face great difficulties in getting the reservation of first class at Burhanpur Railway Station;

(b) if so, the reasons therefor; and

c) whether Government propose to make such arrangements that the first class passengers may not face difficulties in getting reservations ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) No, if the reservation is asked for well in-advance. Burhanpur does not suffer from any peculiar disadvantages in this matter and the position there is similar to what obtains at other stations from where trains do not originate and where traffic justification does not exist for earmarking a separate quota for reservation.

(c) In view of position explained in reply to parts (a) and (b), no special arrangements can be contemplated for Burhanpur station.

Manufacture of Implements

4314. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the steps being take to increase the production and to bring efficiency in the public sector in the matter of manufacturing impliments for industrial proposes ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

औद्योगिक बस्तियां

4315. श्री हेमराज : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में राज्य-वार, तथा संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी ग्राम्य तथा शहरी औद्योगिक बस्तियों की मंजूरी दी गई थी और कितनी स्थापित की गई;

(ख) राज्यवार तथा संघ राज्यक्षेत्रवार ऐसी कितनी बस्तियों में औद्योगिक कार्य आरम्भ हो गया है और कितनी बस्तियां बेकार पड़ी हैं:

(ग) वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में राज्यवार ऐसी कितनी बस्तियों की मंजूरी दी गई थी और कितनी स्थापित की गई; और

(घ) कितनी बस्तियों में राज्य-वार तथा संघ राज्यक्षेत्रवार उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

आमों को बिहार से होकर ले जाना

4316. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के पश्चिम बंगाल में पश्चिम दीनाजपुर के प्रसिद्ध आम उत्पादक जिलों से बिहार से हो कर जाने वाली रेलवे लाइन से आमों को ले जाने से रोक दिया है;

(ख) क्या एक मात्र रेलवे लाइन, जो बिहार में से होकर जाती है और पश्चिम बंगाल के दो आम उत्पादक जिलों को शेष राज्य से मिलाती है, यदि बन्द कर दी जायेगी, तो समस्त पूर्वी भारत की जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और उड़ीसा शामिल है, आम की मंडियों में उथल पुथल हो जायेगी; और

(ग) क्या बिहार सरकार ने बिहार से होकर रेलवे द्वारा पश्चिमी बंगाल के आमों को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) पश्चिम बंगाल के जिलों से आम फराका के रास्ते भी ले जाये जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, खरड़

4317. श्री बृज भूषण लाल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरड़ (चंडीगढ़ के निकट) पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड ने वर्ष 1964-65 और 1965-66 में क्रमशः लाखों रुपयों का लाभ तथा घाटा दिखाया है, जबकि इस अवधि में बिक्री प्रायः बराबर हुई थी;

(ख) क्या हेर फेर करने के कारण उपर्युक्त अवधि में यह लाभ तथा घाटा दिखाया गया है;

(ग) क्या इस कम्पनी के कुप्रबन्ध के बारे में सरकार की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1964-65 तथा 1965-66 के वर्षों में कम्पनी ने, क्रमशः 273-59 तथा 259-64 लाख रुपयों के बराबर निबल विक्रय किया। कम्पनी ने, 1964-65 के वर्ष में 5.36 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया, परन्तु अनुवर्ती वर्ष में, कम्पनी ने 38-68 लाख रुपयों के बराबर, संघृत हानियां उठाई।

(ख) तथा (घ) विभाग ने कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अधीन, कम्पनी के लेखे की किताबों के निरीक्षण का आदेश दिया है। निरीक्षण अभी तक प्रगति पर है, व सरकार के लिये, कम्पनी के कार्य परिणाम की घटा-बढ़ी के बारे में कोई राय प्रगट करना सम्भव नहीं है।

(ग) हां, श्रीमान्।

निर्यात व्यापार के लिए विदेशी सहयोग

4318. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री प० गोपालन :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात व्यापार के क्षेत्र में विदेशी सहयोग की मंजूरी का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कहां से प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2802 के उत्तर में शुद्धि

Correction in Answer to Unstarred Question No. 2802

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : लोक सभा में 16-6-67 को मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 2802 का निम्नलिखित उत्तर दिया था :

(सयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित एक टन स्टैण्डर्ड ग्रेड इस्पात का मूल्य)

मद	1-5-67 से पहले गम्य स्थान के	1-5-67 के पश्चात गम्य स्थान के रेलवे	मूल्य में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि

	रेलवे स्टेशन तक	स्टेशन तक निष्प्रभार		
पहिए और टायर +				
नये डिजाइन के	1286	1356	70	5
पुराने डिजाइन के	1140	1373	233	20
धुरे +				
नये डिजाइन के	1394	1464	70	5
पुराने डिजाइन के	1109	1342	233	21

+ एफ० ओ० आर० वर्क्स

संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा तारीख 1–5–67 को जो मूल्य घोषित किये गये थे उनमें गलती थी जो उन्होंने ठीक कर दी है। सही मूल्य निम्नलिखित है :–

पहिए और टायर +				
नये डिजाइन के	1286	1356	70	5
पुराने डिजाइन के	1140	1210	70	6
धुरे +				
नये डिजाइन के	1394	1464	70	5
पुराने डिजाइन के	1109	1179	70	6

+ एफ० ओ० आर० वर्क्स

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत आ रहे अनाज के एक जहाज को संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा रोक लिये जाने और जुर्माने के तौर पर 27.000 टन अनाज उतारने के आदेश का समाचार।

Shri Kameshwer Singh (Khagaria) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

> "Reported detention of an India bound ship by U. A. R. and order to unload the 27,000 tons of good grains as fine."

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : समूचे संयुक्त अरब गणराज्य के हवाई अड्डों और पट्टियों पर तथा नहरों के कुछ प्रतिष्ठानों पर इसराईल के भारी हवाई हमले के साथ 5 जून को सवेरे पश्चिम एशिया में लड़ाई छिड़ गई। 5 जून को संयुक्त अरब गणराज्य के सूत्रों ने

कहा कि इस नहर के पश्चिमी भाग में कब्रैथ में एक फ्रांसीसी तेलवाहक पर बम गिराकर इसराईल ने नहर बन्द करने की कोशिश की । किन्तु 5 तारीख की ही शाम को संयुक्त अरब गणराज्य ने खबर दी कि नहर खुली रही । 6 तारीख को सबेरे संयुक्त अरब गणराज्य की सर्वोच्च कमान की विज्ञप्ति में लड़ाई छिड़ जाने के कारण सभी जहाजों के लिए स्वेज नहर बंद किए जाने की घोषणा की गई ।

एक ही ऐसा जहाज था जिसमें भारत के लिए माल आ रहा था और जो रोक लिया गया था और अब भी नहर ही में रुका हुआ है । यह जहाज अमरीकी ध्वज तेलवाहक 'ओब्ज़रवर' है जिसमें भारत के लिए 27,400 टन 'मिलो' है । इस जहाज के अतिरिक्त इस नहर में चौदह और भी जहाज रुके हुए हैं जिनमें से 4 ब्रिटेन के हैं, 1 अमरीका, 2 पश्चिम जर्मनी के, 2 स्वीडन के, 2 पोलैंड के, 1 फ्रांस का, 1 चेकोस्लावाकिया का और 1 बलगेरिया का है । भारतीय ध्वज वाला कोई भी जहाज इस नहर में नहीं रुका है ।

जहां तक अमरीकी तेलवाहक 'ओब्ज़रवर' का प्रश्न है जो कि भारत के लिए 'मिलो' ला रहा है, वाशिंगटन-स्थित अपने दूतावास से प्राप्त एक संदेश के अनुसार 6 जून को इस जहाज के मालिकों को जहाज के मास्टर से एक संदेश मिला जिसमें लिखा हुआ था :

> "मरम्मत पूरी हो गई है 061800 जेड । एबीएस का सर्टिफिकेट जारी हो गया है यात्रा पर आगे जाने की इजाजत का इंतजार है इस्माइलिया जो कि लंगर डाले खड़ा है आपसे इस संदेश की यथा शीघ्र पावती देने का निवेदन करता है, डब्ल्युसीसी स्टेशन का इस्तेमाल करें ।"

इस जहाज के मालिकों के नाम जहाज के मास्टर के संदेश से यह पता चलता है कि जब स्वेज नहर बंद थी तब इस तेलवाहक की मरम्मत हो रही थी । इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि इस जहाज को संयुक्त अरब गणराज्य ने रोका है । अगर इस जहाज में मरम्मत की ज़रूरत न होती तो इस बात की पूरी संभावना थी कि लड़ाई छिड़ जाने के बाद स्वेज नहर बंद होने से पूर्व ही वह इसमें से निकल आता । इस समय यह जहाज और 14 अन्य जहाज़ भी स्वेज नहर में रुके पड़े हैं जो कि इसराईल और संयुक्त अरब गणराज्य की लड़ाई के दौरान इसमें डूब जाने वाले छोटे बड़े जलयानों की वजह से बन्द हो गई है । जहां तक नहर में रुके हुए अन्य जहाजों के साथ इस जहाज को भी छोड़ने का प्रश्न है, यह तभी संभव है जबकि डूबे हुए जहाजों को नहर में से निकाल लिया जाए । संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने कह दिया है कि इस नहर को साफ करने का काम तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसराईली सैनिक इस नहर के तट पर कब्जा किए हुए हैं ।

जहां तक अमरीकी तेलवाहक 'ओब्जरवर' में आने वाले खाद्यान्न पर कब्जा कर लेने की खबर का सवाल है, सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार यह खबर ठीक नहीं है ।

इस नहर का बंद हो जाना भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है क्योंकि तेलवाहक 'ओब्जरवर' के रुक जाने के अतिरिक्त, भारतीय और किराए के दूसरे जहाजों को अब 'केप' होकर लाना पड़ेगा जिससे विलम्ब हो जाएगा और खर्चा अधिक पड़ेगा । लेकिन यह स्थिति

उन अन्य 8 देशों के लिए भी इतनी ही चिंता का विषय है जिनके जहाज इस नहर में रुके हैं, और स्वेज के पूर्व में स्थित उन सभी देशों के लिए भी जिनका इस नहर से सामान्य यातायात होता है। इसके साथ ही इस नहर के बंद हो जाने का अभिप्राय है संयुक्त अरब गणराज्य को भारी वित्तीय हानि। इसलिए यह समझना चाहिए कि अगर संयुक्त अरब गणराज्य इस नहर को नहीं खोल पा रहा है तो इसके जरूर कोई अपरिहार्य कारण होंगे, प्रमुखतः उन इलाकों से जिनमें कि इस नहर का पूर्वी तट भी शामिल है, इसराईली सैनिकों की वापसी का सुनिश्चय करने की आवश्यकता, जिनपर कि उन्होंने हाल की लड़ाई में कब्जा कर लिया है।

श्री रणधीर सिंह (खलीलाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 372 उप्र के अन्तर्गत ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :इस नियम में अब संशोधन कर दिया गया है कि जिनके नाम में ध्यान दिलाने वाली सूचना हो वह अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Kameshwar Singh : Sir, I want to know (1) Whether there is really such a situation in the Suez Canal due to its closure as does not allow the passage of this vessel including 14 others or it is detained by the U. A. R. on the instigation of Pakistan and (2) whether the release of this vessel together with those stranded in the Canal depends on the unloading of foodgrains.

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, इस जहाज को बाहर नहीं लाया जा सकता क्योंकि स्वेज नहर बन्द है और इसमें कई जहाज डुबोये गये हैं। संयुक्त अरब गणराज्य यदि इस नहर को फिर से खोलने का निश्चय भी करता है, तो भी इसे जहाजों के आने-जाने योग्य बनाने में कुछ समय लगेगा। ....

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह सूचना, जो कि कुछ समाचार पत्रों तथा न्यूज एजेंसी रिपोर्टों में प्रकाशित हुई है, झूठ है। इसमें वास्तव में 'मिलों' लदा हुआ है और संयुक्त अरब गणराज्य न तो इस अनाज को उतारना चाहता है और न ही उसे लेना चाहता है। वह सूचना गलत है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : The hon. Minister has just now stated that the U. A. R. Government is not interested in unloading it. They are not trying to unload the grain. I would like to draw the attention of the Minister to this news item in the "New York Times".

"Joseph Curran, President of the National Maritime Union and Jessie Calhoon, President of the National Marine Engineers Beneficial Association, charged in a telegram to Secretary of State, Dean Rusk, that the Egyptians were Subjecting the crews of the two ships to "harshtreatment" and that the Egyptian authorities were trying to force the grain-carrying tanker "observer" to unload her cargo" as the price of release".

I want to know whether the Minister has gone through this news item or whether he is in the know of it and (2) Whether any appeal, on behalf of the Prime Minister, has since been made to president Nasser that India bound ships particularly those carrying foodgrains including those already stranded in the canal may be permitted to pass through the Suze even if its closure continues for a further period ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक "न्यूयार्क टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार का सम्बन्ध है, इसमें दी गई सूचना सच नहीं है। इस रिपोर्ट में कोई सचाई नहीं है। यह वक्तव्य कि संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारी अनाज उतारने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्णतः गलत है।

जहां तक इस जहाज के कर्मचारियों के प्रति बर्ताव का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

जहां तक राष्ट्रपति नासर से अपील करने का सम्बन्ध है, हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं और हमारे राजदूत की संयुक्त अरब गणराज्य सरकार के साथ इस मामले में बात–चीत चल रही हैं। स्वेज नहर के पूर्वी तथा पश्चिमी-दोनों ही किनारों पर इसरायली सेना बैठी हुई है, इसलिये जब तक स्वेज नहर पूरी तौर पर संयुक्त अरब गणराज्य के नियंत्रण में नहीं आता, उससे होकर जहाजों का गुजरना खतरे से खाली नहीं है। एक बात यह भी है कि तकनीकी दृष्टि से स्वेज नहर में वास्तविक स्थिति ऐसी है जहां से जहाज निकालना संभव नहीं है।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लोक–सभा में दिये गये विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा देने वाले विवरण।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) मैं, विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्येक विवरण के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

1. विवरण संख्या I	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
2. अनुपूरक विवरण संख्या II	पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
3. अनुपूरक विवरण संख्या IV	सोलहवां सत्र 1966 (तीसरी लोक-सभा)
4. अनुपूरक विवरण संख्या VII	पन्द्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
5. अनुपूरक विवरण संख्या XI	चौदहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक–सभा)

6. अनुपूरक विवरण संख्या XII तेरहवां सत्र, 1966
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 836/67]

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : जहां तक आइटम संख्या 4 का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी ने चार बार यह आश्वासन दिया था कि वह सभा के सदस्यों को रूबी बीमा कम्पनी तथा न्यू एशियाटिक बीमा कम्पनी का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। क्या इस आश्वासन की क्रियान्विति की जायेगी, यदि हां, तो कब ?

डा० रामसुभगसिंह : पिछली बार मैंने एक प्रश्न के उत्तर में श्री स० मो० बनर्जी से कहा था कि मैं सम्बन्धित मंत्री से परामर्श करूंगा और यदि सम्भव हुआ, तो इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा। किन्तु समूचा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखना संभव नहीं है।

श्री स०मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को पिछले सात वर्षों से उठा रहा हूँ। यह एक प्रतिवेदन है और न कि दस्तावेज। यह प्रतिवेदन रूबी बीमा कम्पनी तथा न्यू एशियाटिक बीमा कम्पनी का है जिसका सम्बन्ध बिड़ला हाऊस से है। इस प्रश्न को उठाये आज सात वर्ष बीत चुके हैं लेकिन यह प्रतिवेदन अब तक भी गुप्त ही बना हुआ है। इस बारे में सी० बी० आई० की रिपोर्ट भी है जिसे सरकार अति गोपनीय समझती है। इस प्रतिवेदन को गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह : हमें इसे सभा-पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इसमें गलतियां बहुत हैं, फिर भी यदि आप आदेश दें, तो ऐसा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन है ?

डा० राम सुभगसिंह : जी, हां।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह प्रतिवेदन लगभग पांच-छः वर्ष पुराना है और इस बारे में कई बार प्रश्न उठाये जा चुके हैं। पिछली बार प्रधान-मंत्री ने भी इस पर विचार किया। हमने विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया। यह एक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन है जिसे सरकार ने रूबी बीमा कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त किया था। दुर्भाग्यवश यह प्रतिवेदन एक तरफा है क्योंकि उसने प्रबन्ध से कोई प्रश्न नहीं पूछे और वह विवरण तैयार करता गया जिन्हें गलत पाया गया। अन्ततोगत्वा इसे विधि मंत्रालय में भेजा गया और विधि मंत्रालय ने विभिन्न चीजों पर स्पष्टीकरण मांगा और कई विवरण गलत पाये गये। इसलिए यह निश्चय किया गया कि इसे सभा-पटल पर न रखा जाये। इस सम्बन्ध में कानूनी विशेषज्ञों की राय, तथा की गई कार्यवाही का विवरण भी सभा के समक्ष रखा गया था। इस निर्णय में अब परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

श्री स० मो० बनर्जी : समूचा प्रतिवेदन सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर और आगे बहस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENTS ASSENT TO BILL

सचिव : मैं, चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये पारपत्र विधेयक, 1967 को, जिस पर 24 मई, 1967 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

Third Report

श्री पं० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : मैं आवास निर्माण तथा पूर्ति मंत्रालय–ग्राम्य आवास–के बारे में प्राक्कलन समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

मंहगाई भत्ता आयोग की रिपोर्ट के बारे में

RE : D. A. COMMISSION'S REPORT

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल हमने आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह अनुरोध किया था कि मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करने के लिये अगले सप्ताह में कम से कम दो घन्टे का समय नियत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दें। यदि आप चाहें, तो हम बजट को रोक सकते हैं, और उस पर विचार-विमर्श आरम्भ कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री स० मो० बनर्जी : हम शनिवार को बैठने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं तैयार नहीं हूं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे पत्र के उत्तर में मुझसे यह पूछा था कि मैं इस विषय पर चर्चा सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने से पहले चाहता हूं अथवा उसके बाद और मैंने आपको यह सुझाव दिया था कि चर्चा पहले हो जाये ताकि वित्त-मंत्री को इस सभा के विचारों का लाभ उठाने का मौका मिले। मैं नहीं जानता कि चर्चा

क्यों टाली जा रही है। श्री मोरारजी देसाई कहते हैं कि मैं किसी चर्चा से डरता नहीं, तो फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर स्वतंत्र चर्चा होनी चाहिए।

उप प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : f.सी चर्चा से मेरे डरने का प्रश्न नहीं है। कठिनाई केवल यह है कि चर्चा हो सकती है—उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है— किन्तु जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, मैं सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं कह सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि वे अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, ताकि उस समय, जब सरकार निर्णय लेती है, उनके विचार भी ध्यान में रखे जा सकें।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे इस पर आपत्ति क्यों होने लगी ? वे आय व्ययक के लिये निर्धारित समय से अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

वाणिज्य मंत्रालय-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर और आगे विचार करेंगे।

श्री नन्दकुमार सोमानी अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, वाणिज्य मन्त्रालय को दो महत्वपूर्ण कार्य सौपे गए हैं—पहला व्यावसायिक विपणन और दूसरा कुछ उद्योग, जहां तक सामान्य विपणन कार्यों का सम्बन्ध है, किसी विपणन कार्य का अत्यावश्यक अङ्ग है—अनुसंधान। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस बात का अनुमान लगाया है कि आगामी दस वर्षों में भारत में विभिन्न उद्योगों तथा उपभोक्ताओं की कितनी और क्या-क्या आवश्यकताएं होंगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति देश में कहां तक हो सकेगी। क्या वाणिज्य मन्त्रालय ने इस ओर ध्यान दिया है ?

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम अत्यावश्यक कच्चे माल का एकाधिकार के आधार पर आयात करते हैं। राज्य व्यापार निगम को अपने कार्य में लगाई गई पूंजी का औसतन 39 प्रतिशत लाभ हुआ है।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

औद्योगिक कच्चा माल तथा उर्वरक, अखबारी कागज, औषधियों, तथा दैनिक आवश्यकता की अन्य कई वस्तुओं का आयात करके इतना अधिक लाभ कमाने में कोई औचित्य नहीं है, विश्व में ऐसा कोई निगम नहीं है जो इतना अधिक लाभ अर्जित करता है।

विपणन का दूसरा अत्यावश्यक पहलू यह है कि दुनियां भर में सप्लाई करने वालों के साथ—चाहे वे विश्व के स्वतन्त्र देश हों अथवा साम्यवादी विश्व के—स्थायी तथा दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास किया जाये। लेकिन मैक्सिकों और अमरीका में राज्य व्यापार निगम का नाम इतना बदनाम है कि संसार के प्रमुख सप्लायर उससे बात तक करना नहीं चाहते।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अवमूल्यन से पूर्व पूर्व-अवमूल्यन मूल्य पर तांबे का आयात किया था अब वह अन-बिके स्टाक को अवमूल्यन-पश्चात् मूल्यों पर उद्योग में अनिच्छुक उपभोक्ताओं पर लाद रहा है, हम चाहते हैं कि मन्त्री महोदय उन वस्तुओं की पूरी सूची सभा के समक्ष रखें जिनका आयात अवमूल्यन से पूर्व किया गया था और जिन्हें अब एकाधिकार के आधार पर अवमूल्यन के बाद की कीमत पर बेचा जा रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इतने अधिक उतार-चढ़ाव होते हैं कि इनलिस्टमेन्ट का वार्षिक अथवा द्विवार्षिक कोटा न तो पर्याप्त होगा और न ही अप-टु-डेट होगा। कपड़ा, पटसन, चाय तथा कहवा उद्योगों और कुछ अन्य उद्योगों को दिये गये निर्यात-प्रोत्साहन ऐसे होने चाहिए कि हमारे दोनों ही क्षेत्रों अथात् सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग दूसरों के साथ होड़ करके विश्व बाजार में निर्यात कर सकें। अप्रैल में आगामी 12 महीनों के लिये जिस नीति की घोषणा की गई थी उसका किसी भी प्रकार अनुसरण नहीं किया जा रहा है, हमें अपने निर्यात को, जो कि पिछले कुछ महीनों से गिरता चला आ रहा है, बढ़ाने के लिये युक्तियुक्त आधार पर अपने वाणिज्यिक मार्गों का विकास करना चाहिये और वाणिज्यक जानकारी बढ़ानी चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार की नीतियों का सबसे बड़ा शिकार कपड़ा उद्योग बना है। कपड़े की औसतन 80 प्रतिशत लागत श्रम और रुई पर खर्च के कारण हैं। कई बार इसका उल्लेख किया जा चुका है कि कपड़ा मजदूरों की मजूरी राष्ट्रीय औसत तथा उत्पादकता से सम्बन्धित होनी चाहिए, यह बात समझ में नहीं आती कि भारत में सभी कपड़ा मिलों को एक समान क्यों समझा जाता है, उनमें से कुछ निर्यात—प्रधान हैं। इसलिए उनके साथ विशेष वर्ताव किया जाना चाहिए, कुछ मार्जिनल मिलें हैं जिन्हें सर्वोत्तम तथा यथा समय सहायता दी जानी चाहिए। अन्य मिलें 'बीमार' हैं जिन्हें यथा शीघ्र बन्द करना लाभप्रद तथा उचित है।

राज्य व्यापार निगम एकाधिकार के आधार पर रुई का आयात करता है, जो एक गंभीर स्थिति है, जिस पर मन्त्री महोदय को गंभीर रूप से निष्ठा के साथ तथा बुद्धिमतापूर्ण ढंग से विचार करना जरुरी है। रुई का आयात एक बहुत बड़ा तकनीकी विषय है, रुई की आवश्यकता न केवल सूत की लम्बाई तथा उसकी किस्म के अनुसार घटती-बढ़ती है, बल्कि इसके कई और भी पहलू हैं। राज्य व्यापार निगम यह काम नहीं कर सकेगा चाहे उसे एकाधिकार प्राप्त है, यह कपड़ा उद्योग के हित में नहीं होगा।

हमारे देश के लिए एक गम्भीर चिन्ता की बात यह है कि हम रुपये में भुगतान वाले देशों को जो निर्यात करते हैं, वह अन्य यूरोपीय मण्डियों में पहुँच जाता है और हम उससे जो विदेशी मुद्रा कमा सकते थे उससे वंचित रह जाते हैं और दूसरी ओर वे देश हमारी लागत

पर भारी मुनाफ़ा कमा रहे हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों से आयात में हमें सड़ा-गला माल ही मिलता जो अधिकतर बेकार पड़ा रहता है। इस सारे पहलू की छान-बीन करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो यह देखे कि इन देशों में हो रहे कार्यों से हमें कितना और कहां तक लाभ पहुंच सकता है।

हमारे चाय का निर्यात गिर रहा है, इस मामले में श्रीलंका जैसा छोटा देश हमको पीछे धकेल कर आगे बढ़ गया है। चाय निर्यात में कमी का एक कारण यह भी है कि इङ्गलैंड में हमें चाय मण्डी की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और हमें ब्रिटिश हितों की दया पर बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ता है। सरकार को श्रीलंका सरकार से सबक लेना चाहिए और चाय बोर्ड की सहायता से उचित समय पर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हमारी स्वतन्त्र मार्केटिंग एजेंसियां हो सकें।

Shri P. G. Sen (Purnea): Bihar is passing through famine and scarcity conditions and is facing a grave crisis. The Jute Traders and Jute mills in the State have created an artificial scarcity of jute and with a view to meet this so called shortage of raw jute. This is being imported in huge quantities, by the jute mills whereas the bare fact is that several lakh maunds of raw jute is lying in stock with the merchants and cultivators in Bihar and due to lack of purchasers, the price of raw jute has considerably gone down. I would like to quote a few sentences from the statement issued by the Executive Committee of Bihar Jute Growers and Traders' Association at a meeting held in the second week of April regarding import of raw jute from Thailand ;-

"The Members of the Executive Committee of Bihar Jute Growers' and Traders' Association at a meeting on 9th April, 1967 held at Gulabbag expressed great concern over Governments liberal permission to the jute mills for import of raw jute from Thailand which has very badly affected the economy of the cultivators. Members cited that nearly 4-5 years back, Assam bottom raw jute was sold at Rs. 4-5 per maund higher than the junglee bottom jute of Bihar, but since two years due to heavy imports of raw jute from Thailand by the mills, the Bihar junglee jute is being sold at Rs. 15 per maund lesser than the Assam jute. It should be noted that the major portion of Bihar raw jute is of junglee quality. It is estimated that over 20 lakh maunds of raw jute is still lying in stock with the merchants and cultivators in Bihar to-day. Due to lack of purchasers, the price of junglee raw jute has gone down to Rs. 20 to Rs. 25 per maund effecting the cultivators very seriously. It is surprising that while enough raw jute is available in the country, the mill owners are importing Thailand jute and are intended to consume the foreign jute only to compel the cultivators to bring the prices of Bihar raw jute even lesser.

The Union Government is adding fuel to the fire by granting the mills subsidy of Rs. 9 per maund approximately on the imported raw jute."

So the raw jute is graded as junglee raw jute there. The retired Chairman of the Indian Jute Mills Association is still of the view that there is still a shortage of jute in the State and there is need to import raw jute from Thailand. We had to spend foreign exchange to the tune of Rs. 3.70 crores on 1.35 million bales of jute fibre imported from Thailand. The traders buy raw jute as a group to deprive the cultivators of remunerative prices, Since the jute grower is not getting any incentive in terms of price, he is not taking any interest in augmenting his produce. On the other hand, the rising prices of rice are attracting him towards paddy cultivation. If the present trend continues, our dream to achieve self sufficiency in jute cannot be materialised. On the contrary, when-ever a

demand for the grant of an increase in the price of raw jute is put forth, it is stated by the Indian jute Mills Association that jute mills are not in a position to afford any rise in the price as they are passing through a financial crisis and are finding difficulty in obtaining finance ever for day to day working. The Association approached the Government for reduction in import duty and the Government have sanctioned some money for improvement in colouring and bleaching. It says :—

"We have now received permission from Government to set up our fibre conversion and product development project which will give us 6.4 million."

Frankly speaking, the jute mill and jute traders are making fat profits while the actual grower is being denied or deprived of even the reasonable price for his produce.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न-भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके बाद लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह् भोजन के पश्चात दो बज कर 6 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

Shri P. G. Sen (Purnea) - Mr. Deputy Speaker, Sir there is a Government publication about jute which say something about the jute of Thailand. Their requirement is for 20-lakh bales, but the Government says that there is plenty of demand.

It is stated in that, that the raw jute cultivators have thus been denied the benefit of world prices of jute goods.

The money earned from jute mills is spent on steel. On the one hand they say that they do not have money but on the other hand they are spending money on other items.

The Thailand jute is being imported in an unwise manner. Our jute is not of inferior quality. If you want to improve upon that quality you will have to provide aid for that. Our cultivators do not get much profit. They cannot even earn the money which they spend in weeding out the grass from their fields.

On the other hand the profit of mill owners is increasing day by day. The picture put before you by the mill owners it not correct.

The jute commissioner says that the mills have been asked not to buy raw jute as a group. They should buy jute weekly. But the mill owners do not follow this advice. The mill owners have formed an association but the cultivators have not done so and as such are put to loss.

The profit of our fibres is increasing but the cultivators have earned no profit out of that. Even the Purchase Tax has affected the cultivators and not the traders.

We want our jute to be exported. You may do so through the S. T. C. but I want the cultivators to get profit of it.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि वाणिज्य मंत्री एक आवश्यक निर्यात योजना पर विचार कर रहे हैं। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वह निर्यातकों को नकद प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रोत्साहन भी दें। उस प्रोत्साहन में यह होना चाहिये कि निर्यातक जो बाहर से मंगवाना चाहें मंगवा सकें अथवा बाहर जाना चाहें वे बाहर जा सकें। मैं समझता हूँ कि यह सब से बड़ा प्रोत्साहन होगा।

इस वर्ष गोआ में 7·5 लाख टन कच्चा लोहा उत्पन्न होगा और इस सब का निर्यात किया जायेगा। संसार के देश बड़े-बड़े जहाजों में अपना माल लाद रहे हैं परन्तु गोआ में अब तक छोटे जहाज हैं। वाणिज्यिक हिसाब से मारमागोआ की बन्दरगाह पर माल उतारने का कार्य पूरा हो जाना चाहिये था परन्तु अभी परियोजना की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन ही है।

अवमूल्यन के पश्चात कच्चे लोहे पर निर्यात शुल्क को प्रति टन के हिसाब से लगा दिया गया है जिसके कारण अच्छे और बुरे लोहे पर एक जैसा ही कर है। खराब कच्चे लोहे को बेचना भी कठिन है और निर्यात करने वालों को घाटा रहता है तथा अच्छे कच्चे लोहे के बेचने वाले लाभ में रहते हैं। संयोगवश अच्छे दर्जे का कच्चा लोहा राज्य व्यापार निगम करता है न कि निजी व्यापारी। इस सम्बन्ध में गोआ के निर्यातकों ने कई अभ्यावेदन किये हैं, और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

आयात व्यापार में बहुत लाभ होता है। यह लाभ अधिकतर राज्य व्यापार निगम कमाता है। परन्तु इसमें 80% तो उन वस्तुओं का व्यापार है जिनमें राज्य व्यापार निगम का एकाधिकार है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह यह जांच करें कि किन आयात की हुई वस्तुओं का मूल्य वह कम कर सकते हैं, ताकि यहां जो वस्तुयें उत्पन्न होती हैं उनका मूल्य कम हो सके।

राज्य व्यापार निगम का विचार है कि कपड़े के उद्योग पर भी अपना एकाधिकार कर ले। पहले कपड़ा उद्योग अच्छी अवस्था में था परन्तु सरकार ने इसकी भी अब हालत खराब कर दी है। मैं चाहता हूँ कि वे इस धंधे को अपने हाथ में न लें।

एक समय हम संसार में सब से अधिक चाय का निर्यात करते थे। 1957 में हमारे कुल निर्यात का 45% भाग था; परन्तु अब यह घट कर 34.8% रह गया है। लंका का व्यापार 1957 में 30.2% था परन्तु यह बढ़ कर अब 39 2% हो गया है।

हमें चाय का उन देशों में अधिक निर्यात करना चाहिये जहां से ऐसी विदेशी मुद्रा मिल सके जिसे हम कहीं भी उपयोग कर सकें। दूसरा प्रश्न चाय के सम्बन्ध में यह है कि क्या कारण है कि इसे अभी तक ब्रिटिश चाय एकाधिकार के साथ बांधा हुआ है ? यही कारण है

कि हमारा अमरीका से चाय का व्यापार कम हुआ है, जबकि लंका का व्यापार बढ़ा है। हमें उन देशों में चाय का निर्यात करना चाहिये जहां से स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। चाय बोर्ड को चाहिये कि इस मामले में उन व्यक्तियों का स्वतन्त्र सम्पर्क स्थापित करे जो चाय का कारोबार करते हैं तथा उनकी सहायता करे ताकि वे चाय के व्यापार को बढ़ा सकें।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ढ़ंका) : वाणिज्य मंत्रालय में दो गुण होने चाहिये। एक तो व्यापार करने में निपुणता और दूसरे साहस। ऐसा प्रतीत होता है वर्तमान मंत्रालय में इन दोनों गुणों की कमी है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने मंत्रीजी से एक प्रश्न सट्टे के बारे में पूछा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कानूनी तथा ग़ैर-कानूनी सट्टे के भेद का पता नहीं था। इसी प्रकार का उत्तर उन्होंने गुजरात में कपास के नियन्त्रण के बारे में दिया जब हम उनसे मिलने गये।

गत 15 वर्षों के अनुभव ने बता दिया है कि हमारी व्यापारिक समस्याओं के सुलझाने के लिए एक नई नीति की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकरण से काम नहीं चलेगा क्योंकि आयात तथा निर्यात का राज्य को ठीक ज्ञान नहीं है। हमने कोटा पद्धति द्वारा नियन्त्रण लगा के भी देख लिया तो पता चला कि उसका लाभ भी उपभोक्ता को नहीं होता। देश में जो उत्पादन बढ़ रहा है वह भी ऐसा है कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उनका उत्पादन तो बढ़ रहा है परन्तु जिनकी आवश्यकता है उनका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है।

तीसरा मार्ग मूल्यों के नियन्त्रण का है। सीमेंट तथा लोहे और इस्पात पर से नियन्त्रण हटाये जाने ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वह मिल जाती है। यदि आप कपास पर से भी नियन्त्रण हटा दें तो इसका आपको लाभ ही होगा। यदि इसे आपने कुछ दिन और रखा तो इसका लाभ न तो उत्पादन करने वाले को होगा और न ही व्यापारियों को होगा।

मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि आंकड़ों के हिसाब से व्यापार बढ़ा है अथवा घटा है। इसका कारण यह है कि आयात को बढ़ा कर लिख दिया जाता है तथा निर्यात को कम करके लिख दिया जाता है। इस कारण आंकड़ों से ठीक पता नहीं चल सकता।

आप एक ही प्रश्न अपने मन से पूछिये कि क्या राज्य व्यापार निगम से ठीक कार्य चल गया है ? क्या नियंत्रणों से लाभ हो गया है ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर "नहीं" में होगा। इसलिये अब केवल बाजार का अपने आप कार्य करना ही एक रास्ता रह गया है। आपने आयात तथा निर्यात पर इतने कर लगा रखे हैं; उन्हें हटा क्यों नहीं देते ? आपने अवमूल्यन कर दिया है तो आप इन आयात तथा निर्यात शुल्कों को भी समाप्त कीजिये। इसी प्रकार राज्य व्यापार निगम को भी समाप्त कीजिये। यदि आपने ऐसा किया तो फिर वही वस्तु आयात की जायेंगी जिनकी आवश्यकता होगी। इसी प्रकार आप साहस से निर्णय लीजिये और वह कार्य कीजिये जो आपको 15 वर्षों के अनुभव ने बताया है।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों की चर्चा में भाग लिया है।

स्वतन्त्रता के कुछ समय पश्चात भारत का विदेशों से कुल व्यापार 181.6 करोड़ अमरीकी डालर था। इस वर्ष यह 424.9 करोड़ डालर है। इससे प्रतीत होता है कि यह मंत्रालय कितने बढ़े हुए व्यापार को कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा एक पेचीदा कार्य किया जा रहा है जिसमें एक ओर तो इस देश में आर्थिक गतिविधियों से निपटाना तथा दूसरी ओर विदेशों में अपने व्यापार को प्रोत्साहन देना है।

इन कार्यों को निपुणता से करने के लिए सारे मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया है। एक तो वस्तु अधिकारी तथा दूसरे क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। वस्तु अधिकारियों का कार्य यह है कि निर्यात को बढ़ाया जाये तथा इस कार्य के लिए बाहर जोश पैदा किया जाये और प्रशासनिक कठिनाईयों को दूर किया जाये। यह काम क्षेत्रीय अधिकारियों का है। इन अधिकारियों के नीचे कार्य करने वाले ऐसे लोग हैं जो प्रचार, वित्तीय सहायता, आयात शुल्क कम कराना आदि कार्य करते हैं।

इस मंत्रालय के नीचे सरकारी क्षेत्र के बहुत से कारखाने हैं। यदि कुछ माननीय सदस्य की बात मान कर सब आयात तथा निर्यात शुल्क हटा दिये जायें तो सरकार का कार्य कैसे चलेगा ? स्वतन्त्र व्यापार तथा बिना कंट्रोलों के हम कहां पहुंचेंगे ?

कपड़ा उद्योग जो पहले लाभ में था अब समय के कारण बीमार सा हो गया है। अब हम एक और समय में रह रहे हैं और इसके साथ-साथ हमें परिवर्तन करने होंगे।

स्वतन्त्र दल के सदस्य सरकारी क्षेत्र के कारखानों के विरुद्ध हैं परन्तु हमें उनसे प्यार है और जनता तथा देश को लाभ पहुँचाने के लिये उन्हें और प्रोत्साहन दिया जायेगा।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : हम सरकारी कारखानों के विरुद्ध नहीं है परन्तु यदि देश को उनके द्वारा घाटा हो तो हम विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि आप उनसे लाभ कमायें।

श्री दिनेश सिंह : हां, लाभ से चलायेंगे और मैं आशा करता हूं कि इसमें आपका सहयोग प्राप्त होगा।

राज्य व्यापार निगम की यहां चर्चा हुई है। इसे 11 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। पहले वर्ष 1956–57 में इसका व्यापार 9.19 करोड़ रु० का था और उससे कुल आय 110 लाख रु० की थी तथा लाभ 33 लाख रु० का था। 1966–67 में कुल व्यापार 151.99 करोड़ रु० का हुआ और उससे कुल आय 6.10 करोड़ की हुई तथा लाभ 160 लाख रु० का हुआ। इसी से सदन अन्दाजा लगा सकता है कि यह कम कार्य नहीं है। साथ ही यह आरोप भी असत्य है कि राज्य व्यापार केवल लाभ कमाने में ही लगा हुआ है। यह जो लाभ कमाता है उससे अधिक लाभ तो आयात-निर्यात करने वाला कोई भी परिवार कमाता है।

इस मंत्रालय की जिम्मेदारी यह थी कि निर्यात को बढ़ाये। दुर्भाग्य से आरंभ से ही हमारा व्यापार अच्छी स्थिति में नहीं था। हम उन वस्तुओं का आयात करते हैं जो यहां बनाई नहीं जाती। जनता को यह नहीं भूलना चाहिये कि जो माल हम बाहर से आयात करते हैं

उनका मूल्य हमें वस्तुओं में ही देना पड़ता है। जब तक हम ऐसा अनुभव नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी।

अवमूल्यन का हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ा है। और उसमें 1966–67 में 1965-66 की तुलना में 13.46 करोड़ डालरों की कमी हुई है।

लगातार सूखा का भी हमारे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उस दिशा में जो हमारा व्यापार है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। हमें कच्चा माल भी अधिक मात्रा में आयात करना पड़ा। अच्छी वर्षा होने से ऐसी आशा है कि इस वर्ष इसमें कुछ सुधार होगा।

मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि हम निर्यात की प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर रहे हैं। कपास के उत्पादन में हम संसार में चौथे नम्बर पर हैं। परन्तु हमारे देश में प्रति एकड़ कपास का उत्पादन संसार में सब से कम है। इसी प्रकार हमारा कच्चे पटसन का उत्पादन पाकिस्तान से भी कम है। हमें मुख्य कठिनाई यह हो रही है कि हमारे देश में ही वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। वैसे तो यह अच्छा है, परन्तु इसका निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। अब हमारा ब्रिटेन से व्यापार उतना नहीं रहा जितना पहले था। रूस के साथ 1961–62 में 32.21 करोड़ रु० का था। 1965–66 में यह बढ़ कर 92.92 करोड़ रु० हो गया। इसी प्रकार अमरीका से भी इस अवधि में हमारा व्यापार 28 प्रतिशत अधिक हो गया।

हम आयात के बारे में उदारता का प्रयास कर रहे हैं ताकि उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, परन्तु यह अस्थाई हल ही होगा। हमें अन्ततः निर्यात ही बढ़ाना होगा। मैं सदन के सदस्यों का इसमें सहयोग चाहूँगा।

अन्दरूनी बाजार तथा निर्यात के बारे में बता चुकने के बाद मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से इस देश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को बैठकें करनी चाहियें-चाहे ये बैठकें किसी एक वस्तु पर विचार करने के लिये हों या कई वस्तुओं पर विचार करने के लिये हों, जो भी उन्हें सुविधाजनक हो।

अब में विश्व की वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सात वर्ष पहले जब विश्व के देशों ने यह संकल्प लिया था कि आर्थिक समृद्धि कुछ देशों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये। गरीब देशों के लोगों के दिलों में बड़ी बड़ी आशाएं उत्पन्न हो गई थी जो अच्छा जीवन व्यतीत करने के अधिकार की मांग करते रहे हैं। उन्होंने इस दशाब्दी का नाम विकास दशाब्दी रखा था। परन्तु यह विकास दशाब्दी का संकल्प एक बहकावा ही रहा है और उनकी आशाएं धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि उसके लिये जिस कार्यवाही की आवश्यकता थी, उन्नत देशों द्वारा वह कार्यवाही नहीं की गई है। विकासशील देशों की व्यापार की शर्तें बराबर गिरती ही जा रही हैं क्योंकि विश्व के बढ़ते हुए व्यापार में उनका हिस्सा घटता रहा है और उनकी आयात आवश्यकताओं तथा निर्यात आय में अन्तर बढ़ता रहा है। विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। इसके विपरीत उनकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर कम हो गई है। इससे इन देशों की विकास योजनाओं को बड़ा धक्का पहुंचा है। यह मानता हूं कि हमारे

विकास कार्यक्रमों में मित्र तथा उन्नत देशों ने सहायता दी है, परन्तु विकासशील देशों को दीर्घकालीन पूंजी का प्रवाह निरन्तर धीमा पड़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार तथा विकास सम्बन्धी प्रथम सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि विकसित देशों को अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम एक प्रतिशत भाग विकासशील देशों के विकास के लिये देना चाहिये। इस पर न केवल अमल ही हुआ है, अपितु उनका यह अंशदान जो 1961 में ·84 प्रतिशत था 1965 में घट कर लगभग ·65 प्रतिशत रह गया है।

विकासशील देशों के विदेशी ऋणों की बकाया राशि में बड़ी तेजी से होती जा रही वृद्धि की ओर बार बार हमारा ध्यान दिलाया गया है। इन देशों को इस ऋण से पूरा लाभ नहीं होता है। उन्हें अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक मूल्य देने पड़ते हैं। इसके विपरीत इन ऋणों की अदायगी के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं होती है। ऋण देने वाले देश ऋण प्राप्त करने वाले देशों को निर्धारित मूल्यों पर सामान बेचते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक होते हैं, परन्तु ऋण लेने वाले देश उन्हें अपना सामान नहीं बेच सकते। इसलिये उन्हें ऋण का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है।

कैनेडी दौर से कुछ अच्छे परिणाम निकलने की आशा है। मैं इस विषय पर बाद में विस्तार से वक्तव्य दूंगा।

व्यापार तथा विकास पर संयुक्तराष्ट्र संघ का दूसरा सम्मेलन 1 फरवरी और 25 मार्च, 1968 के बीच नई दिल्ली में होना निश्चित हुआ है। हम आशा करते हैं कि कम विकसित देशों के संघर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में यह सम्मेलन कुछ ठोस परिणामों पर पहुंचेगा। जब यह कहा जाता है कि चाय उद्योग बुरी स्थिति में है और निर्यात घट रहा है तो यह आश्चर्य की बात है कि इस देश से बाहर भेजा जाने वाला वार्षिक मुनाफा कम नहीं हो रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि पूंजी कम हो गई है और पूंजी का निवेश कम होता जा रहा है, किन्तु मुनाफा ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस स्तर पर हम इस देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये इच्छुक हैं। हमारी मध्यम तथा मोटी किस्म की चाय को अच्छी किस्म की चाय की अपेक्षा अधिक स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप मध्यम और मोटी किस्म की चाय का निर्यात कम हो रहा है। हम किसी ऐसे उत्साही और स्वतन्त्र व्यापारी को चाहते हैं जो यहां से मिश्रित चाय को डिब्बों में बन्द करके बेचे, जिससे भारतीय चाय लोकप्रिय बन सके और जिससे हमारे निर्यात पर हमें उचित मुनाफा मिल सके।

हमारे देश में कपास की पैदावार बहुत कम होती है। हमारे पास कपास बहुत कम है और हमारी कपड़े की मिलें बहुत हैं। जब कभी यह मिलें बन्द होती हैं तो सरकार से इन्हें अपने हाथ में लेने के लिये कहा जाता है। हमें कई बार इन बीमार मिलों और बन्द होने वाली मिलों को अपने हाथ में लेना पड़ा था। इनमें से तीन को हमने मिल मालिकों को मुनाफे के साथ वापिस कर दिया था। इसलिये हमने एक ऐसे टेक्सटाइल कारपोरेशन को बनाने की बात सोची जिससे ठीक चल पड़ने पर इन मिलों को उनके मालिकों को वापिस न करना पड़े।

हम चाहते हैं कि रबड़ के उत्पादन में वृद्धि हो। दुर्भाग्य से इस देश में पैदा किये गये रबड़ से इस समय हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती। जहां तक रबड़ के मूल्य का सम्बन्ध है प्रशुल्क आयोग ने इसकी जांच की है और इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। रबड़ के मूल्य निर्धारित करने से पहले हम इस मामले पर विचार करेंगे। इस मामले में केरल सरकार के अधिकारियों और रबड़ बोर्ड से हम पहले से ही विचार–विमर्श कर रहे हैं। मैंने केरल राज्य के मन्त्री को लिखा है कि हमें इस मामले में अन्तिम निर्णय करने से पहले उनके साथ विचार-विमर्श करके बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री वासुदेवन नायर ने कहा है कि यदि सरकार रबड़ उत्पादकों को उचित दाम दिलाएगी तो वे प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को 54000 टन से बढ़ा कर 74000 टन करके दिखा देगें। मैं तो उनके इस आश्वासन के पूरे होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं उन्हें वह सभी संभव सहायता देने के लिये तैयार हूं जो केन्द्रीय सरकार उन्हें दे सकती है।

जहां तक रबड़ के मूल्य का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि छोटे उत्पादकों का हमें बहुत ध्यान है और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही रबड़ के मूल्य निर्धारित किये जायेंगे। एक मुख्य कठिनाई यह है कि छोटे बागानों तथा बड़े बागानों की उत्पादिता में कुछ अन्तर है और यदि हम अधिक मूल्य निर्धारित कर दें तो बड़े बागान मालिक बहुत अधिक मुनाफा कमा लेंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ऐसा नहीं होने देना चाहते।

पटसन उद्योग के सामने जो कठिनाइयां हैं हमें उनकी जानकारी है। हमने इस वर्ष जूट का मूल्य बढ़ा दिया है। इसका समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति मन निर्धारित किया गया है इससे उत्पादकों को सहायता मिलेगी। जहां तक काजू उद्योग का सम्बन्ध है, हम इसका निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। इसका निर्यात देश में इसकी खपत को कम करके भी बढ़ाया जा सकता है।

मेरे मंत्रालय, उससे सम्बद्ध कार्यालयों तथा कुछ कारपोरेशनों के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि ये सभी संस्थान पूर्णतया त्रुटि रहित हैं। परन्तु मैं इस सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अधीन किसी भी कार्यालय अथवा निगम में जो भी अनियमितता हुई होगी उसका पता लगाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। मैं ऐसे मामलों की जांच करने के लिये भी तैयार हूं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि माननीय सदस्य सभा में किसी मामले के बारे में जानकारी दें किन्तु उन्हें आरम्भ में ही किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं करना चाहिए। इससे कार्य दक्षतापूर्वक नहीं चल सकता है। इस सभा में उठाई गई बातों के कुछ तथ्य मेरे पास हैं। कपड़ा आयुक्त के कार्यालय तथा कुछ दूसरी संस्थाओं के विरुद्ध कुछ विशेष आरोप लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि ये आरोप पहले ही केन्द्रीय जांच विभाग को जांच के लिए सौंप दिये गये हैं और जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनेक मामलों में दोषी पाये गये व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनके बारे में कोई बात छिपाई जाये। किन्तु सदस्यों से मेरा निवेदन है कि तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि उनसे जांच कार्य में सहायता मिले। यदि

हमें कुछ आरोप बिना किसी को मालूम हुए प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें उससे जांच करने में सुविधा होती है क्योंकि जांच कार्य आकस्मिक ढंग से ही अधिक अच्छे ढंग से हो सकता है।

गंधक के आयात के बारे में मामला बार बार इस सभा में उठाया जा रहा है। इस सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अमरीका से गंधक का आयात करने के लिए समझौता किया था। किन्तु गन्धक उत्पादकों तथा अमरीकी सरकार के बीच कुछ मतभेद हो जाने के कारण हमें पूरी मात्रा में गन्धक नहीं मिल सका। कभी कभी इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएं हो ही जाया करती हैं।

विश्व में गन्धक की कमी और बढ़ते हुए मूल्यों तथा भारत की गन्धक सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 28 जून, 1966 को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गन्धक का आयात करने का निर्णय किया गया था। इस निर्णय में, कुछ समय बाद, थोड़ा संशोधन किया गया और 5,000 टन से अधिक नियतन वाले वास्तविक प्रयोक्ताओं को गन्धक का सीधे आयात करने की अनुमति दी गई। राज्य व्यापार निगम को प्रतियोगी मूल्यों पर गन्धक का, जिसमें रुपये में भुगतान करके पोलैंड से आयात किया गया 50,000 टन गन्धक भी शामिल है, आयात करने में पर्याप्त सफलता मिली है। यह प्रणाली अपनाने से हुए लाभ स्पष्ट हैं। इससे देश में गन्धक के मूल्य घटे हैं। इस संशोधित नीति से देश में गन्धक सम्बन्धी स्थिति अधिक खराब नहीं होने पाई। जहां तक ओवल इण्डस्ट्रीज के साथ सौदे का सम्बन्ध है, इस फर्म ने गन्धक उत्पादकों के साथ एक करार किया था। उसने यह बताने के लिए कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे कि उसका खानों के साथ एक करार है जहां से वह गन्धक ले सकती हैं। इस फर्म के साथ किये गये प्रारम्भिक करार में ये खण्ड भी थे कि हमें किसी प्रकार का घाटा न उठाना पड़े। इस फर्म को यह भी बताना पड़ा कि उसके पास गन्धक है और उसने बैंक का भी विवरण दिया। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि यह फर्म करार के अनुसार गन्धक सप्लाई नहीं कर सकी। उन माननीय सदस्यों को जो आयात-निर्यात सम्बन्धी कारोबार से सम्बन्ध रखते हैं, इस बात का अनुभव होगा कि जो सौदे किये जाते हैं उनमें से बहुत से क्रियान्वित नहीं हो सकते हैं और कभी कभी तो उनमें घाटा भी उठाना पड़ता है। हमने इसके लिये इस फर्म पर 75,000 रुपये व्यय का दावा किया था और फर्म हमें यह रकम देने के लिए तैयार हो गई है। हो सकता है कि कुछ मामलों में अनियमितताएं भी हुई हों, किन्तु हमें अपने निगमों के संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए।

उपलब्ध सीमित समय में मैंने अधिक से अधिक बातों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है, यदि कोई बात रह गई हो तो माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं केवल एक जानकारी चाहता हूँ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : केवल एक प्रश्न।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय सीमित समय में काफी बातों का उत्तर दे चुके हैं, माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं श्री मोडी को अपवाद स्वरूप प्रश्न पूछने की अनुमति तभी दे सकता हूं जब सारी सभा इसके लिये सहमत हो।

श्री पीलु मोडी : आज बीस वर्षों के बाद भी हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे पिछड़े क्यों हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कदाचित कुछ माननीय मित्रों के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) - मन्त्री महोदय ने हथकरघा बुनकरों और हथकरघा उत्पादों के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में कल उपमन्त्री महोदय प्रकाश डाल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut motions were put and negative

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा अस्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Ministry of Commerce were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	वाणिज्य मन्त्रालय	29,43,000
2.	विदेशी व्यापार	26,28,25,000
3.	वाणिज्य मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	12,75,32,000
110.	वाणिज्य मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	16,37,000

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTION

छठा प्रतिवेदन

श्री नायनार (पाल घाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 28 जून, 1967 को सभा में उपस्थपित किया गया था, सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 28 जून, 1967 को सभा में उपस्थाति किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खाद्यान्नों की वसूलो की योजना के बारे में संकल्प–जारी

RESOLUTION Re: SCHEME FOR PROCUREMENT OF FOODGRAINS-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खाद्यान्नों की वसूली के बारे में संकल्प पर आगे विचार करेगी।

श्री मु० कु० तापड़िया (पाली) : मुझे अपने संकल्प का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : माननीय सदस्य को अपने संकल्प का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे संकल्प समाप्ति के बाद, मैं इस संकल्प के प्रस्ताव की अनुमति देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री भगवान दास (ओसग्राम) : इस विषय पर इस सभा में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। मुख्य मंत्रियों के 11 अप्रैल, 1967 को हुए सम्मेलन में केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करने का वचन दिया था किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के दो पड़ौसी राज्यों में एक तो कमी वाला राज्य है और दूसरे राज्य में अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा होता है। प्रायः कमी वाले राज्य

अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से घिरे हुये हैं । कमी वाले राज्यों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । इसका परिणाम यह है कि दो पड़ौसी राज्यों में एक ही वस्तु के मूल्यों में भारी अन्तर रहता है । इस प्रकार की असमानता हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है । मुख्य मन्त्री सम्मेलन में दिये गये सुझाव के अनुसार इस असन्तोष पूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय बजट तैयार किया जाना चाहिए । यह कार्य बड़े उत्पादकों द्वारा उत्पादित अधिक खाद्यान्न की एकाधिकार वसूली, अनाज के गैर-सरकारी थोक व्यापार को समाप्त करके तथा देश में उत्पादित अनाज को उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से बेचे जाने की व्यवस्था करके किया जा सकता है । चूंकि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है, अतः सभा द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश दिए जाने चाहिए ।

खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष चूहे तथा कीड़ों द्वारा 2 करोड़ 60 लाख टन अनाज की बरबादी होती है । इसका मुख्य कारण यह है कि बड़े-बड़े उत्पादक और थोक व्यापारी अपने स्टाक को गुप्त गोदामों में छिपा कर रखते हैं । यदि सरकार इस सारे फालतू अनाज को अपने गोदामों में रखने की व्यवस्था कर दे तो इस अनाज को बरबाद होने से बचाया जा सकता है । इस अनाज के बच जाने से हमें अनाज का आयात नहीं करना पड़ेगा ।

यदि सरकार देश के छोटे किसानों को उनकी खड़ी फसल की जमानत पर ऋण देने की व्यवस्था कर दे तो वे उस ऋण को अपने उत्पादों के रूप में वापिस करने को तैयार हैं । यदि किसानों को उचित और निर्धारित मूल्यों में मसाले, चीनी, मिट्टी का तेल आदि जीवनोपयोगी अत्यावश्यक दी जाएं तो वे अपना अनाज नियन्त्रित मूल्यों पर बेचने को तैयार हो जायेंगे ।

वसूली योजना के लिए केवल इस नीति द्वारा ही अधिकांश ग्रामीण-जन का सहयोग मिल सकता है । सरकार को उनका समर्थन पाने के लिए बेकार भूमि का वितरण, छोटी भूमि पर लगान से छूट और दूसरे करों में कमी आदि उपाय करने चाहिए । सरकार निर्धन किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए जितना अधिक करेगी उतना ही उसे वसूली कार्य में अधिक सहायता उनसे मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्रियों को छोड़कर सब दलों के सदस्यों को बोलने का समान अवसर मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों के सदस्यों को बोलने का समान अवसर देने का प्रयत्न करूंगा । हमें मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए नियत समय भी ध्यान में रखना होता है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) इस संकल्प में बड़े उत्पादकों से आवश्यकता से अधिक अनाज की अनिवार्य वसूली की व्यवस्था है । इसमें 15 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को बड़ा उत्पादक कहा गया है ।

{ श्री मनोहरन पीठासीन हुए
Shri Manohran *in the Chair* }

न तो हमारी सरकार ही बहुत ही कार्यकुशल और ईमानदार है, और न इसके एजेन्ट ही ईमानदार और कार्यकुशल हैं । यह भली भांति सिद्ध हो चुका है कि जब भी अनिवार्य वसूली की गई सरकार के पदाधिकारी किसानों के प्रति दुर्व्यवहार ही करते रहे । यही कारण है कि मैंने सदैव ही अनिवार्य वसूली का विरोध किया है ।

सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को अपने अपने क्षेत्रों मे अनाज के भण्डार रखने की परम्परागत प्रणाली अपनाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि संकट के समय वे इन भण्डारों से अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके । इन भन्डारों की जानकारी स्थानीय सरपंचों को दी जानी चाहिए ताकि उनको पता रहे कि किसके पास कितनी मात्रा में अनाज है । यह अनाज इन किसानों से उचित मूल्य पर खरीद कर भूमिहीन किसानों को दिया जा सकता है ।

अनाज की क्षेत्रीय प्रणाली राज्य स्तर आरम्भ होकर तालुक स्तर पहुंच गई है। इस प्रणाली से हम एक स्थान से दूसरे स्थान में अनाज नहीं ले जा सकते हैं; जिससे अभाव वाले क्षेत्रों को दी जानी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है । सरकारी अधिकारी अनुचित बल प्रयोग करके जनता को सताते हैं । मैंने इस व्यवस्था का सदैव ही विरोध किया है ।

इस प्रस्ताव में कई साम्यवादी सिद्धान्तों का भी समावेश किया गया है इसमें कहा गया है कि यदि बड़े किसान अपनी पूरी भूमि पर काश्त न कर सके तो फालतू भूमि उनसे लेकर बांट दी जानी चाहिए । यहां तक कि इसमें यह व्यवस्था है कि इस भूमि में सहकारी और सामूहिक खेती की जाये । इस प्रकार की साम्यवादी विचारधारा का मैं विरोध करता हूं ।

यह दुख की बात है कि किसानों को चोरबाजारी करने वाले तथा जमाखोर कहा जाता है । किसान चोरबाजारी नहीं करते हैं । हमें उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को यथासंभव प्रोत्साहन देने चाहिए और उनसे फालतू अनाज लाभप्रद मूल्यों पर खरीदने चाहिए । कोई भी लोकतंत्रीय देश जो खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनना चाहता है किसानों के साथ चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखोरों के साथ जैसा व्यवहार नहीं कर सकता ।

अनाज अधिक से अधिक उत्पादन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये तथा लाभप्रद और आकर्षक मूल्यों पर अपनी उपज बाजार में लाने के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जावे ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : (जम्मू) मैं श्री रंगा के इस विचार से सहमत हूं कि जब तक किसानों को समाज सम्मान नहीं दिया जाता और उसे समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । इस संकल्प में जो प्रस्ताव किया गया है वह भ्रामक है । मैं अनिवार्य वसूली के पक्ष में नहीं हूं । मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय बजट पर जोर देने के स्थान पर कृषि प्रधान नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता है ।

आज किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे कृषि उत्पादन बढ़ा सकें। देश में उत्पादित अनाज का उचित रूप से वितरण किया जाना चाहिए। यदि देश के किसी भाग में अनाज की कमी होती है तो उस कमी को देश के सभी लोगों में बांटना चाहिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

हमें पिछले 6-7 वर्षों से बताया जारहा है कि सरकार ने कृषि आयोग नियुक्त किया है और वह ऐसे आंकड़े इकट्ठा कर रहा है जिनके आधार पर किसानों को दिये जाने वाले मूल्य निर्धारित किये जायेंगे। किन्तु हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी नहीं है कि अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है। अतः मन्त्री महोदय को बताना चाहिए कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और वास्तव में कितनी प्रगति हुई है। चाहे सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ भी कार्यवाही करे, किन्तु जब तक उत्पादकों को उचित लाभ मिलने का आश्वासन नहीं दिया जाता तब उनसे अधिक उत्पादन की आशा नहीं की जा सकती है।

जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, यह समस्या के केवल एक पहलू का हल है। यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध हो जाये तो वसूली कोई समस्या ही नहीं रह जायेगी। मैं समझता हूं कि अभी अनिवार्य वसूली योजना लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भारत का किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह अपना अनाज बिना बेचे अपने पास एक दिन से अधिक समय तक रोक सकता है क्योंकि उन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिये आवश्यक वस्तुएं खरीदनी होती हैं जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। हमारे देश के 75 प्रतिशत से अधिक किसानों के पास 15 एकड़ से कम भूमि है। अतः उनके लिए अनाज को अपने पास रोक रखना असम्भव है।

यदि मन्त्री महोदय वसूली योजना को क्रियान्वित करना ही चाहते हैं तो सहकारिता को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि किसानों द्वारा पैदा किये जाने वाले आवश्यकता से अधिक अनाज को छिपाये जाने से रोकना है, तो अनाज का राज्य व्यापार किया जाना चाहिए। सरकार को उत्पादकों के तथा वितरण के स्तर पर अनाज को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जब तक दोनों स्तरों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, तब तक समस्या हल नहीं हो सकती है।

Shri George Fernandes : (Bombay-South) : There is a long standing demand for the abolition of food zones so that the whole country becomes one unit. All the political parties agree with it in principle but when the question of implementation of the same comes there is some opposition from certain quarters. This is very unfair on the part of the parties who oppose it.

It has been reported that the headquarters of the good Corporation is being shifted from Madras to Delhi. It would mean unnecessary expenditure will have to be incurred in its shifting, therefore the Government should reconsider its decision in this regard.

The officials of the Food Corporation do not pay any attention to the procurement work. They always try to find an opportunity to make foreign tours. A lot of money has

been wasted on the cancellation of air bookings of these officials. I would request the hon. Minister to give detailed figures in this regard.

While fixing fair prices for the foodgrains Government should also fix fair prices of Commodities required by the farmers. A parity should be maintaind between the prices of foodgrains and other commodities of daily consumption. This is essential from the point of farmers.

According to the figures given by the F. A. O. E. C. A. F. E. and in the President's broadcast on the 26th January, about one third of our agricultural produce amount to about two and a half crores tons is wasted on accourt of a number of verious, If this is stopped we cannot only stop import of foodgrains but we can also be in a position to export something. A definite policy should be laid down in this regard.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : इस संकल्प के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं। वसूली व्यवस्था राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सौंपी गई है। वे अपने राज्यों में अपनी अलग अलग व्यवस्था के अनुसार यह कार्य करते हैं। देश की वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए इस संकल्प का वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं है जिसे क्रियाविन्त किया जा सके। हमारे खाद्य उत्पादन की वर्तमान स्थिति में सम्पूर्ण थोक व्यापार को सरकारी क्षेत्र में लाना वांछनीय नहीं है। श्री जार्ज फरनेन्डीज ने खाद्य निगम के विरुद्ध कुछ शिकायतें की हैं। इन शिकायतों की जांच की जायेगी। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि राज्य व्यापार निगम की कार्य कुशलता बढ़ाने तथा उसमें मितव्ययता बरतने की दिशा में जो कुछ आवश्यक होगा हम करेंगे।

जहां तक खाद्य निगम के मुख्यालय को मद्रास से दिल्ली लाने का सम्बन्ध है, इसके बारे में निर्णय लेते समय संभवतः यह बात ध्यान में रखी गई होगी कि खाद्य निगम का कार्य क्षेत्र अब चावल की वसूली तक ही सीमित नहीं रह गया है, अपितु बहुत बढ़ गया है, इसलिये इसका दिल्ली में होना अधिक उपयुक्त होगा। अब इसे विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क रखना होगा और यह कार्य दिल्ली से ही अधिक सुविधापूर्वक किया जा सकता है। निस्संदेह मुख्यालय के स्थानान्तरण पर कुछ व्यय होगा, किन्तु मंत्रालय ने निर्णय करने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार अवश्य किया होगा। निगम के कार्य तथा इसके अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा के मामलों की विस्तार पूर्वक जांच की जायेगी और यदि अवसर मिला तो मैं इसके बारे में सभा को अवगत कराऊंगा।

हमारी खाद्य समस्या को हल करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बात उपज बढ़ाने की है। हमें अनाज की समस्या खेती में पैदावार बढा कर हल करनी है। हमें किसानों को आश्वासन देना होगा कि उपज बढ़ाने के लिए उन्हें खाद आदि सभी प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी। किसानों के लिए सरकार ने कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की है. किन्तु मैं यह निःसंकोच स्वीकार करता हूँ कि इन सुविधाओं से छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। हमें उपज बढ़ाने के हेतु किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करनी होगी। खाद्यानों के मूल्य निर्धारित करते समय इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलें।

श्री जॉर्ज फरनेन्डीज ने मूल्यों में असमानता का प्रश्न उठाया है। निस्संदेह यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस दिशा में प्रयत्न किये गये हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में अब तक कोई

नीति निर्धारित नहीं की जा सकी है । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसानों के लिए आवश्यक वस्तुओं के प्रचलित मूल्यों को देखते हुए खाद्यानों के मूल्य निर्धारित किये जायें । हमें इसके लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसे कार्य रूप दिया जा सके । जहां तक वसूली का सम्बन्ध हैं, हम अभी किसानों से उनकी आवश्यकता से अधिक अनाज की सारी मात्रा लेने की स्थिति में नहीं हैं । हम किसानों से वसूली के निर्धारित मूल्यों पर कुछ अनाज ले लेते हैं और शेष अनाज किसानों के पास खुले बाजार में प्रचलित मूल्यों पर बेचने के लिए छोड़ देते हैं । खाद्यानों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यही एक मध्य मार्ग अपनाया जा सकता है ।

अब मैं क्षेत्रीय व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं नहीं कहता कि क्षेत्रीय व्यवस्था कोई आदर्श व्यवस्था है। किन्तु वर्तमान अभाव की स्थिति में हमें फालतू अनाज वाले राज्यों से कमी वाले क्षेत्रों के लिये अनाज की व्यवस्था करनी होती है, अतः इस संदर्भ में क्षेत्रीय व्यवस्था लाभप्रद हो सकती है । अनाज का उत्पादन बढ़ जाने पर क्षेत्रीय व्यवस्था स्वयं प्रभावहीन हो जायगी । हम सबका यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपनी शक्ति अनाज का उत्पादन बढ़ाने में लगानी चाहिए । इस कार्य में सभी राजनीतिक दलों तथा सभी सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं को अपना योगदान देना चाहिए ।

कभी कभी यह शिकायत की जाती है कि अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने वाले लोग तो अनाज की वसूली की नीति का पालन करते किन्तु कमी वाले राज्य इस नीति में ढील दे देते हैं । अतः इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हू कि कमी वाले राज्यों को वसूली नीति का पूरी तरह पालन करना चाहिए ।

निःसंदेह बड़ी मात्रा में हमारा अनाज बरबाद होता है । यह बरबादी आरम्भ में बीज बोने के समय से लेकर उपभोग की स्थिति तक होती रहती है । विश्व भर के वैज्ञानिक इस बरबादी को पूरी तरह रोकने के लिये कोई उपयुक्त तरीका निकालने के कार्य में लगे हैं किन्तु उन्हें अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिली है । हमारे यह विवाह आदि उत्सवों के अवसरों पर भोज आदि देने पर भी बड़ी मात्रा में अनाज की बरबादी होती है । इस बरबादी को रोकने के लिये हमें प्रचार द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे लोग इस बरबादी से देश को होने वाली हानि को समझ सकें ।

लगातार तीन वर्षो से पर्याप्त वर्षा न होने के कारण हम गंभीर खाद्य स्थिति का सामना कर रहे हैं । इस स्थिति का सामना करने के लिये दोनों कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों ने हमें पूरा सहयोग दिया है । इस सराहनीय कार्य के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ **Mr. Speaker** *in the chair* }

इस संकल्प के प्रस्तावक ने संकल्प में कुछ ऐसे सिद्धान्तों की व्यवस्था की है जिन्हें क्रियान्वित करने के लिये इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है । अतः इस संकल्प को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

Shri Bhagwan Das: I thank the Minister and to all the hon. member who participated in the lively discussion. In view of the importance of this resolution, I urge that the resolution be put to the vote of House.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Resolution was put and negatived.

तिब्बत के बारे में संकल्प

RESOLUTION Re : TIBET

अध्यक्ष महोदय : अब हम तिब्बत के सम्बन्ध में श्री श्रीचन्द गोयल के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : Mr. Speaker I move my resolution which seeks that Dalai Lama should be recognised as the head of the Emigre Government of Tibet and all facilities and help be extended to him by the Government of India to liberate Tibet from the colonial rule of Communist China.

Tibet was a great country of the world and was connected with India in all the fields whether it was the cultural field or the religious field.

History says that when Tartars invaded Tibet, the latter sought and got the help of Chinese king of that time and thus faced the Tartars. Since then there used to be an agent of China at Lhasa. But in 1911 when the Manchu dynasty was abolished in China due to a revolution there the Tibetans revoked the old agreement of having agent at Lhasa. Even in the Simla convention of 1913-14 Tibet participated as an independent country along with India and China. Later on the Chinese Government withdrew recognition to their representative who participated in the Simla convention. In this way the Chinese have lost even the small claim if any, about their any central over Tibet.

Now conditions in China have changed.

Tibet was a buffer state between China and India. We had cultural contacts with China but these were put an end to when the communist regime came to power in China.

The area of China was only 10 Lakh sq. miles when they constructed a wall but during the last 1500 years they have increased it to 26 Lakh sq. miles. After annexation of Tibet they have 8 Lakh sq. milets move to it. In this way China is three times bigger than India now in area. China has a tendency to expand. Now they have their eyes on India Nepal, Sikkim, Bhutan and similarly the countries of West Asia.

Reverent Patterson crosed the mountains and came to India and informed Nehru that china was to grab Tibet but Nehru did not believe him. Patterson was indicated alt these in a book published by him now.

Our ambassador to China at that time was Sardar Pannikar but he failed in his duty to bring all these facts to the notice of the Government of India. He kept India in the dark about China's intentions. When Peking radio announced to on 24th October 1950 about liberation army in Tibet, they in fact had already annexed Tibet. We should have sided with Tibet at that time. It was necessary to have Tibet as a buffer State between India and China. When the 2500th anniversary of Mahatma Budha was being celebrated the Lamas of Tibet came here and informed Nehru about developments there but the latter sent them back after consoling them that he would write to the Communist Government not to interfere in the internal affairs of Tibet. We even encouraged the slogan "Hindi Chini Bhai Bhai" and signed the Pachsheel Treaty. The Government never informed the people of India about the real intentions of China.

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय सदन में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है। सदस्य महोदय अपना भाषण जारी करें।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarn) : In regard to Tibet we have committed a Himalayan blunder. the people of India will never forgive the Government for its Tibet policy. China has thrown to prices the Panchsheel agreement. Has China behaved with us according to the terms of the agreement where Macmohan line was accepted as boundry between India and China. Even our diplomatic staff in China has not been spared by Chinese. We should announce that Tibet is an independent country. Those countries which believe in the forms of government like us should also recognise the independence of should force U. N. O. also for it.

China is going to attack India again if not soon after some years. if we want to defend our country we shall have to create a buffer state again and get the cooperation of other Tibet. We countries for it.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि दलाई लामा को तिब्बत की प्रवासी सरकार के प्रमुख के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और तिब्बत को साम्यवादी चीन के उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार को उन्हें सभी सुविधायें और सहायता देनी चाहिए।"

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Speaker, I support this resolution. Indians made great sacrifice to win their freedom from the British. I want Sardar Swara Singh not to commit the folly as was done by one of his predecessors. We should reconsider the policy of Tibet and thereby do something which may give comfort to the soul of Sardar Patel.

We should liberate Tibet and give it to Dalai Lama in the same manner as was done by Shri Ram who killed Ravana and restored the kingdom to Shri Vibhikshan. If we do so we will discourage China in its evil designs. We will support you in so doing. Our politicians committed fault during the past. You should undo that. We should help Tibet now.

श्री देवकी नन्दन पटोदिया (जालोर) : 17 वर्ष पूर्व 7 अक्तूबर 1950 को तिब्बत का प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में चीन के राजदूत से बातचीत कर रहा था। उसी समय

चीन की सेनाओं ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। बस फिर उस नसल की समाप्ति आरम्भ हो गई। वह आज भी जारी है। उनकी सम्पत्ति छीन ली और हजारों तिब्बती स्त्री पुरुषों को नपुंसक बना दिया गया। इस प्रकार एक नसल को समाप्त किया जा रहा है। कुछ मन्दिरों को पुलिस चौकियों में परिवर्तित कर दिया है। तिब्बत वाले अपने पड़ौसी भारत पर विश्वास किये बैठे रहे कि वह उनकी रक्षा करेगा। परन्तु हमने उनके साथ धोखा किया। भारत तथा तिब्बत के बीच सांस्कृतिक मेल था।

पहले तो चीन भारत से हजारों मील दूर था परन्तु तिब्बत पर चीन द्वारा कब्जा करने के पश्चात अब वह हमारे सर पर आ बैठे है।

1954 की संधि ने तो तिब्बत पर चीन की स्वायतता भी स्वीकार कर ली है। पहले तो चीन के लोग तिब्बत में सम्मानित व्यक्तियों की भांति रहते थे परन्तु उससे तिब्बत की स्वायतता पर उसका कोई प्रभाव न था।

1876 में चीन की इच्छा के होते हुए भी तिब्बत ने ब्रिटिश मिशन को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं दी। इसी प्रकार दूसरे महायुद्ध में तिब्बत ने ब्रिटेन की युद्ध सामग्री को तिब्बत से होते हुए चीन ले जाने की अनुमति नहीं दी। इन दो उदाहरणों से तिब्बत की प्रभु-सत्ता का पता चलता है। परन्तु 1954 की संधि ने पहली बार तिब्बत पर चीन की स्वायतता को स्वीकार किया। हां उस करार के अनुसार भी चीन को भी तिब्बत को पूरी स्वायतता के अधिकार देने को कहा था। यह भी था कि वे उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे न ही उनके धर्म तथा वहां की सरकार की पद्धति के विरुद्ध कुछ करेंगे। परन्तु चीन ने उन्हें मानने से इन्कार कर दिया। उनका उलंघन किया। इसलिये कोई करार एक तरफा नहीं होता है और इसे अब समाप्त समझा जाये।

दलाई लामा वहां से भाग कर अपने साथियो के साथ भारत आ गया है। उसके पास अपने देश को बचाने के कोई साधन नहीं हैं।

वह भारत पर भरोसा करता है परन्तु भारत ने उसे धोखा दे दिया इसलिये हमें इस समस्या पर फिर से विचार करना होगा।

हमें इस समस्या पर सुरक्षा की दृष्टि से देखना होगा। दूसरे हमें इसे मानवता की दृष्टि से देखना होगा। फिर हमें इसे इतिहास की परम्पराओं की दृष्टि से देखना होगा। मुझे आशा है कि भारत सरकार इन मामलों पर विचार करेगी और दलाई लामा की सरकार को मान्यता देगी तथा उन्हें वहां दृढ़ सरकार बनाने में सहायता देगी। हमें चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने के प्रयास की सहायता नहीं करनी चाहिये। चीन के साथ सम्बन्ध तोड़ लेने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री जे० के० चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम) : स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास ऐसे अनेक अपराधों से भरा पड़ा है, जैसा कि हमने तिब्बत के मामले में किया है। वास्तव में इति-हास की दृष्टि से 20 वर्ष का समय किसी घटना के कारणों तथा उसके प्रभाव को जानने के

लिये पर्याप्त अवधि नहीं है, तथापि हमें अन्ततोगत्वा यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 1954 की सन्धि के कारण चीन ने भारत पर हमला किया।

सर्व प्रथम मैं कहना चाहता हूं कि डाक तार सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध तथा तिब्बत में हमारी सेना की छोटी सी टुकड़ी रखने के कुछ अधिकार भारत को अंग्रेजों से उत्तराधिकार में मिले थे। तिब्बत के साथ हमारे शताब्दियों से अति घनिष्ठ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहे हैं। परन्तु जैसे ही चीन शक्तिशाली हुआ उसने वर्ष 1950 में तिब्बत पर हमला कर दिया। उस समय हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा। 1954 में हम यह विश्वास करके गुमराह हो गये कि तिब्बत चीन का एक स्वायत्तशाली प्रदेश माना जायेगा।

{ **श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए** }
{ **Shri G. S. Dhillon** *in the Chair* }

तिब्बत को एक स्वतंत्र स्वायत्तशाली प्रदेश माना गया था तथा इस सन्धि पर भारत की ओर से अंग्रेजों ने तथा चीन और तिब्बत-तीनों ने हस्ताक्षर किये थे। परन्तु चीन बाहरी तिब्बत के बारे में अपने हस्ताक्षरों से मुकर गया, परन्तु वह आन्तरिक तिब्बत के बारे में अपने हस्ताक्षरों से नहीं मुकर सका। यदि चीन आन्तरिक तिब्बत के बारे में भी अपने हस्ताक्षरों से नहीं मुकरा होता तो वर्तमान स्थिति उत्पन्न न होती तथा तिब्बत भारत और चीन के बीच इसी प्रकार एक मध्यवर्ती राज्य बना रहता, जैसे आउटर मंगोलिया चीन और रूस के बीच एक मध्यवर्ती राज्य है।

वर्ष 1954 के समझौते में मैकमोहन लाइन को मान्यता दी गई थी जिस पर शिमला में हस्ताक्षर हुए थे और वर्ष 1954 तक इसकी यही स्थिति रही जबकि साम्यवादी चीन के अधिकार को भारत द्वारा मान्यता दी गई। ऐसा करके हमने तिब्बत की स्वतंत्रता का सौदा तो किया ही तथा अपनी प्रतिरक्षा का भी सौदा किया। हमने हिमालय तक आने के लिये तथा हिमालय की दूसरी ओर दर्रों के बिलकुल निकट सैनिक संस्थान स्थापित करने और तैयारियां करने के लिये चीन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। इससे 1962 में भारत पर हमला करने का मार्ग साफ हो गया। अब हम अपने आपको बड़ी कठिनाई में पाते हैं। अब हम बहुत डरते हैं क्योंकि दूतावास के झगड़े के समय मैं ने इसी सभा में यह कहते सुना है कि हमें चीन के रवैये का उसी रूप में जवाब नहीं देना चाहिये, कहीं चीन हम पर पुनः हमला न कर दे। हमें चीन के हमले से नहीं डरना चाहिये। हमें अपने अधिकारियों पर दृढ़ रहना चाहिये। हमारा यह दृढ़ निश्चय होना चाहिये कि या तो हम विजय प्राप्त करेंगे अथवा मर जायेंगे। यदि एक भी भारतीय चीन की तलवार से नहीं बचता, तो भी कोई बात नहीं, हमारा इरादा पक्का होना चाहिये।

बड़े राष्ट्रों के इतिहास में महान कार्यों तथा बड़ी घटनाओं में अनुत्तरदायित्व के कुछ अंश पाये जाते हैं। हम राणा प्रताप का भीलों और कोलों की सहायता से मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना आप उसका अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। परन्तु क्या 50 करोड़ भारतीय चीन से नहीं लड़ सकते? हमें चीनी आक्रमण से भयभीत नहीं होना चाहिये। हमें नैतिक और देशभक्ति के आधार पर चीन से लड़ना है और उसे हिमालय पर एक इंच

भूमि भी हथियाने नहीं देना है । हमें ऐसा करना ही होगा । इसमें उत्तरदायित्व और अनुत्तर दायित्व का कोई प्रश्न नहीं है । चीन की शक्ति, उसका अणुबम एवं परमाणुबम हमें डरा नहीं सकते । हमने दलाईलामा के प्रति अपराध किया है । इस लज्जाजनक अध्याय का परिष्करण किया जाना चाहिये । चीन द्वारा रोके जाने पर भी हमें भारत में प्रवासी सरकार स्थापित करके उसके अधिकार का समर्थन करना चाहिये । हमें राष्ट्रसंघ में भी तिब्बत का प्रश्न उठाना चाहिये ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Speaker, no one can deny the fact that it is ultimately due to the weak policy adopted by us towards Tibet during these last 15 or 20 years that China had become a major threat to our security and existence. Had we adopted a tough policy, we would not have found ourselves in the tight corner in which we are finding ourselves to-day. The weak policy adopted by us had not merely done enormous harm to us alone, but it had also distorted India's image in our neighbouring countries like Nepal, Sikkim and Bhutan. Our position in these countries has degraded so much that they are going away from us Even the small state of Sikkim, which was hitherto considered as a part of India, is trying now to declare herself an independent nation. I think it is all due to our weak policy towards Tibet.

Now we should not waste time in discussing the mistakes done by us in regard to Tibet, but we should take an earliest action to rectify them. We should recognise Tibet as an independent State and in doing so there should be no fear in our mind that if we give recognition to Tibet, we would be termed as agents of capitalists or imperialists. I would like to point out that even Russia's attitude towards China has completely changed. She has now declared that China is following an expansionists policy. While commenting on the explosion of Atom bomb by China, the Russian spokesman has said "The feudal rulers of China are now on a expansionist spree." So we should have no apprehension in our mind that if we recognise Tibet, it will be alleged that we are agents of capitalists or imperialists. Moreover it is no secret that the relations between China and Russia have deteriorated to a very large extent. China had committed more border violations or Russia's territory than she had committed territory. There are vast differences between Russia and China on the questions of Outer Mangolia, Siberia and Kazakistan. So while reviewing our policy towards China and Tibet, we should consult Russia and then spell out a policy correcting our past mistakes.

ibet has been an independent country since time immemorial. She has more close cultural, historical, geographical, religious and linguistic connections with Indias' than China. So it is our duty and we should not leave any stone unturned for getting her independence. o far we have been adopting a wrong policy towards Dalai Lama. We have not allowed him to propagate his case from India. We must give him every help which is possible within the frame work of democracy to get his country freed from the domain of China. Secondly we should give employment to those Tibetan refugees, who had come here. But inspite of the fact that we should give them employment. We must side by side inculcate in them an ambition that ultimately they have to go back to their country and regain their independence.

The question of Tibet is not our internal question. It is an international problem and we must recognise it as an international problem. We must take up this question in the United Nation. Our attitude towards this question should not be of a sleeping partner's attitude, but we must support Tibet's cause actively.

Lastly I would like to make a reference have that some years back certain indications were given by Edgont Snow, who is considered to be the greatest friend of China. about the possibilty of a border settlement with China. The matter was raised here in

this House by Dr. Ram Manohar Lohia. But I think no serious attempt has been made so far by Government for exploring the avenues of a settlement. I am raising this point only for information and would like to know whether any action has been taken in this regard or not.

With these words I support the resolution.

श्री गणेश (अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हमें स्थिति की वास्तविकता को समझना चाहिये। यह सच है कि भारत ने तिब्बत पर चीन के अधिराज्य को मान्यता दी थी। हम जानते हैं कि चीन में क्या हो रहा है और हम यह भी जानते हैं कि चीन ने अपने उस वचन को भंग कर दिया है, जो उसने हमारे प्रधान मंत्री को दिया था कि वह तिब्बत की स्वायत्तता का आदर किया जायेगा। परन्तु आज विश्व की राजनीति में चीन का रवैया अद्भुत है। चीन आन्दोलन के समय विश्व के नेताओं ने चीन के बारे में जो अनुमान लगाया था, वह सब झूठा पड़ गया है। चीन का रवैया न केवल भारत के प्रति बल्कि संसार के अन्य देशों के प्रति भी जिस में रूस भी शामिल है, जिसने चीन के आन्दोलन के समय उसकी बहुत सहायता की थी और जिसकी सहायता के बिना चीनी आन्दोलन को सफलता नहीं मिल सकती थी, युद्धपूर्ण एंव शत्रुतापूर्ण है। इस सभा की यह प्रथा हो गई है कि जब कभी कोई मामला उठाया जाता है चाहे वह तिब्बत के बारे में हो अथवा पश्चिम एशिया के बारे में, समूची विदेश नीति की आलोचना की जाती है। जब भारत सरकार को यह ज्ञात हुआ था कि तिब्बत के लोगों को माननीय अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, तो माननीय अधिकार के अन्तर्गत उसने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया था। यह सिद्ध हो चुका है तथा देश का बहुमत इस तथ्य से सहमत है कि हमारी विदेश नीति सफल रही है।

मध्यवर्ती राज्य स्थापित करने की बात कही गयी है। वर्ष 1967 के संसार में मध्यवर्ती राज्य के बारे में बात करना ऐसा है जैसा सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के बारे में बात करना। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि भूतकाल में मध्यवर्ती राज्यों के कारण लड़ाइयां हुई है, तो भी वे तिब्बत को मध्यवर्ती राज्य बनाने की बात कह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश का बहुत बड़ा क्षेत्र चीन के अधिकार में है, तो भी चीन के अधिकार से उस क्षेत्र को मुक्त कराना बहुत कठिन कार्य है। यदि हम दलाई लामा को मान्यता देते हैं और भारत में प्रवासी सरकार बनाने की उसे इजाजत देते हैं और यदि हम चीन के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाते हैं तथा दलाई लामा की सहायता करते हैं तो इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक देश को हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना हमारे देश के लिये तबाही मोल लेना होगा। हम जानते हैं कि चीन विस्तारवादी नीति अपनाये हुए हैं और वह न केवल हमारे देश के साथ बल्कि रूस के साथ भी यही नीति अपनाये हुए है। हम यह भी जानते हैं कि आज चीन विश्व राजनीति में अकेला पड़ गया है। इस समय हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना हमें अपने लिये तबाही मोल लेना है।

चीन के साथ हमारा वर्तमान झगड़ा चाहे जो हो परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अन्ततः चीन एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है और हमें आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अपनी स्वतंत्रता का त्याग किये बिना, अपनी प्रभुसत्ता का त्याग किये बिना तथा अपने प्रजातंत्र का त्याग किये बिना, चीन के साथ कोई समझौता करना होगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध एक हैं और

हम दोनों पड़ोसी देश हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव में उल्लिखित इस बात को स्वीकार करना कि दलाई लामा को भारत में प्रवासी सरकार बनाने की अनुमति दी जाये, देश के हित में नहीं है। इस देश ने सभी सम्भव तरीकों से तिब्बती शरणार्थियों की सहायता की है। हमने दलाई लामा को आश्रय दिया है। तिब्बत में माननीय अधिकारों के हनन का मामला राष्ट्र संघ में उठाया है। सरकार अब तक जो नीति अपनाती रही है उसके सिवाय और कोई नीति नहीं है जो देश के हित में हो।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता सदस्य तथा अन्य सदस्यों ने इसके समर्थन में विचित्र तर्क पेश किये हैं। उनका कहना है कि चूंकि चीन भारत के साथ दुर्व्यवहार करता है इसलिये हमें भी उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिये, चूंकि चीन दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है इसलिये हमें भी उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये तथा चूंकि चीन का रवैया युद्धपूर्ण है इसलिये हमारा रवैया भी युद्धपूर्ण होना चाहिये। मैं इस बात को बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सर्वविदित है कि चीन के नेता एक ऐसी नीति का पालन कर रहे हैं जो विश्व की शांति, लोगों की मैत्री विशेषकर एशिया की जनता अफ्रीका की जनता और चीन की जनता के हितों के लिये हानिकारक है।

परन्तु यह नहीं सोचना चाहिये कि ऐसी नीति को बदला नहीं जा सकता और यह शाशवत है। हम इस सिद्धान्त से सहमत नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति का सावधानी से अनुसरण करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि तिब्बत के बारे में हम जिस नीति का पालन कर रहे हैं, वह बहुत हद तक सही है और हमें उसको जारी रखना चाहिये। हमारी नीति में एक सिद्धान्त है कि हमें दूसरों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूँ यह बहुत अच्छा सिद्धान्त है। यदि एक देश दूसरे देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करता है तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। चूंकि चीन गलत बात कर रहा है, इसीलिये हमें गलत बात नहीं करनी चाहिये। ब्रिटेन ने शताब्दियों तक सारे एशिया में कपटपूर्ण कार्य करता रहा। हमें उन बातों को भूल कर ब्रिटेन द्वारा दी गई सूचना पर निर्भर नहीं करना चाहिये। चीन द्वारा उत्तेजित किये जाने के बावजूद रूस वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा चीन रूस के साथ करता है (**व्यवधान**)।

तीसरे यह विचित्र बात नहीं है कि भारत में जो लोग दलाई लामा का समर्थन करना चाहते हैं और उन्हें आश्रय देना चाहते हैं वे वही लोग हैं जो देश में प्रतिक्रियावादी एवं सामन्तशाही व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं (**व्यवधान**)। दलाई लामा की सहायता के लिये जनसंघ पार्टी तथा स्वतंत्र पार्टी आदि की दौड़ समझ में आ सकती है परन्तु इस देश को इन प्रतिक्रियावादी संस्थाओं की सहायता नहीं करनी चाहिये।

इस प्रकार इन तीन पहलुओं से हमें अपनी नीति में, जो पहले ही कसौटी पर खरी उतर चुकी है, परिवर्तन नहीं करना चाहिये। मैं जानता हूं कि दबाव के कारण सरकार अपनी नीति से विचलित हुई है और यह बात मानव अधिकारों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से स्पष्ट है। दुर्भाग्य से हाल ही में वैदेशिक-कार्य मंत्री ने इस प्रकार के कुछ वक्तव्य दिये हैं कि भारत सरकार जिस नीति का अब तक अनुसरण करती रही, उस पर फिर से विचार करने के लिये तैयार हैं। परन्तु इस प्रकार से नीति में परिवर्तन करना अधिक कष्टप्रद होगा।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : वैदेशिक मामलों के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना इसलिये आवश्यक हैं, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में परिवर्तन होता रहता है । दलाई लामा संसार में किसी अन्य धार्मिक अधिकारी के समान केवल एक धार्मिक अधिकारी ही नहीं है, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व में एशिया के एक बड़े देश के एक स्वतंत्र राज्य-क्षेत्रीय प्राधिकार की पूरी सक्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनयिक दृष्टि से लगभग सारा संसार तिब्बत के प्रति सहानुभूति रखता है ।

मैं इस विचार से सहमत हूँ कि अन्ततोगत्वा भारत और चीन को आपस में मित्र बन कर रहना है । ये विशाल देश हैं और इनको एक दूसरे के निकट आना है । परन्तु व्यावहारिक कूटनीति के विचार से भारत को यह घोषित करने में क्या कठिनाई है कि तिब्बत का मामला उपनिवेश की समाप्ति के लिये चीन के समर्थन की कसौटी है ? हमें पन्द्रहवीं महासभा के संकल्प सं० 1514 के अधीन उनसे पूछना चाहिये कि उनका क्या विचार है ।

चीन द्वारा तिब्बत पर वास्तविक रूप में कब्जे के बावजूद और दलाई लामा और उनकी सरकार के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों में निन्दा करने के बावजूद तथ्य यह है कि वे काफी लम्बे समय तक दलाई लामा का सम्मान करते रहे हैं । चीनी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि तिब्बत के विशाल जनसमूह पर दलाई लामा का काफी प्रभाव है । इसलिये हमें तिब्बत समस्या के राजनीतिक पक्षों पर विचार करना चाहिये । आरम्भ में कुछ संघर्ष हो सकता है परन्तु यह शान्तिपूर्ण संघर्ष होगा । मेरे विचार से चीन के लिये तिब्बत को अपने कब्जे में रखना राजनीतिक दृष्टि से इतना लाभकारी नहीं है परन्तु सैनिक दृष्टि से उसे इसका बहुत लाभ है । प्रक्षेपणास्त्रों को छिपाने के लिये तिब्बत में बड़ी-बड़ी गुफायें हैं । तिब्बत में वह प्राकृतिक रूप में ही उपलब्ध हैं जिसके लिये अमरीका और रूस को काफी खर्च करना पड़ता है ।

इसलिये वैदेशिक-कार्य मंत्री की समस्या यह है कि तिब्बत को एपाकी योजना की तरह अणु-रहित क्षेत्र बनाया जाये । यदि इस क्षेत्र में प्रक्षेपणास्त्र नहीं होंगे तो भारत अधिक सुरक्षित महसूस करेगा । परन्तु उसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण अपेक्षित होगा । इसलिये यदि दलाई लामा की सरकार को प्रवासी सरकार के रूप में मान्यता दी जाये तो हमारे मित्रों को किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिये । हम ऐसी बातें करते रहे हैं परन्तु हमें अपने देश के हित में तिब्बत को एक राजनीतिक मामला बनाना चाहिये जिससे चीन के साथ बातचीत अधिक हो और लड़ाई कम हो ।

श्री नायनार (पालघाट) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । जो लोग दलाई लामा को तिब्बत की प्रवासी सरकार के अध्यक्ष के रूप में मान्यता देना चाहते हैं वे वस्तुतः तिब्बत को पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आपका भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 जुलाई 1967 । 12 आषाढ़ 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha than adjourned till Eleven of the clock on Monday, July 3, 1967/ Asadha 12, 1889 (Saka).